संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन की गाड़ी है। -डॉ. बीआर आंबेडकर

जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है। दोनों जगहों की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नई राजनीतिक परिस्थितियों में पहली बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है।

ऐतिहासिक अवसर

चुनाव आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही जहां इन दोनों जगहों में चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं इस बात की भी पुष्टि होती है कि हाल के दिनों में खासकर जम्मू में उपद्रव की तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिया है, जो स्वागत योग्य है। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू-कश्मीर के राज्य से केंद्रशासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है, जो पूरे दस साल बाद हो रहा है। जाहिर है कि यह ऐतिहासिक अवसर है। गौरतलब है कि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में 87 विधानसभा सीटों के लिए हुआ था। परिसीमन के बाद इस बार 90 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें से 43 जम्मू क्षेत्र में और 47 कश्मीर क्षेत्र में हैं। पिछले दो दशकों में जम्मू-कश्मीर में सबसे कम मात्र तीन चरणों में-18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्तूबर को मतदान संपन्न होंगे। आम तौर पर जिस प्रदेश में समस्याएं ज्यादा होती हैं, वहां उतने अधिक चरणों में चुनाव करवाए जाते हैं। मगर हाल के आतंकवादी हमलों और सामान्य से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बावजूद यदि मात्र तीन चरणों में ही चुनाव कराने की घोषणा हुई है, तो साफ है कि सरकार यहां जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती है। चुनाव आयोग के इस फैसले के पीछे लोकसभा चुनाव का सुखद अनुभव भी हो सकता है, जब मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लगी थीं और कहीं भी पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। प्रदेश के लोगों ने चुनाव बहिष्कार और हिंसा को नकार कर बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था, जो लोकतंत्र के प्रति वहां की आम जनता के भरोसे का परिचायक है। हरियाणा में एक ही चरण में एक अक्तूबर को मतदान होंगे, लेकिन हरियाणा और जम्मू-कश्मीर, दोनों के चुनाव नतीजे चार अक्तूबर को घोषित होंगे। हरियाणा में जहां 10 हजार से ज्यादा मतदाता सौ वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर में पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3.71 लाख है और 20 लाख से ज्यादा मतदाता युवा हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब देखना होगा कि राजनीतिक दल किस प्रकार मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं। हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था की वैसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में हाल के दिनों में बढ़ी आतंकी मुठभेड़ों के मद्देनजर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने की चुनौती होगी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इन ऐतिहासिक चुनावों के जरिये जम्मू-कश्मीर में नए युग की शुरुआत होने जा रही है।

राज्य मनमानी नहीं कर सकते

भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जो दोनों में से किसी को भी संप्रभु होने से रोकता है। दोनों की विधायी क्षमता संतुलित रखी गई है, ताकि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन को सर्व-समावेशी और सर्वव्यापी बनाया जा सके।

सीवीपी श्रीवास्तव
अध्यक्ष, सेंटर फॉर अप्लायड रिसर्च इन गवर्नेंस, दिल्ली

भारत के राजनीतिक स्वरूप की विशिष्टता इसकी एकात्मक संघीय प्रकृति है, जिसे आचार्य दुर्गा दास बसु ने 'चरित्र में परिसंघीय और आत्मा में एकात्मक' के रूप में वर्णित किया है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ, 1977 मामले में न्रैनविले ऑस्टिन का हवाला दिया है, जिन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान शायद पहला ऐसा संविधान है, जिसने शुरू से ही एएच बर्च द्वारा संकल्पित 'सहकारी संघवाद' की संकल्पना को अपनाया है। यानी संघ और राज्य तथा राज्य और राज्य परस्पर सहयोग और समन्वय से कार्य करेंगे, ताकि संविधान द्वारा निर्धारित कल्याण के साझा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। न्यायालय ने माना है कि संविधान ने एक ऐसी केंद्र सरकार की संकल्पना की है, जो इस अर्थ में 'उपयचर' है कि वह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार संघीय या एकात्मक तल पर कार्य कर सकती है।

एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 मामले में शीर्ष न्यायालय ने भारत के संघवाद को 'व्यावहारिक संघवाद' कहा है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण तो हुआ है, पर इसका झुकाव संघ की ओर है। हरियाणा बनाम पंजाब राज्य, 2004 मामले में 'अर्ध-संघीय' शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1974 मामले में न्यायालय ने इसे 'परिसंघीय से अधिक एकात्मक' कहा था। शीर्ष न्यायालय के इन विचारों से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनीतिक संरचना को विषम परिसंघ कहा जाना सही है, जहां विधायी शक्तियों का वितरण दो अलग-अलग स्तरों पर काम करने वाली स्वायत्त सरकारों की जरूरतों के अनुसार किया गया है, हालांकि दोनों में से किसी को भी कमजोर या मजबूत नहीं बनाया गया है। इसे ही हम शक्तियों का न्यायसंगत वितरण कहते हैं।

हाल ही में, भारत के प्रधान न्यायाधीश ने मिनरल एरिया डेवलपमेंट बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2024 मामले में

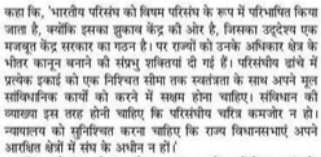

कहा कि, 'भारतीय परिसंघ को विषम परिसंघ के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि इसका झुकाव केंद्र की ओर है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत केंद्र सरकार का गठन है। पर राज्यों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने की संप्रभु शक्तियां दी गई हैं। परिसंघीय ढांचे में प्रत्येक इकाई को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता के साथ अपने मूल सांविधानिक कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। संविधान की व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि परिसंघीय चरित्र कमजोर न हो। न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य विधानसभाएं अपने आरक्षित क्षेत्रों में संघ के अधीन न हों।'

संविधान के अनुच्छेद एक के तहत, भारत को राज्यों के एक संघ के रूप में स्थापित किया गया है, जहां राज्यों के निर्माण का अधिकार संघ का है और राज्य भारत के आवश्यक भाग हैं। अनुच्छेद 245 कानून बनाने के लिए भारत के राज्यक्षेत्र का वर्गीकरण करता है और संघ व राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रयोज्यता की सीमा का प्रावधान करता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने के लिए विषयों का बंटवारा करता है, फिर भी संसद को 'अवशिष्ट शक्तियों' के तहत उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है और जो नए उभरने वाले विषय हैं। यही परिसंघीय ढांचे को विषम परिसंघ बनाता है।

इसी प्रकार, वित्तीय शक्तियां भी संघ में निहित हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 109 का खंड (1) उल्लेखनीय है, जो यह प्रावधान करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। विषम परिसंघ के ये प्रावधान भारत को एक कार्यात्मक परिसंघ भी बनाते हैं, जिसमें वित्तीय और नए उभरने वाले विषयों की शक्तियां राज्यों में निहित नहीं होती हैं।

सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, हालांकि, संघ सूची के कुछ विषयों को राज्य के विषयों पर वरीयता दी गई है, फिर भी यह परिसंघ को कमजोर नहीं बनाता है। जैसे, राज्य सूची की प्रविष्टि 17 में 'पानी' यानी जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।

2024 के मिनरल एरिया डेवलपमेंट मामले में दिए गए फैसले में उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से कर लगाने संबंधी राज्यों की विधायी क्षमता की जांच की। मुख्य प्रश्न यह जांचना था कि क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और क्या संसदीय कानून, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के बाद राज्यों को खनिज अधिकारों पर रॉयल्टी/कर लगाने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानसभाओं में निहित है। संसद के पास सूची-1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, यह एक सामान्य प्रविष्टि है। चूंकि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति सूची-2 की प्रविष्टि 50 में उल्लिखित है, इसलिए संसद उस विषय वस्तु के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है। राज्यों की विधायी क्षमता पर केवल इसलिए सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि भारतीय परिसंघ विषम है।

संविधान निर्माताओं ने संघ और राज्यों के बीच किसी भी संभावित टकराव को रोकने के लिए सातवीं अनुसूची में विषयों को बहुत स्पष्टता से सूचीबद्ध किया है। इसके अलावा, समन्वय का सिद्धांत समवर्ती सूची में अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें संघ और राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं। भारत के संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, जो दोनों में से किसी को भी संप्रभु होने से रोकता है। इस अर्थ में, संघ और राज्यों, दोनों की विधायी क्षमता इतनी संतुलित है कि परिसंघीय विषमता कानून बनाने के कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है, ताकि संसाधनों को न्यायसंगत ढंग से वितरित करके व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का साझा लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए लोकतांत्रिक शासन को सर्व-समावेशी और सर्वव्यापी बनाया जा सके।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

फ्रांसिस्क मिरालेस

एक साथ कई काम करने से असल काम छूट जाता है

आज की तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है-हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त हम एक तरफ यू-ट्यूब पर वीडियो भी देखते रहते हैं। उतने में चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई सूचना देता है और हम फिर उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में तीस मिनट कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे, वह तो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है।

घर में भी लोग टीवी देखते-देखते खाना खाते हैं और आखिरी निवाले तक उन्हें पता नहीं चलता है कि भोजन अच्छा बना है या नहीं। लोगों को यह गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं, वे भी ज्यादा कार्यदक्ष नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्यक्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारियां अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते हैं। इसके परिणामस्वरूप कोई एक काम ठीक से नहीं होता है। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं। साथ ही हमारी ऊर्जा और समय, दोनों व्यर्थ होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना प्रवाह पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी होता है। पहला, काम के लिए अच्छा माहौल, दूसरी बात, हम जो कर रहे हैं, उसके बारे में आत्मविश्वास होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी ने वाकई बड़ी क्रांति की है। जब तक वह हमारे नियंत्रण में है, तब तक वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन जब हम उसके नियंत्रण में जाते हैं, तो वह तकलीफदेह बन जाती है। मान लें, आपको शोध कार्य करना है। आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर पर गूगल खोलकर जानकारी लेने बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है, तो आप अपने विषय के बारे में लिखना छोड़कर और अन्य चीजों की जानकारी में खो जाते हैं। इस मामले में गूगल और इंटरनेट आप पर हावी हो जाते हैं और आपको अपने प्रवाह से दूर ले जाते हैं। आज विज्ञान ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और तीसरे काम में लगाते रहते हैं, तो हमारा समय व्यर्थ जाता है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए हमें अपनी जीवन-शैली में कुछ बदलाव लाने होंगे।

विज्ञान ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान एक से अधिक कामों में लगाते हैं, हमारा समय व्यर्थ जाता है। एक साथ मेल, फेसबुक, यू-ट्यूब और चैटिंग में व्यस्तता से ध्यान भटकता है।

टेक्नोलॉजी का उपवास करें

सूत्र

हफ्ते में एक दिन, खासकर शनिवार या रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करें। जीवन तनावमुक्त रहेगा। आप इंटरनेट पर अगर 25 मिनट काम करते हैं, तो पांच मिनट आराम करें। आप कितना समय आराम करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तय करते हैं, उसका पालन करें।

दूसरा पहलू

काशी का एक गांव, जहां रहते हैं तीन से 19 वर्ष की उम्र के 300 फुटबाल खिलाड़ी। इनमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं।

पहाड़ी में बसा छोटा-सा ब्राजील

बनारस में एक छोटा-सा ब्राजील बसा है। गांव का नाम है पहाड़ी। और यहां रहने वाले 1500 परिवारों के 300 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। खूबसूरत बात यह है कि इनमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। बार-बार सिलवाए हुए जूते पहनकर हर शाम जब वे ग्राउंड के लिए निकलती हैं, तो रौनक किसी खेल गांव जैसी लगती है।

इस गांव के बच्चे 12 वर्ष पहले तक जुआ खेलते थे। इधर-उधर भटकते थे। तभी पास की कॉलोनी में रहने वाले फुटबॉल खिलाड़ी भैरव दत्त इन बच्चों के लिए 3-4 फुटबाल ले आए। मैदान के झाड़-झंखाड़ और गड्ढे ठीक करवाकर फुटबॉल खेलने लायक बना लिया। फिर गोल पोस्ट के नाम पर तरफ बांस के पोल लगाए और दूसरी तरफ कुर्सी रख दी। शुरुआत में सिर्फ सात-आठ बच्चे आते थे। उनके लिए कोच भैरव ने किस्तों में किट मंगवाई। यहां-वहां से जूतों के पैसे जुटाए। तीन नेशनल खेल चुकी सृष्टि कहती हैं कि उन्हें पहली किट भैरव सर ने ही दिलवाई थी। वह दूसरों को देखने मैदान पर जाती थी और सोचती थी कि खेल पाऊंगी या नहीं। फुटबॉल की इस पीढ़ी को तैयार करते हुए कोच भैरव को 40 साल हो चुके हैं। इस मैदान पर पांच साल की, जो बच्ची खेलने आती थी, अब वह 17 साल की है। पिछोराबड़ के भैरव सर वैसे तो बरेका में नौकरी करने काशी आए थे। अब उनके सिखाए बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। यही नहीं, अपने खेल के बूते खेल कोटे से नौकरी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई भी। एमफिल, बीएड और पीएचडी तक। किलाहल सात लड़कियां बीएचयू और दो गुवाहाटी से रिसर्च कर रही हैं। तीन प्रोफेसर बन गई हैं। सात पंजाब में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप की एक शर्त है। पढ़ाई के बदले इन सभी को खेल में पदक जीतने होते हैं। कुछ बेटियां ओडिशा व पश्चिम बंगाल के फुटबॉल क्लब का हिस्सा हैं।

75 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं। इनमें लखपति के परिवार के आठ बच्चे हैं। गांव के लोग इस परिवार को लखपति बुलाते हैं, लेकिन गांव में सबसे टूटा-फूटा घर इनका ही है। हां, उनके हिस्से इस गांव के सबसे ज्यादा मेडल जरूर हैं। पार्वती के परिवार में छह बहनें हैं। तीन बहनें फुटबॉलर हैं और दो नेशनल खेल चुकी हैं। जिस ग्राउंड पर इन बच्चों ने सबसे पहले खेलना शुरू किया, वहां अब इमारत बन गई है। जिस गांव में 300 खिलाड़ी हैं, वहां अब मैदान नहीं। खेलने के लिए अब डेढ़ किलोमीटर दूर बरेका जाना होता है।

उपमिता वाजपेयी

पहाड़ी गांव में 12 वर्ष पहले तक बच्चे जुआ खेलते थे, लेकिन फिलहाल के रहने वाले भैरव दत्त ने बच्चों को फुटबॉल थैकर नई दिशा प्रदान की है।

इस गांव की 75 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं। जिस ग्राउंड पर इन बच्चों ने खेलना शुरू किया, वहां अब इमारत बन गई है। जिस गांव में 300 खिलाड़ी हैं वहां अब मैदान नहीं। खेलने के लिए अब डेढ़ किमी दूर बरेका जाना होता है।

आंकड़े

अच्छी हवा

उयादातर शहरों में लोग अच्छी हवा के लिए तरस रहे हैं। वहीं, इस साल कुछ शहरों की वायु गुणवत्ता ने सुखद तस्वीर पेश की है।

आइजोल	9.9
गंगटोक	14.8
चामराजनगर	17.7
गढग	18
थिकमगलूरु	18.2

आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में हैं। | स्रोत : CPCB

ऋषिकुमार ने कहा 'आपके दान की ख्याति सुनी है, लेकिन आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई स्वर्णपात्र नहीं है, आपने हमें मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया।'

कुबेरलोक से स्वर्ण मुद्राएं लाए रघु

अंतर्यात्रा
संकलित

महाराज रघु बड़े ही पराक्रमी और धर्मात्मा थे। एक बार वह दरबार में बैठे थे कि उनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषिकुमार आए। महाराज ने ऋषिकुमार का स्वागत-सत्कार किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ऋषिकुमार लौटकर जाने लगे, तो महाराज ने पूछा, आप क्यों जा रहे हैं?

ऋषिकुमार ने कहा- राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है, आप अद्वितीय दानी हैं; मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था। यहां आकर मैंने देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई स्वर्णपात्र नहीं है और आपने हमें मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः अब मैं आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा-नहीं, ब्राह्मण! आप मुझे अपनी बात बताइए। मैं यथासाध्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। कौत्स ने कहा, 'राजन! मैंने अपने गुरु के यहां रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए चौदह लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए।' महाराज ने कहा, 'मैं कुबेरलोक से धन लाकर आपको दूंगा।' महाराज ने मुद्राएं ऋषिकुमार को लाकर दीं। लेकिन मुद्राएं नियत संख्या से बहुत अधिक थीं, तब उन्होंने राजा से कहा, मुझे तो केवल चौदह लाख ही चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा।'

अंत में कौत्स को जितनी जरूरत थी, वह उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहां चले गए। इसके बाद जो मुद्राएं बची थीं, वे ब्राह्मणों में दान कर दी गईं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 09 मार्च, 1958

दो पाकिस्तानी जासूसों को पांच-पांच वर्ष की कैद

दो पाक जासूसों को पांच-पांच वर्ष की कैद

जम्मू, 8 मार्च। यहां की एक अदालत ने दो पाकिस्तानियों को 5-5 वर्ष कैद की सजा का आदेश दिया। इस्तगासे के अनुसार इन पर अधिनियम यह था कि इन्होंने गुप्त विराम रेखा को पार कर काश्मीर के भारतीय प्रदेश में आने तथा उस प्रांत में

जम्मू की अदालत ने दो पाकिस्तानी जासूसों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा का आदेश दिया। इन्होंने गुप्त रेखा को पार कर कश्मीर में डाके डालने और पानी की पाइपलाइन में जहर मिलाने की चेष्टा की।

भारत से '71' में ही हो गई थी बड़ी चूक

भारत ने जब बांग्लादेश को आजाद करवाया, तो उसी वक्त उसके संविधान में अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान करवा देना चाहिए था।

शिवदान सिंह | मुद्दा

बांग्लादेश में हिंसा और विरोध प्रदर्शन के चलते प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आईं शेख हसीना ने पूरे घटनाक्रम पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और आरोप लगाया कि उनको सरकार को गिराने के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका ने बांग्लादेश के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण वह बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दे। लेकिन विचारणीय पहलू यह है कि भारत ने सन 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान से युद्ध किया और 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त करके बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की।

भारतीय सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और उनके कमांडर जनरल नियाजी को बंदी बना लिया था। इस युद्ध में 3,000 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 12,000 घायल हुए। इसके अलावा इस युद्ध में भारत की एक पंचवर्षीय योजना पर होने वाले धन के बराबर धन खर्च हुआ, जबकि उस समय देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। यह धन देश की विकास योजनाओं पर खर्च किया जाना था। परंतु मानवता की पुकार के कारण भारत सरकार ने यह धन बांग्लादेश के निर्माण पर खर्च किया। युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार और खासकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विश्वस्तर पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बगैर ही बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और युद्ध समाप्ति के 15 दिन बाद ही अपनी सेना को बांग्लादेश से वापस बुला लिया। यहां पर विचारणीय यह कि लंबे समय से पूरे पाकिस्तान में, जिसमें बांग्लादेश भी सम्मिलित है, हिंदू अल्पसंख्यकों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे थे, जिसके कारण वह तो वे पलायन कर रहे थे या फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो रहे थे। आजादी से पहले 1946 में बांग्लादेश स्थित नोहा खाली नाम के स्थान पर सांप्रदायिक दंगे में कई हिंदुओं की हत्याएं की गईं और महिलाओं से दुष्कर्म किए गए। महात्मा गांधी भी इन दंगों को नहीं रोक पाए थे।

1947 में पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू आबादी 18 फीसदी और पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में 25 फीसदी थी, लेकिन आज पाकिस्तान में हिंदू आबादी घटकर एक प्रतिशत और बांग्लादेश में केवल पांच फीसदी रह गई है। दोनों ही देशों से अब भी हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने और उसका निर्माण करने में अपने 3,000 सैनिकों की कुर्बानी और अपनी एक पंचवर्षीय योजना का पूरा धन खर्च करने के बाद भी भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाई। न्याय और मानवता के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में उसके निर्माण के समय ऐसे प्रावधान किए जा सकते थे, जिससे वहां की कानून व्यवस्था हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उस समय बांग्लादेश की सरकार भारत की हर शर्त मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि भारत ने ही उसे पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, जहां पर किसी देश ने दूसरे देश को बांग्लादेश की तरह स्वतंत्रता दिलाई हो।

भारत ने जिस देश को लंबी गुलामी से मुक्त कराया, उसके साथ ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके अनुसार, उसके कानून में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान हो। इसके अलावा भारत की ओर से किए गए अनके आर्थिक अनुबंधों की वजह से बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की एक उभरती आर्थिक शक्ति बन रहा है। सीमाओं पर भी भारत ने उसे सुरक्षा प्रदान की है। पूरी बंगाल की खाड़ी में भारत की नौसेना अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रही है। परंतु आज उसी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिससे मानवता शर्मसार हो रही है।

इस समय भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आती है, उसे साफ शब्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रबंध करने के लिए कहे, अन्यथा भारत अपने आर्थिक संबंध बांग्लादेश से समाप्त कर देगा। उसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाकर उसको भी पाकिस्तान की तरह एक आतंकी देश घोषित करवा सकता है। इस्लाम एक छोट-सा देश है, लेकिन पूरे विश्व के वहाँदयों को वह संरक्षण उपलब्ध करा रहा है। क्या भारत भी इस प्रकार हिंदुओं की रक्षा कर सकता है? परंतु हमारे देश में धर्म निरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं की बात ही नहीं की जाती। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक माना जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की घटनाओं को देखते हुए अब समय आ गया है कि भारत सरकार विश्व पटल पर खुलकर हिंदुओं की रक्षा की बात रखे।

सम्पादकीय

बैंकों के ऋण और जमा वृद्धि के बीच कैसे कम होगा अंतर?

हाल के दिनों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास दोनों ने बैंकिंग क्षेत्र में ऋण और जमा वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर को लेकर चिंता जताई। दास इस विसंगति के बारे में सार्वजनिक रूप से पहले से ही चर्चा करते रहे हैं। उदाहरण के लिए गत सप्ताह मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय की घोषणा करते समय उन्होंने कहा कि वैकल्पिक निवेश केंद्र खुदरा निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं। ऐसे में फंडिंग के मोर्चे पर बैंकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप बैंक अल्पावधि के गैर खुदरा फंड तथा अन्य उपायों पर निर्भर हैं ताकि अपने ऋण की बढ़ती मांग की पूर्ति कर सकें। इससे बैंकिंग तंत्र ढांचागत नकदी संकट के जोखिम का शिकार हो सकता है। जमा वृद्धि कुछ समय से ऋण वृद्धि से पीछे है जिसके संभावित परिणाम हमें झेलने पड़ सकते हैं। जैसा कि इस समाचार पत्र ने बुधवार को प्रकाशित किया, कुछ बैंक जमा आकर्षित करने के लिए नई किस्म की रणनीति अपना रहे हैं। यह देखना होगा कि ऐसे उपाय अंतर को पाटने में कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए गत वित्त वर्ष में जब ऋण 20 फीसदी की दर से बढ़ रहा था, तब जमा वृद्धि केवल 14 फीसदी थी। इस अंतर को रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया। यह रुझान ऋण-जमा अनुपात में भी देखने को मिलता है जो सितंबर 2021 के बाद बढ़ा है। दिसंबर 2023 में यह 78.8 फीसदी के साथ उच्चतम स्तर पर पहुंचा और मार्च 2024 तक दोबारा घटकर 76.8 फीसदी रह गया। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह अनुपात खासतौर पर अधिक है। हालांकि गत दो-चार साल में कुछ विचलन नजर आया है लेकिन वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर दोनों ने इस मसले को रेखांकित करके तथा बैंकों को उपयुक्त कदम उठाने को कहकर सही किया है। यह सही है कि बैंकिंग व्यवस्था को कोई तात्कालिक खतरा नहीं है लेकिन विचलन के कारणों तथा इसके बड़ी समस्या बन जाने के पहले उठाए जाने वाले उपायों को लेकर बहस एक आवश्यक है। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही ऋण में इजाफा हुआ। यह बढ़ोतरी नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से तेज है और इस बात को समझा जा सकता है। बहरहाल जमा वृद्धि में कमी की कई वजह हो सकती हैं।

संभव है कि आम परिवारों ने अन्य उपायों का रुख कर लिया हो क्योंकि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को मदद पहुंचाने के लिए वास्तविक नीतिगत दर को कुछ समय से नकारात्मक कर रखा है। हाल के वर्षों में देश के शेयर बाजारों का अच्छा प्रदर्शन भी इसकी वजह हो सकता है। एक अन्य वजह हो सकती है परिवारों की वित्तीय बचत में गिरावट। ताजा उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि 2022-23 में यह जीडीपी के 5.3 फीसदी के साथ कई दशकों के निचले स्तर पर आ गई है। घरों की वित्तीय बचत में सुधार जहां अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, वहीं बैंक अतिरिक्त बचत जुटाने के लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। मार्च के अंत में अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.6 फीसदी था।

विकसित भारत को गढ़ने के संकल्पों का उद्बोधन

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में खास एवं ऐतिहासिक होने की अनुगूंजें इस उद्बोधन में साफ सुनाई दी, जैसाकि उनके पूर्व के दो कार्यकाल इस लिहाज खास रहे हैं कि उनकी पार्टी के जिन लक्ष्यों को राजनीति की अन्य धाराएं लगभग नामुमकिन मानती थीं, उन्हें देश के अजेंडा का हिस्सा बनाते हुए हासिल कर लिया गया। चाहे वह अयोध्या में राममंदिर बनाने की बात हो या अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष दर्जा खत्म करने की। तीसरे कार्यकाल में ऐसा ही एक और लक्ष्य है कॉमन सिविल कोड जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना बाकी है।

ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लालकिले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस का अब तक का सबसे लम्बा 98 मिनट का 11वां राष्ट्रीय उद्बोधन एक विशाल एवं विराट इतिहास को समेटे हुए नये भारत के नये संकल्पों की बानगी है। जो आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने के लिये लोगों को ऊंचे सपने देखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान की वैश्विक एवं राजनैतिक चुनौतियों को भविष्य की अपनी दृष्टि पर हावी नहीं होने दिया। यह उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा रेखांकित करते हुए उसे विश्व गुरु बनाने एवं दुनिया की आर्थिक महाताकत बनाने का आह्वान है। यह शांति का उजाला, समृद्धि का राजपथ, उजाले का भरोसा एवं महाशक्ति बनने का संकल्प है। लालकिले से जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो वह भारत के महान लोकतंत्र की उस आत्मा को साकार करता है जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भीतर बसती है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन को वास्तविकता की रोशनी में नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत के रूप में देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को जरूरी बताने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफार्म्स तक, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से लेकर गवर्नेंस मॉडल, रोजगार, व्यापार, रक्षा, चिकित्सा समेत कई विषयों की चर्चा की। उन्होंने न्यायिक सुधारों पर आगे बढ़ने का भी संकेत दिया। इसके साथ ही वह विपक्ष को निशाना बनाने से नहीं चूके और सरकार का एजेंडा उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। निश्चित ही अब तक हुए लालकिले की प्राचीर के उद्बोधनों में सर्वाधिक प्रेरक, संकल्पमय एवं विकसित भारत की इबारत लिखने वाला यह उद्बोधन रहा। अंधेरों को चीर कर उजाला की ओर बढ़ते भारत की महान यात्रा के लिये सबके जागने, संकल्पित होने एवं आजादी के अमृतकाल काल को अमृतमय बनाने के लिये दृढ़ मनोबली महानायक का आह्वान है।

मोदी ने धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के रूप में इसका जिक्र करके यह संकेत दिया है कि इसे देशवासियों के लिए स्वीकार्य बनाना और लागू करना उनकी सरकार की प्राथमिकता में काफी ऊपर है। उनके शब्दों में मौजूदा सिविल कोड एक तरह से साम्प्रदायिक नागरिक संहिता है। देश को ऐसे सिविल कोड की जरूरत है, जिससे धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति मिले। जब देश में अधिकतर मामलों में नागरिकों पर एक समान कानून लागू होते हैं तो फिर अलग-अलग धर्मों के अपने अलग-अलग लॉ भारत के संविधान पर सवालिया निशान लगाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी देश में बार-बार होने वाले चुनावों को विकास की राह में बाधा मानते हैं और यह कोशिश करते रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने लगें। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद उनकी पार्टी और सरकार का यह अजेंडा आगे बढ़ना मुश्किल भले ही माना जा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इसका भी जिक्र करते हुए यह संकेत दिया कि इस दिशा में उनकी सरकार के प्रयास जारी रहेंगे। इन सबके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की खास उपलब्धियों और उसके सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र करना नहीं भूले। अनेक विशेषताओं एवं विलक्षणताओं वाले इस बार के उद्बोधन एवं स्वतंत्रता दिवस समारोह की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा गया, उससे यही स्पष्ट हुआ कि वह अपने इस एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के बाद भी वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं हैं। इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अतिरिक्त और बाहरी चुनौतियों की चर्चा करते समय बांग्लादेश के हालात का भी जिक्र किया और वहां के हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने एक ओर जहां जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति पर प्रहार किया, वहीं दूसरी ओर कोलकाता की दिल दहलाने वाली घटना को ध्यान में रखते हुए नारी सुरक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने यह कहकर देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन लाने की भी पहल की कि आने वाले समय में एक लाख ऐसे युवाओं को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों में सक्रिय होना चाहिए, जिनके परिवार के लोग पहले कभी राजनीति में न रहे हों। निश्चित ही भारतीय राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति एवं नए विचारों और नई ऊर्जा से ओतप्रोत युवा नेताओं की आवश्यकता है।

यह ऐतिहासिक उद्बोधन कोरा राजनीतिक उद्बोधन न होकर राष्ट्रीयता को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने का सशक्त आह्वान है जो इस बात विश्लेषण करता है कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए। अंतरिक्ष हो या समंदर, धरती हो या आकाश, देश हो या दुनिया आज हर जगह भारत का परचम फहरा रहा है, भारत ने जितनी प्रगति की है उसे देखकर हर देशवासी को भारतीय होने का गर्व हो रहा है तो इसका श्रेय मोदी को दिया जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं है, इसकी चर्चा करना राजनीतिक नहीं, भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समृद्धि का बखान है। हर भारतवासी मोदी के उद्बोधन से इसलिये भी प्रेरित एवं प्रभावित हुए है कि 'मिशन मोड' पर 'ईज ऑफ लिविंग' को पूरा करने के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए उसे आगे बढ़ा रहे है। उन्होंने व्यवस्थित मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने भारत में जीवन को आसान बनाने की अपेक्षा की, ताकि अमीरों एवं युवा प्रतिभाओं के पलायन को रोका जा सके। मोदी ने देश की जनता में जोश एवं संकल्प जगाते हुए ऐसा ही कुछ कहा जो जीवन की अपेक्षा को न केवल उद्घाटित करता है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को परत-दर-परत खोलकर रख देते हैं। 'विकसित भारत' की थीम के साथ इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा को रेखांकित करते हुए कह रहा है कि देश किन्हीं समस्याओं पर थमे नहीं, रूके नहीं, क्योंकि समाधान तलाशते हुए आगे बढ़ना ही जीवंत एवं विकसित देश की पहचान होती है। इसके लिये जो अतीत के उत्तराधिकारी और भविष्य के उत्तरदायी है, उनको दृढ़ मनोबल और नेतृत्व का परिचय देना होगा, पद, पार्टी, पक्ष, प्रतिष्ठा एवं पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर। यही भावना सबल सक्षम और समरस राष्ट्र बनाएगी और विश्व में भारत का मान बढ़ाएगी, इससे ही भारत विश्वगुरु बनेगा। हम भारत के लोग विश्व मंगल की कामना की पूर्ति तभी अच्छे से कर सकते हैं जब पहले राष्ट्र मंगल की भावना से ओतप्रोत हों। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने पिछले 78 वर्षों में जो प्रगति की उडान अपनी विविधता को संजाये हुए भरी है उससे पूरी दुनिया हैरत में है। बढ़े-बढ़े देश अब भारत के लोगों के विकास, ज्ञान और उनकी मेहनत के दीवाने हैं। दुनिया के हर कोने में भारतीय अपना झंडा गाड़ रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ने का आह्वान भी किया क्योंकि ये गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। उन्होंने नवाचार के इच्छुक उद्यमियों को विशेष रूप से संबोधित किया गया। भारत का निर्यात बढ़ना जरूरी है और इसके लिए ऐसे उत्पाद बनाने की जरूरत है, जिनकी विश्व स्तर पर मांग हो। देश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के मकसद से अगले पांच वर्षों में 75000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा महत्वपूर्ण है। ऐसी ही घोषणाओं से भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा।

आज का राशिफल

हमारे आपकी ज्योतिषियों की टीम के अनुभवों अथवा कई विधि तरकों को पूरा करेंगे। तथा आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपको विशेष कुछ करेंगे और पूर्णतः तथा, अपनी किस बातों से लाभकर लाभा पहिये। हम ने ऐसी सभी बातों में और संदेश हमों को कुछ करने वाला लाभकारक उन्हें जो लाभकर करेंगे, बंधित कारकीदि लक्षों में भी, जहां यह लाभकारकता हमें लाभ और कठिनाई में लाभ प्रदान करेंगा

मेष
दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

वृष
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

मिथुन
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

कर्क
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। स्नेहीजनों के साथ भनिष्ठता बढ़ेगी।

सिंह
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

कन्या
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। दोपहर के बाद आप आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

तुला
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

वृश्चिक
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से सोचिए-सुजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

धनु
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

मकर
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी।

कुंभ
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा।

मीन
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

शख्सियत

हमारे कर्म हमें ही पता है कि हम कर क्या रहे हैं पर हमें समाज के दिखावे के लिए धर्म का प्रमाण पत्र चाहिए होता है जो ये पूव कर सके कि हम धार्मिक हैं जबकि ये कर्म भूमि है यहां कर्म ही धर्म दिलाता है.....

डॉ.योगेन्द्र शर्मा
(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)

नमस्कार साथियों हमारे आज की शख्सियत है अलवर के होनहार सपूत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ योगेन्द्र शर्मा। जो इस समय अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ के वास कुपाल नगर में 3 दिसंबर सन् 1975 को जन्मे डॉक्टर योगेंद्र शर्मा शुरू से ही जमीनी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। पिताजी भी सरकारी स्कूल में टीचर रहे ऐसे में नैतिक संस्कार और शिक्षा इन्हें परवरिश के रूप में मिली है। कक्षा 6 से 10 तक बाल विहार स्कूल में और 11वीं 12वीं हैप्पी स्कूल से करने के बाद एमबीबीएस रविंद्र नाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर से सन 1994 में कंपलीट की। सन 1999 प्रथम प्रयास में अप्रैल 2003 तक ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू ब्रह्माकुमारी इंटरनेशनल हैडक्वार्टर्स में काम किया। शादी के बाद में 2003 से 2009 तक सरदारशहर तहसील चूरू में मेडिकल ऑफिसर पद पर कार्यरत रहे। 2009 से 2011 तक सीएचसी तिजारा में इंचार्ज के रूप में कार्यभार संभाला। 2011 से 2014 में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में चेस्ट मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम प्रयास में पूर्ण कर अलवर का गौरव बढ़ाया। सन 2014 जुलाई से टीबी क्लिनिक अलवर हॉस्पिटल में ज्वाइन किया जहां मरीजों को अंतिम छोर तक उनके स्वास्थ्य लाभ दिलाकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने का जिम्मा उठाया। सन 2019 में जिला टीबी ऑफिसर पद पर नियुक्त हुए और लगातार कार्य कर मरीज व उनके परिजनों को लाभ दिलाया। यही नहीं सरकारी की टीबी उनमूलन कार्यक्रम के तहत बडे स्तर पर लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक कार्यक्रम चलवाया। 16 मार्च 2024 को सरकार ने इन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर सुशोभित किया, जहां आज पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर विकास और मरीज व उनके परिजनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ.योगेन्द्र शर्मा सच में एक सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी हैं। सीएमएचओ पर पर रह कर टीबी मरीजों को ओफिस में देखना उनकी शख्सियत दर्शा रही है क्योंकि डाक्टर बनाना शायद आसन है लेकिन इंसान बनना बेहद मुश्किल लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि डॉ.योगेन्द्र एक बेहतरीन चिकित्सक के साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

जय हिन्द

आज का इतिहास

17 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- 1659-दारा शिकोह को औरंगजेब द्वारा फाँसी दी गयी।
- 1682-विलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कॉलोनी की स्थापना की।
- 1780-जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया।
- 1806-न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र 'डेली एडवर्टाइजर' आखिरी बार प्रकाशित किया गया।
- 1928-द इंडियंडेंस ऑफ़ इंडिया लीग की भारत में स्थापना।
- 1947-भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया।
- 1951-फिलीपींस और अमेरिका ने एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये।
- 1991-अजरबैजान ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।
- 1999-पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह सम्पन्न।
- 1999-पूर्वी तिमोर के निवासियों ने इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया।
- 2002-ताइवान में भूकम्प के झटके महसूस किये गए।
- 2002-कोनोको इंक और फिलिप्स पेट्रोलियम ने विलय कर कोनोकोफिलिप्स बनायी।
- यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी।
- 2003- रूसी पनडुब्बी बेरेंट्स सागर में डूबी, नौ मरे, आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता।
- समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
- 2007-जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर मिमिथ और आल्फ्रेंस स्टालहोफ़ेन ने अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को गलत ठहराने का दावा किया। नेपाल की कोईराला सरकार ने चार माओवादी विद्रोहियों को फ्रांस, डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और मलेशिया का राजदूत नियुक्त किया। बांग्लादेश सरकार ने नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।

30 अगस्त को जन्मे व्यक्ति

- 2001-जैस्मिन लंबोरिया-भारत की महिला मुक्केबाज़ हैं।
- 1954-रवि शंकर प्रसाद-एक वकील और राजनीतज्ञ हैं।
- 1918-विनायक आचार्य-ओडिशा के 9वें मुख्यमंत्री रहे थे।
- 1912-नैंसी वेक-दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान प्रसिद्ध महिला लड़ाकों में से एक थीं।

विशेष आलेख

भारतीय राजनीति के चहेते दिशा-प्रवर्तक अटल बिहारी बाजपेई

संजीव ठाकुर

स्वयं को समाज का सेवक कहने वाले और समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान करने वाले व्यक्ति कोई साधारण लेखक या कवि मात्र नहीं थे,बल्कि भारतीय राजनीति के स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ही थे। वह भारतीय राजनीति में पक्ष-विपक्ष के चहेते राजनेता थे। भारतीय राजनीति में जिस प्रकार से एक नए युग प्रवर्तक की भूमिका अटल जी ने निभाई वह निश्चित तौर पर युगों युगों तक ज्यादा की जाएगी। 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में जन्मे अटल बिहारी वाजपेई विलक्षण प्रतिभा के वक्ता और संवेदनशील कवि थे। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर विक्टोरिया कॉलेज में उन्होंने स्नातक की डिग्री ली फिर राजनीति विज्ञान में कानपुर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य रहे तथा आर्य कुमार सभा में सक्रिय भूमिका निभाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल भी गए थे। इसके पश्चात भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संपर्क में आकर और अपनी प्रतिभा की बदौलत उनके राजनीतिक सचिव बन गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने राष्ट्र धर्म चेतना, दैनिक स्वदेश, वीर अर्जुन,आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी भली-भांति किया था। एक कुशल संपादक एवं प्रखर पत्रकार भी रहे हैं। 1953 में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनसंघ की अगुवाई का जिम्मा भी उनके ऊपर आया जिसका निर्वहन भी उन्होंने बखूबी किया। स्वाधीन भारत की राजनीति के अटल जी एक अटल स्तंभ बने और राजनीति में संवेदनशील सुचिता के प्रखर प्रवर्तक भी रहे। 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था पर उस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा पर धीरे-धीरे उनकी लोकप्रियता वृद्धि होती गई परिणाम स्वरूप वह 9 बार लोकसभा दो बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में श्री अटल बिहारी वाजपेई ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कवि ह्रदय होते हुए बेबाक बोलने का कौशल रखने वाले वाजपेई जी ने लगभग 4 दशक से अधिक समय तक विपक्ष में रहते हुए बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभाई और भारत के तीन बार प्रधानमंत्री चुने गए। पहली बार 1996 में 13 दिन दूसरी बार वर्ष 1998 में 13 महीने सरकार चला सके परंतु वर्ष 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद पूरे 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाने में वह कामयाब रहे। यह भारतीय राजनीति में उपलब्धि अपने नाम कराने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता है। स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उनकी वाकपटुता तथा ओजस्वी लेखन को देखते हुए कहा था किया नौजवान एक दिन भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। उनका कहना सत्य भी हुआ और नेहरू, इंदिरा जी के बाद पुनः देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने देश को एक नई राजनीतिक ऊर्जा दी। कवि ह्रदय होते हुए भी अटल जी ने बेझिझक होकर सबके सामने अपनी बात रखने का कौशल दिखाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाई। बिना किसी दबाव के उन्होंने परमाणु शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई और पड़ोसी देश पाकिस्तान से नए रिश्ते की बुनियाद भी रखी। उनके कार्यकाल की विदेश नीति अब तक की सबसे सफल विदेश नीति मानी जाती है। उन्होंने दिल्ली लाहौर बस सेवा का शुभारंभ किया और स्वयं बैठकर लाहौर तक गए थे। अटल जी की उदारता का अनुचित लाभ उठाते हुए 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध का कुचक्र रचा, अटल बिहारी जी ने इस युद्ध की स्थिति को बहुत अच्छी तरह संभाला और ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को पराजित किया था। अटल जी के नेतृत्व में इस विजय के फल स्वरुप अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश गया कि भारत का नेतृत्व कुशल और अनुभवी हाथों में है,भारत किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण सड़क योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सर्व शिक्षा अभियान और नदी जोड़ो परियोजना जैसी कल्याणकारी परियोजनाओं का आरंभ किया। बिना किसी वाद विवाद के वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के गठन का श्रेय भी अटल बिहारी सरकार को ही जाता है। उनके कार्यकाल में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत विकास दर में वृद्धि दर्ज करा सका था इस प्रकार उन्होंने आज के भारत को बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया था। राजधर्म को सर्वोपरि मानने वाले एवं उसका पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेई जी को आज भी एक सशक्त नेता ,मंत्र मुग्ध करने वाला वक्ता, कुशल प्रशासक, विरोधियों के बीच सहज स्वीकार्य ,भरोसा पैदा करने वाले और असहमतियों का आदर करने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है। कदम से कदम मिलाकर चलना होगा में विश्वास रखने वाले अटल जी में स्वाभाविक रूप से सबको साथ लेकर चलने का राजनीतिक कौशल भी था जिसके कारण उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करने में थकते नहीं हैं। अटल जी एक साफ-सुथरी निर्विवाद एवं बेबाक सभी के स्वामी थे। भारतीय राजनीति स्वच्छ छवि के एकमात्र नेता अटल बिहारी वाजपेई पूर्व प्रधानमंत्री ही थे। अटल जी एक अच्छे कवि तथा एक अच्छे लेखक भी थे। मेरी 51 कविताएं, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, कैदी कविराय की कुंडलियां ,21 कविताएं, न्यू डाइमेंशन आफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आदि प्रमुख किताबों के रचयिता थे। खराब स्वास्थ्य के कारण 2005 में राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। उन्हें 2014 में भारत रत्न से भी नवाजा गया था।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा सेड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नन्दुजा पठान* | प्रधान संपादक-राम विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244481 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-भैरूनाथ सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 | ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

चिंतन

लाल किले से विकसित भारत का एक्शन प्लान

लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत की आकांक्षाओं को आवाम के सामने रखा, जिसमें उन्होंने विकसित भारत की थीम के तहत कहा कि, पिछले दस साल में देश में बहुत कुछ बदले हैं, वर्तमान में बहुत कुछ बदल रहे हैं और अगले पांच साल में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। बेकार कानून खत्म हुए, अनेक शासनिक, प्रशासनिक व आर्थिक सुधार हुए, न्याय संहिता आई। वर्ष 2014 में पीएम बनने के बाद पहली बार लाल किला से मुझे बोलने का मौका मिला था। इस बार मोदी ने 11वीं बार संबोधित किया, पंडित नेहरू के बाद यह रिकार्ड है। अब तक के सबसे लंबे संबोधन (103 मिनट) में पीएम ने नकारात्मक व देशविरोधी राजनीति, राजनीति में परिवारवाद, दीमक की तरह व्याप्त भ्रष्टाचार, समान नागरिक संहिता (सेक्युलर सिविल कोड), एक राष्ट्र एक चुनाव, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात, बुनियादी ढांचे के विकास, कोलकाता रेप-मर्डर केस, सामान्य मानविकी की समस्याओं के निदान, निवेश आदि विषयों पर फोकस किया। अपनी सरकार की नीतियों पर बात करते हुए पीएम ने विकसित भारत लक्ष्य, नई शिक्षा नीति, आत्मनिर्भर भारत, न्याय संहिता, बैंकिंग सेक्टर व कृषि क्षेत्र में सुधार की बात कही। भाषण के दौरान मोदी ने एक खास बात कही कि 'कुछ लोग देश को निराशा के गर्त में डुबोना चाहते हैं, लेकिन हमें उनसे सावधान रहना होगा। उनका इशारा हाल में कांग्रेस व राहुल गांधी के बयानों की ओर था, जो अपनी राजनीति के लिए लक्षित झूठ के जरिये भ्रम की स्थिति पैदा करते रहते हैं। देश माई-बाप कल्चर से कुछ हद तक मुक्त हुआ है, गवर्नेंस मॉडल बदला है, लेकिन प्रो-पीपल या पीपल ओरिएंटेड प्रशासनिक सुधार अब भी अपेक्षित है। पीएम ने कहा, 'देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है। अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है'। इससे साफ है कि मोदी सरकार अब समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ बढ़ेगी। भाजपा के कोर वादे अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर, तीन तलाक का खात्मा आदि पूरे हो गए, केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बाकी है। सरकार इस कार्यकाल में एक देश एक चुनाव की पृष्ठभूमि भी तैयार करेगी। पीएम को जनगणना और परिसीमन पर भी सरकार की दृष्टि स्पष्ट करनी चाहिए थी। वर्ष 2026 तक परिसीमन होना है, इसके बाद लोकसभा व विधानसभा का गणित बदल जाएगा। लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का विषय भी परिसीमन पर ही अटका हुआ है। राष्ट्रीय जनगणना 2021 में नहीं हुई, इसके लिए 2031 तक इंतजार नहीं करना चाहिए, सरकार को जल्द जनगणना करा लेनी चाहिए, इससे जाति गणना का हौवा भी खत्म होगा और सब्सिडी व गरीबी उन्मूलन योजना में लक्ष्य आधारित सुधार करना आसान होगा। पीएम ने विकसित भारत के लिए दस से अधिक सुझाव भी दिए हैं। इनमें देश को स्किल कैपिटल बनाने, मैन्यूफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने, यूनिवर्सिटी हब, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने, मोटे अनाज को विश्व के हर क्षेत्र में पहुंचाने, न्याय व्यवस्था में सुधार, भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने, पारंपरिक औषधि को विकसित करने, शासन-प्रशासन में कैपिसिटी बिल्डिंग करने और भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने आदि शामिल हैं। सरकार राष्ट्रीय प्रीन हाइड्रोजन मिशन पर पहले से ही काम कर रही है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी व्यापक कदम बढ़ा रही है। समूचे संबोधन में विकसित भारत का खाका है, उसका एक्शन प्लान है, अब असल जरूरत इन पर अमल करने की है। राजग सरकार इन पर कितना अमल करती है, इस पर लक्ष्य निर्भर करेगा।

डॉक्टरों की जान कौन बचाएगा?

विचार
डॉ.संजय शुक्ला

भारत में चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते 9 अगस्त को कोलकाता के आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या की घटना ने पूरे देश के चिकित्सक बिरादरी को उद्वेलित कर दिया है। इस बर्बरता पूर्ण घटना के विरोध में धर्मोपैथिक चिकित्सकों के देशव्यापी संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 'आईएमए' ने 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से पीबीके गेट के लिए देशव्यापी काम ठप्प करने का ऐलान किया है। इस दौरान अस्पतालों में आपातकालीन सेवा के अलावा अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। मौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है जिसके घंटेट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत पीलेवर आ रहे हैं। साल 2019 में भी पश्चिम बंगाल में भीड़ ने एक जूनियर डॉक्टर पर हमला किया था जिसके बाद डॉक्टरों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया था। अलबत्ता कोलकाता की इस घटना ने सख्तरूप दल के लोगों की पोलिपाल और पुलिस जांच में खामियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। दूसरी ओर पंद्रह अगस्त को भारी भीड़ ने पहिंसा जहां कार्यरत थी उस अस्पताल में हमला कर काफी तोड़-फोड़ करते हुए जूनियर डॉक्टर के साथ भी हाथापाई की है। भीड़ द्वारा किए गए इस हमले में अस्पताल के उस हिस्से में काफी क्षतिग्रस्त हुआ है जहां युवा डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई थी जताया साफ है कि यह करतूत समूह विशेष के लिए किया गया है। आत्यर्यजनक तौर पर पश्चिम बंगाल पुलिस इस दौरान तमाशबीन बनी रही।

बहरहाल भारत में किसी मरीज की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराने, उस पर हमला करने और उसके अस्पताल में तोड़फोड़ की खबरें आम है। बीते साल 2023 में केरल के एक अस्पताल में कथित तौर पर नशे में धूत एक मरीज ने युवा सर्जन डॉ. वंदना दास की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। केरल में ही भीड़ ने एक अस्पताल में मरीज की मौत के बाद एक कॉर्डियोलॉजिस्ट पर हमला कर दिया जबकि वह मरीज के उपचार में शामिल ही नहीं था। आईएमए के केरल इकाई के अध्यक्ष के मुताबिक केरल में हर महीने डॉक्टरों पर हमले के पांच मामले दर्ज होते हैं। देश के डॉक्टर कितने दबाव में काम कर रहे हैं इसका अंदाज बीते सालों के दौरान भीड़ द्वारा डॉक्टरों के अस्पतालों और खुद उन पर हो रहे हमलों से पता चल रहा है। विडंबना यह कि पुलिस भी राजनीतिक या भीड़ के दबाव में आकर डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है फलस्वरूप उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मौरतलब है कि राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट शहर में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद डॉक्टर पर दर्ज हत्या के प्रकरण और मृतक मरीज के परिजनों से व्यथित हाईआर्डना हमनी द्वारा खुदकुशी की घटना ने समूचे चिकित्सक बिरादरी को स्तब्ध कर दिया था। बहरहाल अस्पतालों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हो रहे हमलों और तोड़फोड़ के बाद चिकित्सा संगठनों के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ी हुई है कि सरकार के तमाम दावों और कानूनों के बावजूद वे कितना सुरक्षित हैं? विशेषज्ञों के अनुसार कानून में डॉक्टरों को पूरा संरक्षण तो है लेकिन यह उन्हें पेशेवर जिम्मेदारियां नहीं देता फलस्वरूप डॉक्टर अपने पेशे में मजबूत नहीं हैं। कानूनी तौर पर डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मामले दर्ज हो सकते हैं लेकिन उपचार के दौरान मौत पर आमतौर पर इलाज में लापरवाही यानि धारा 304 ए के तहत मामला कायम होता है लेकिन कई मामलों में पुलिस दबावबश डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस ने हत्या यानि धारा 302 का मामला कायम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में यह फैसला दिया था कि चिकित्सक के खिलाफ इलाज में लापरवाही के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के पहले विवेचना अधिकारी को संबंधित मामले में विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड की राय को प्राथमिकता देनी चाहिए अधिकतर मामला लापरवाही का है अथवा नहीं। इस फैसले के मुताबिक मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर ही चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी तब तक डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मौरतलब है कि तेज सरकार ने साल 2020 में देश में कोरोना जांच के दौरान कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले के बाद 123 साल पुराने 'महामारी अधिनियम 1897' में बदलाव करते हुए एक कानून लागू किया था। इस संशोधित महामारी अधिनियम में डॉक्टरों और अन्य हेल्थ वर्कर्स पर हमला करने या दुर्व्यवहार करने वालों पर अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। चिकित्सा संगठनों से जुड़े लोगों के मुताबिक यह कानून महामारी के बाद लागू शुरुआ हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा साल 2022 में लोकसभा में हेल्थ केयर प्रोफेशनल और वित्तीयकर्ता प्रतिष्ठानों के खिलाफ हिंसा की प्रोहिबिशन विधेयक - 2022 पेश किया गया है जो अभी पारित नहीं हुआ है। इस कानून में अस्पतालों, डॉक्टरों, नर्सेज और अन्य हेल्थ वर्कर्स को हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। प्रस्तावित कानून में अस्पतालों या हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ होने वाले हिंसा को संज्ञेय अपराध मानते हुए हमला, दुर्व्यवहार और हिंसा करने वालों के खिलाफ बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान है। मामले में दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को 6 महीने से लेकर 7 साल का कारावास एवं 1 लाख से 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। अस्पताल में हमला और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कारावास के साथ ही संपत्ति नुकसान का बाजार मूल्य से दोगुना वसूलने का भी व्यवस्था इस कानून में है। कोलकाता संहिता अथवा हाल में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों के परिप्रेक्ष्य में देश भर के चिकित्सक और उनके संगठन इस कानून को तुरंत लागू

करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अलबत्ता देखना यह है कि सरकार डॉक्टरों के परिवाद पर कब संजीदा होती है? हालांकि वर्तमान में देश के 19 राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून लागू है। आंध्रप्रदेश पहला राज्य है जहां 2007 में स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया था जिसमें इस पेशे से जुड़े डॉक्टरों और अन्य कर्मियों के साथ हिंसा को गैर जमानती अपराध मानते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है। विडंबना है कि इस कानूनी प्रावधानों के बावजूद मेडिकल स्टाफ के साथ हिंसा नहीं थम रही है तथा अराजाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। देश में चिकित्सा बिरादरी पर हो रहे हमलों के कारण डॉक्टर जोड़ दबाव में काम कर रहे हैं वहीं डॉक्टर और मरीज के बीच परस्पर विश्वास भी घट रहा है जो चिकित्सा जैसे मुकद्दस पेशे के लिए अशुभ है। डॉक्टर मरीजों के दर्द और मर्ज दोनों को ठीक करने का हरसंभव कोशिश करता है लेकिन यदि मरीज का मरीज नहीं हो तो डॉक्टर को हर कोशिश नाकाम हो जाती है। डॉक्टर को 'गोड ऑफ अर्थ' यानि धरती का भगवान कहा जाता है। एक डॉक्टर के जिंदगी में ऐसे क्षण बार-बार आते हैं जब कोई मरीज आखरी सांस की डोर थामे जिंदगी के लिए जिंगोजद्दो जद्दोजहद कर रहा हो, यह संघर्ष एकतरफा मरीज की ही नहीं बल्कि खुद डॉक्टर के लिए भी होती है। मरीज के जीवन और मौत के बीच जारी जंग में सांसों की हार पर सबसे ज्यादा दुखी और निराश डॉक्टर ही होता है। आमतौर पर हर डॉक्टर अपने पेशे के प्रति हमेशा संजीदा रहता है तथा वह हरसंभव समाज को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए संकल्पित भी रहता है। एक डॉक्टर अपने व्यवसायिक जीवन में सैकड़ों लोगों को मौत की मुंह से बाहर निकालता है हजारों को बीमारी से मुक्त करता है ऐसे में किसी अनहोनी के लिए डॉक्टर को कठघरे में खड़ा करना कितना उचित है? तब मरीज के परिजनों या भीड़ ने कानूं हाथ पर लेंगे किया? विडंबना है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा और दुर्व्यवहार के मामले कोरोना महामारी के दौरान भी बढ़े जब पेशेवरों ने हेल्थवेयर वर्कर्स को सलाम देने और उनका उत्साहवर्धन के लिए घंटी, थाली और ताली बजाई थी हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए थे। महामारी के दौरान और उपचार के दौरान हिंसा और दुर्व्यवहार की लगातार घटनाएं हुई जो उनके लिए बेहद निराशाजनक था। समाज के एक हिस्से के चिकित्सा बिरादरी के अपमानजनक व्यवहार के बावजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीजों के जिंदगी की डोर थामने दिन-रात जुटे रहे। बावजूद के खिलाफ जंग के दौरान अनेक डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स भी गंभीर रूप से संक्रमित हुए हैं और उनकी मौतें हुई है। महामारी के दौरान 1500 डॉक्टरों की मौत हुई थी। एक शोध के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना जांच और उपचार के दौरान डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के साथ संक्रमित 66 फीसदी हिंसा भारत में हुए थे।

विचारणीय है कि डॉक्टरों पर हो रहे हमलों से चिकित्सक समुदाय खाब में है तथा अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिसका प्रभाव उनके कार्यक्षमता और दक्षता में दृष्टिगोचर हो रहा है। कुछ सालों पहले आईएमए द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 75 फीसदी डॉक्टर अपने कार्यस्थल में किसी न किसी हिंसा का शिकार होते हैं जो अधिकतर मरीजों के परिजनों द्वारा अंजाम दिया जाता है।बेड के बीच में 87.7 फीसदी डॉक्टरों ने अपने पेशे में तनाव की बात कही थी जिसमें 46.3 फीसदी डॉक्टरों का मानना था कि हिंसा उनके तनाव का मुख्य कारण है। इस शोध में 62.8 फीसदी डॉक्टरों ने खतरा था कि वे हिंसा और भय के बीच सेवाएं देंगे हैं।बहरहाल डॉक्टरों के साथ हिंसा हर हाल में अस्वीकार्य है लेकिन हिंसा के पीछे के कारणों पर डॉक्टरों और समाज दोनों को सोचना होगा।कि सदेह समाज में नैतिक मूल्यों के क्षरण का असर चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे पर भी हुआ है तथा कुछ चिकित्सकों ने इस मुकद्दस पेशे को बुनियादी आवश्यकों के खिलाफ आचरण किया है लेकिन इसके लिए समूचे चिकित्सा बिरादरी को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। बहरहाल आम जनता और समाज से अपेक्षा है कि वह चिकित्सकों और उनके सहकर्मियों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए।चिकित्सक भले ही ईश्वर हमें जीवन देता है लेकिन गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं में जीवनदान तो डॉक्टर ही देता है। सरकार का भी दायित्व है कि वह अस्पतालों, डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य सेवा में जुटे कर्मियों के जान-माल की सुरक्षा हेतु सख्त कानून लागू करे ताकि चिकित्सा जैसे पवित्र कार्य में जुटे लोग निर्भय होकर अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकें।

पीएम संबोधन

डॉ. मोनिका शर्मा

महिलाओं के लिए देश में बने भयमुक्त परिवेश

कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद बर्बर हत्या के मामले में अभी वीभत्स खुलासे हो ही रहे हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और क्रूरता करने की घटना सामने आई है। मुजफ्फरपुर की घटना में भी 14 वर्षीय छात्रा के अर्धनग्न अवस्था में मिले शव पर गंभीर घाव मिले हैं। धारदार हथियार से कई जगह काटकर बच्ची को शारीरिक प्रताड़ना देने वाली दुष्कर्म की यह घटना भी दिल दहलाने वाली है। ज्ञात हो कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ भी दुष्कर्म और हद दर्जे की बेरहमी की गई थी। इस दर्दनाक वारदात में भी अर्धनग्न शरीर पर चोटों के कई निशान थे। वहीं झांसी में स्वतन्त्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ भी दुष्कर्म की घटना सामने आई है।

बेटियों के साथ किए गए वीभत्स और क्रूरतम व्यवहार के मामले समग्र समाज को भयभीत करने वाले हैं। महिलाओं के प्रति मौजूद बर्बरता की भयावह सोच लिए आए दिन देश के कोने-कोने से सामने आतीं ऐसी घटनाएं बताती हैं कि अब बात केवल चर्चा और चिंता करने तक सीमित नहीं रखी जा सकती। ऐसे मामलों में कठोर दंड और त्वरित कार्रवाई के जरिये आपराधिक मानसिकता के लोगों के मन में भय पैदा करना भी आवश्यक हो चला है। ध्यातव्य है कि 78वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बर्बरता पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ' मैं आज लाल किले से एक बार फिर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के तौर पर हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। देश में इसके खिलाफ आक्रोश है। मैं इस आक्रोश को महसूस कर सकता हूं।

देश, समाज और राज्य सरकारों को इसे गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो, इन राक्षसी कृत्यों को अंजाम देने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिले। समाज में विश्वास जगाने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना और सजा पाने वालों पर व्यापक चर्चा करना आवश्यक है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का मुद्दा समाज के हर वर्ग के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ये स्थितियां आमजन को एक विवशता के घेरे में भी ला रही हैं। जांच हो या कार्रवाई, इनसे जुड़ी संस्थाओं की निष्पक्षता से विश्वास घट रहा है। हर दिन कोई नई घटना और अपराधियों के लिए कानूनी कार्रवाई के नाम पर बरसों का इंतजार। कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी स्थितियां ही आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का दुस्साहस बढ़ाती हैं।

इन्हीं पीड़ादायी स्थितियों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 'देश में महिलाओं के साथ बर्बरता और अत्याचार हो रहे हैं। राज्य सरकारों से, शासन-प्रशासन से अपील करता हूं कि वो ऐसे उदाहरण पेश करें कि कोई किसी महिला के साथ ऐसा करने की हिमाकत नहीं कर सके। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। बलात्कार जैसा पाप करने वाले को फांसी की सजा हो ताकि कोई ऐसा करने की सोचे तो उसे पता हो कि जीवन से हाथ धोना होगा।' चिंतनीय है कि समस्या अपराधियों को सबक ना मिलने की ही है। बरसों-बरस चलने वाली कानूनी कार्रवाई परिजनों का हौसला तोड़ देती है। अपराधियों की हिमाकत बढ़ाती है। नतीजतन बलात्कार महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हालिया वर्षों में दुष्कर्म के मामलों में 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2022 के आंकड़े कहते हैं कि देश में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटनाएं होती हैं। प्रतिवर्ष महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी देश की छवि बिगड़ रही है । यह कटु सच है कि हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे भारत में आज शिक्षित-अशिक्षित, ग्रामीण-शहरी, बालिग-नाबालिग हर जगह और हर आयुवर्ग की महिलाएं डर के माहौल में जी रही हैं। लचर रवैये और आरोप- प्रत्यारोप के बजाय त्वरित कार्रवाई से ही इन हालातों को बदला जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को मिली सख्त सजा ही समाज में भी भरोसे का भाव जगा पाएगी।

(लेखिका स्वतंत्र स्तम्भकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सिया राम मय सब जग जानी

संकलित
दर्शन

हमारे वेद कहते हैं- सर्वे भवंतु सुखिनः:, सर्वे संतु निरामया...अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों। वहां कोई, वर्ण, जाति, समूह और पक्ष-विपक्ष की बात ही नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले यह सूत्र दे दिया था-वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। संपूर्ण विश्व के लोगों के सुख और स्वास्थ्य की कामना भारतीय दर्शन का मूल है। न सिर्फ मनुष्य, बल्कि जीव मात्र के हित की इच्छा रखना ही सनातनी परिचय है। मैं राम कथा गाता हूं। राम राज के मूल में भी सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की ही भावना है। भगवान श्रीराम ने सेतु बनाया। आज पूरे विश्व में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु बनाए जाने की आवश्यकता है। जिसमें भी राम तत्व होगा, वह केवल जोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की नहीं। सत्य, प्रेम और करुणा प्रमुख राम तत्व हैं। जिसमें ये तत्व होंगे, वह वंचितों तक पहुंचेगा। राम समाज के वंचित लोगों के पास स्वयं चलकर गए। केवट, शबरी, अहिल्या के प्रसंग इसके प्रमाण हैं। आज समाज की एक बड़ी जरूरत है कि सक्षम लोग वंचित लोगों तक, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक स्वयं चल कर पहुंचें। मानस में नौ प्रकार की भक्ति का वर्णन हुआ है। शबरी के सामने गाई गई नौ प्रकार की भक्ति में गोस्वामी जी ने सातवीं भक्ति पूरे संसार को ब्रह्ममय मानना-देखना बताई है-'सातवं सम मोहि मय जग देखा।' जब हम पूरे संसार को ब्रह्ममय देखेंगे, महसूस करेंगे तो किसी के भी दोष दिखाई नहीं देंगे।

मंजिल तक कैसे पहुँचा जाए

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक संत ने अपने दो भक्तों को बुलाया और कहा आप को यहाँ से पचास कोस जाना है। एक भक्त को एक बोरी खाने के समान से भर कर दी और कहा जो लायक मिले उसे देते जाना। और एक खाली बोरी दी उससे कहा रास्ते मे जो उसे अच्छा मिले उसे बोरी में भर कर ले जाए। दोनों निकल पड़े जिसके कंधे पर समान था वो धीरे चल पा रहा था। खाली बोरी वाला भक्त आराम से जा रहा था। थोड़ी दूर उसको एक सोने की ईंट मिली उसने उसे बोरी में डाल लिया। थोड़ी दूर चला फिर ईंट मिली उसे भी उठा लिया। जैसे-जैसे चलता गया उसे सोना मिलता गया और वो बोरी में भरता हुआ चल रहा था। और बोरी का वजन बढ़ता गया उसका चलना मुश्किल होता गया और साँस भी चढ़ने लग गई।

एक एक कदम आगे चलना कठिन होता गया। दूसरा भक्त जैसे-चलता गया रास्ते में जो भी मिलता उसको बोरी में से खाने का कुछ समान देता गया धीरे-धीरे बोरी का वजन कम होता गया। और उसका चलना आसान होता गया। जो बाँटता गया उसका गंतव्य स्थान तक पहुँचना आसान होता गया। और जो लालच में आकर इकट्ठा करता रहा वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हम सभी को अब ये सोचना चाहिए कि हमने जीवन में क्या बाँटा और क्या इकट्ठा किया हम मंजिल तक कैसे पहुँच पाएँगे। आखिर लालच ही बुरी बला है।

अंतर्मन

आज की पाती

गौरवमय भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति पर पहले से ही अतिक्रमण होते आए हैं, फिर भी उस चीज का क्रामण रहना अत्यंत शास्त्र की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। भारत आध्यात्मिक भूमि होने के कारण यहां की संस्कृति को नष्ट करने के लिए आने वाली ताकतें खुद ही नष्ट हो गईं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को महत्व मिलने पर भी सिर्फ मौज-मस्ती करने के लिए हमें हमारी संस्कृति पर आक्रमण करने वाले विदेशी रिवाजों की क्या जरूरत है? उनका समर्थन करने में समय बर्बाद करना हमारी वैचारिक कमजोरी है। विदेशों की तरह देश की पाठशाला-महाविद्यालयों के छात्र इनके की चपेट में आ चुके हैं। इस सुनी आवत से उन्हें कैसे छुड़ाया जाए यह बड़ा सवाल देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। - पवन सोनी, डोंगरगढ़

ट्रेंड

जल्द कड़ी सजा मिले

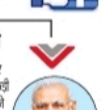

हमारी लड़कियों-बहनों बेटियों पर अत्याचार करने के गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा घृणा करने वालों में डर पैदा हो।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

सेक्युलरिज्म का पालन हो

पीएम द्वारा 15 अगस्त को लाल किले से डा. भीमराव आंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक-समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की सौर्वभौमिक व्यवस्था को 'कम्युनल' कहना क्या उचित है? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म है। -मायावती, बसपा सुप्रीमो

अभी बहुत कुछ बाकी

दिवाली त्यार करने वालों ने अपने आप में दक्ष बनने तथा, भारत ने निश्चय आत्म आप वाले देश का दर्जा हासिल करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। उस आप वाला देश बनने वाले हमारी कोशिश में अभी भी बहुत कुछ शामिल करना बाकी है। -किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

आवाज उठाइये

आवाज उठाइये !! हर हालत में आवाज उठाइये ! कोलकाता की डॉक्टर बच्ची के साथ जो हैवानी, रूह को हिला देने वाला और मानवता को तार-तार किया गया है। उसके खिलाफ आवाज उठाइये। -अनुपम खेर, अभिनेता

करंट अफेयर

न्यूयॉर्क में हर्षोल्लास से मनाया गया भारत का स्वतंत्रता दिवस

भारत के तिरंगे की छटा, समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत और अमेरिका के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की झलक न्यूयार्क सिटी में उस समय देखने को मिली जब यहां भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति की भावना और हर्षोल्लास साथ मनाया गया। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुसदस्यीय कौंसलेट ने शहरभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों के साथ-साथ भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित किया गया। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन, टाइम्स स्क्वायर और लोअर मैनहट्टन में भारतीय प्रवासियों तथा शहर के अधिकारियों की उपस्थिति में धव्जारोहण समारोह आयोजित किए गए। लातिन अमेरिका की यात्रा से पहले शहर में ही मौजूद विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने वाणिज्य दूतावास और टाइम्स स्क्वायर में आयोजित धव्जारोहण समारोह में प्रवासी समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। अप्रवासी प्रवासी संगठन 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन' (एफआईए) ने न्यूयॉर्क सिटी के प्रमुख स्थल टाइम्स स्क्वायर पर स्वतंत्रता दिवस पर एक विशेष समारोह आयोजित किया।

ऑफ बीट

अंडाशय के कैंसर का पता लगाना कठिन

डिम्बग्रंथि या अंडाशय के कैंसर का पता अक्सर तब चलता है जब वह विकसित हो चुके होते हैं और उनका इलाज करना कठिन होता है।

शोधकर्ताओं का लंबे समय से मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं को पहली बार लक्षणों का अनुभव तब होता है जब डिम्बग्रंथि का कैंसर अपनी जड़ें अच्छी तरह से जमा चुका होता है। लक्षणों को पहचानना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे असपष्ट और अन्य स्थितियों के समान ही होते हैं। लेकिन एक नए अध्ययन से पता चला है कि डिम्बग्रंथि के कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता लगाया जा सकता है। अध्ययन में चार विशिष्ट लक्षणों वाली महिलाओं को लक्षित किया गया - सूजन, पेट में दर्द, बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता, और जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होना - और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वह तत्काल किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। परिणामस्वरूप, डिम्बग्रंथि के कैंसर के सबसे आक्रामक रूपों का भी उनके प्रारंभिक चरण में पता लगाया जा सकता है। डिम्बग्रंथि के कैंसर का पता सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग (जिसे पैप स्मीयर कहा जाता था) के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता है और स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में पेल्विक परीक्षाएँ उपयोगी नहीं होती हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 17 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कर्म, ज्ञान और भक्ति-ये तीनों जहां मिलते हैं, वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है।

-महर्षि अरविंद

चुनौतियां नयी अंदाज पुराना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार देश को संबोधित किया। कहा कि भारत बाधाओं, रुकावटों और चुनौतियों को पारस्त करते हुए नये संकल्प के साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरे देश का समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों को लेकर जिस तरह आक्रामक है, उससे यह लक्ष्य काफी दूर नजर आ रहा है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की राह में भ्रष्टाचार दूसरी सबसे बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जो भ्रष्टाचार का महिमामंडन कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री एक

ओर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी पार्टी में ऐसे राजनीतिक नेता शामिल किए जाते रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जाहिर है कि ऐसे कृत्यों से जनता में संदेश जाता है कि सरकार कहती कुछ है, और करती कुछ और है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कुछ ऐसे राजनीतिक एजेंडे भी सेट किए जिन पर आने वाले दिनों में सियासत गर्म होगी। उन्होंने कहा कि इस समय देश में जो सिविल कोड है, वह वास्तव में कम्युनल है, भेदभाव करने वाला है। हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा का पुराना मुद्दा है। काफी संवेदनशील है और एनडीए के सहयोगी दल जदयू और तेलुगू देशम सिविल कोड को लेकर असहज हो सकते हैं। अन्य विपक्षी दलों में इसे लेकर मतैक्य बनाना आसान नहीं होगा। आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा कि इस पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन पाती है या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बिना कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की चर्चा की। कहा कि समाज के तौर पर हमें महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने नई शिक्षा नीति के संबंध में ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करने की बात कही जिससे देश के नौजवानों को विदेश न जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आश्वस्त किया कि देश तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा तो मैं तीन गुना गति से काम भी करूंगा। मैं चुनौतियों से टकराने से डरता नहीं हूं क्योंकि आपके और आपके भविष्य के लिए जीता हूं।

नापाक इरादों पर प्रहार

पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए भाषण में यह कहा। आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां किसी भी आतंकी संगठन का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं बचा है। हड़ताल और पथराव की घटनाएं इतिहास के पन्नों में सिमट गई हैं। पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए सिन्हा ने कहा, जो देश अपने नागरिकों को दो वक्त का खाना मुहैया कराने तक में असमर्थ है, वह अस्थिरता पैदा करने और शांति भंग करने के लिए यहां विदेशी आतंकियों को भेज रहा है। बीते दिनों आतंकी हमलों में शहीद

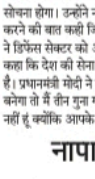

हुए अधिकारियों, सैनिकों और नागरिकों के बलिदान का उन्होंने स्मरण किया। स्थानीय लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने की भी बात की। सिन्हा ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आतंकवादी नेटवर्क पर हमला कर रहे हैं। उधर जम्मू में उधमपुर जिले में आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद कैप्टन दीपक सिंह को सेना और पुलिस ने श्रद्धांजली दी। डोडा के अस्सार में एक दिन पहले ही कैप्टन शहीद हुए थे। अंदेशा है कि ऊपरी इलाकों खासकर जंगलों में आतंकी छिपे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि पिछले दिनों हुए हमलों में आतंकियों ने अल्पाइन क्वेस्ट लोकेशन एप्लीकेशन का प्रयोग किया था जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना, नौ सेना और वायु सेना करती है। इसके जरिए घने जंगलों के नदी-नालों और पहाड़ी गुफाओं की सटीक लोकेशन मिल जाती है। कठुआ एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के पास मिली चीजों पर पाकिस्तानी जगहों के नाम और पते उर्दू में अंकित थे। जब-जब पाकिस्तान में आंतरिक उथल-पुथल होती है, वे अवाम का ध्यान बांटने के लिए सीमा से घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों में तेजी लाने लगते हैं। सरकार के कड़े निर्णयों और सेना को छूट देने जैसे निर्णयों ने ही आतंकवाद पर काबू पाया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व शांति बहाली के प्रयास बेहद जरूरी हैं।

कटाक्ष/ कबीरदास

अपनी-अपनी आजादी!

विरोधियों की ये दोरंगी पॉलिसी मोदी जी किसी भी तरह नहीं चलने देंगे। बताइए, एक तरफ भाई लोग आजादी-आजादी करते हैं। बार-बार मोदी जी से पूछते हैं कि आजादी की लड़ाई में उनके वैचारिक पुरखे कहां थे, क्या कर रहे थे, वगैरह, वगैरह। दूसरी तरफ ऐन उसी वाली आजादी की साल्लगिरह के मौके पर, सेवी की मुखिया का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस्तीफा भी अपना पैसा, घुमा-फिरा के अडानी भाई की कंपनी में लगाने के लिए। यानी मांगने को इन्हें सारी आजादी चाहिए और देने को बेचारी सेवी की मुखिया को इसका फैसला करने तक की आजादी देने को तैयार नहीं हैं कि अपना पैसा कहीं भी लगाएं।

विपक्ष वालों ने दोरंगी पॉलिसी का चलन चला दिया, तो जिसे देखो उसी रास्ते पर दौड़ रहा है। बताइए, राम जी की भव्य अयोध्या में, दिव्य भक्ति पथ और राम पथ पर लगी, देदीप्यमान लाइटों को, कुछ भक्तों ने जरा सा निजी क्षेत्र में स्थानांतरित क्या कर लिया, मीडिया वालों ने चोरी का शोर मचा दिया; छोटी-मोटी नहीं, पूरी आफा करोड़ की लाइटों की चोरी का। देश पूछता है, 15 अगस्त, 1947 को देश आजाद हुआ था कि नहीं हुआ था? कंगना जी नाराज न हों, हमारा 1947 पर इतना जोर भी नहीं है और 15 अगस्त पर तो और भी नहीं है। उन्हीं की बात हो, हमारा 2014 वाले स्वतंत्रता दिवस से भी कोई झगड़ा नहीं है। 1947 में न सही, 67 साल बाद 2014 में सही, आजादी तो मिली थी। क्या आजाद भारत में राम भक्तों को यह तय करने की भी आजादी नहीं होगी कि लाइट कहां लगना बेहतर है; सार्वजनिक पथ पर या निजी घर पर। 2014 वाली आजादी का आदर्श क्या वह वाला नहीं है-राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ की चिड़िया भर-भर पेट! प्लीज भक्ति के मामलों से न खाऊंगा न खाने दूंगा की गर्जनाओं को दूर ही रखें। पीएम जी लाल किले से युवाओं के लिए विज्ञान लाने का वादा किए हैं। बनारस विश्वविद्यालय में ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, तो एक आईआईटी में भूत विद्या और कहीं और पुनर्जन्म। एनसीईआरटी वाले किताबों में संविधान की उद्देशिका से लेकर मुगलों तक, न जाने क्या-क्या गायब कर रहे हैं। बताइए, विरोधी इस सबका भी विरोध कर रहे हैं। बात समझिए; 2014 वाली स्वतंत्रता यानी अपनी-अपनी आजादी!

फिजूल की तकरार

सामयिक

डॉ. मनीष कु. चौधरी

विगत दिनों संसद में राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ और राज्य सभा सांसद और प्रख्यात अभिनेत्री जया बच्चन के बीच उठे विवाद के कई राजनीतिक निहितार्थ हैं। संसद में सभापति की कुर्सी सर्वोच्च होती है। संसदीय नियमों और परंपराओं के साथ संसद की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। लोक सभा के चुनाव के बाद दोनों सदनों में अतिरिक्त गतिरोध दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र की आत्मा संसद में बसती है। संसद देश के दिमाग को आकार देती है। संसद विकास की नीतियों और योजनाओं का प्रसूति गृह है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों की भूमिका निर्णायक होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के प्रति उदार और अनुशासित रहें।

सभापति किसी दल के न होकर तटस्थ भूमिका में रहते हुए संवैधानिक नियमों, मर्यादाओं से बंधे होते हैं। जया बच्चन को अपने आधिकारिक नाम 'जया अमिताभ बच्चन' बुलाए जाने पर आपत्ति है। यह आपत्ति पहली बार दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि 29 जुलाई और 5 अगस्त को भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण द्वारा 'जया अमिताभ बच्चन' बुलाया गया। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उन्हें टोका और कहा कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन न कहा जाए। सिर्फ जया बच्चन कहा जाए।

उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आधिकारिक तौर पर उनका मिडिल नाम अमिताभ है, और वो इसी का पालन करेंगे। इस पर जया बच्चन ने कहा 'यह कोई नया तरीका है क्या कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएं। उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्या। उनकी अपने में कोई उपलब्धि नहीं है।' निस्संदेह जया बच्चन वरिष्ठ सांसद हैं। कुशल अभिनेत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता और सम्मान सर्वविदित हैं। लेकिन यह दूसरा पक्ष है। आप संसद में संसदीय मर्यादाओं से बंधे होते हैं। वहां आप सिर्फ और सिर्फ बुनियादी रूप से सांसद होते हैं। राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा भी जया अमिताभ बच्चन संबोधित किए जाने पर जया बच्चन नाराज हो गईं और सभापति से बोलीं, 'मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूं कि मैं कलाकार हूं, वांडी लॉयंडेल समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, सर आप मुझे माफ करिएगा, आपका जो रोल है, वह स्वीकार्य नहीं है।' इसके बाद सभापति धनखड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए जया बच्चन को बैठने के लिए कहा। धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सभा की वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का

निरादर करने का लाइसेंस है। विवाद इतना बढ़ा कि विपक्ष वॉकआउट कर गया और सभापति के विरुद्ध महाभियोग लाने की बातें आने लगीं। प्रश्न यह है कि संसद में छोटी-छोटी बातों पर अगर तल्खी इस कदर बढ़ेगी तो नुकसान किसका होगा। पूरे प्रकरण पर गौर करें तो सभापति और उपसभापति की भूमिका निर्दोष दिखती है क्योंकि संसदीय दस्तावेज में जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है। निःसंदेह इस नाम को जया बच्चन ने अपनी सहमति से दर्ज कराया होगा। फिर उस नाम के संबोधन से आपत्ति व्यावहारिक नहीं दिखती।

जया बच्चन ने अपनी फिल्मों में सदैव संवेदनशील चरित्र को जिया है, लेकिन व्यावहारिक जिंदगी में जया बच्चन की छवि गुस्सैल एवं तुनकमिजाज कतई जा रही है। इस छवि की निर्मिति के लिए जया बच्चन खुद जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भी अपने प्रशंसकों के साथ उनका संवेद्य तनावपूर्ण रहा है जिससे भी उनकी छवि प्रभावित होती है। राजनीति में हर कार्य के पीछे एक अप्रत्यक्ष विचार सक्रिय रहता है। कई बार कुछ भी बोलने -टोकने के अपने निहितार्थ होते हैं। कई बार लगातार टोकने-बोलने से हम किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी करते हैं। राज्य सभा के सभापति पर विपक्ष द्वारा आरोप तर्कसंगत नहीं है। यह पूरा प्रकरण पूर्वाग्रह से प्रेरित दिख रहा है। बात कई बार बढ़ी नहीं होती, उसे अनावश्यक विस्तार दे दिया जाता है जिसका खामियाजा देश को भुगतना होता है। संसद की प्रत्येक कार्यवाही पर हर एक मिनट में ढाई लाख रुपये खर्च होते हैं। संसद में हंगामा होने के कारण आम आदमी का लगभग ढाई लाख रुपये प्रत्येक मिनट बर्बाद होता है।

आसान भाषा में समझें तो एक घंटे में डेढ़ करोड़ रुपये खर्च हो जाता है। आम आदमी के पैसों की शर्त पर हम गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकते। सभापति जगदीप धनखड़ का यह कहना कि अभिनेता, निर्देशक का विषय होता है, यह कथन ज्ञापित करता है कि यह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं है, बल्कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। इस घटना के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जया बच्चन ने कहा कि संसद के सभापति हमारे सहकर्मी होते हैं। वह भी हमारी तरह एक सांसद हैं। यह तर्क भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि राज्य सभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनकी अपनी संवैधानिक गरिमा होती है। जया बच्चन जैसी वरिष्ठ सांसद से ऐसी टिप्पणी शोभनीय नहीं मानी जा सकती। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद कहा जा सकता है कि अगर विपक्ष सभापति से बार-बार असहमति दर्ज करा रहा है, तो उस बिंदु पर भी गंभीरता से विचार जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र की वैश्विक साख है। उस साख को बरकरार रखने का दायित्व देश के सभी सांसदों का है।

आम जन अपने प्रतिनिधि के रूप में सांसदों को चुन कर संसद में भेजता है। दुनिया की तुलना में हम आज भी कमतर हैं। बुनियादी सुविधाओं के लिए हम आज भी जूझ रहे हैं। चतुर्दिक चुनौतियों के मध्य संसद में इस तरह के गतिरोध देश के विकास में बाधक होते हैं। इससे जनभावनाओं की भी उपेक्षा होती है। संसद में सभापति का भी संवैधानिक दायित्व है कि बिना किसी भेद-भाव के संसदीय कार्यवाही का संचालन करें। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक रचनात्मक रिश्ता स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। वैचारिक असहमति मनुष्य होने की शर्त और सीमाएं हैं, लेकिन असहमतियों के बीच सहयोग और साथ देने के मानवीय गुणों को छोड़ा नहीं जा सकता। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है जिससे लोकतंत्र और देश मजबूत होता है।

सभापति किसी दल के न होकर तटस्थ भूमिका में रहते हुए संवैधानिक नियमों, मर्यादाओं से बंधे होते हैं। जया बच्चन को अपने आधिकारिक नाम 'जया अमिताभ बच्चन' बुलाए जाने पर आपत्ति है। यह आपत्ति पहली बार दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि 29 जुलाई और 5 अगस्त को भी उन्होंने नाराजगी जताई थी। इस मामले की शुरुआत तब हुई, जब राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण द्वारा 'जया अमिताभ बच्चन' नाम से बुलाया गया। इस पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उन्हें टोका और कहा कि उन्हें जया अमिताभ बच्चन न कहा जाए

मोदी के कीव दौरे की टाइमिंग से बुरा कुछ नहीं हो सकता। यूक्रेन के अपनी सीमा पर घुस आने पर रूस वही कार्रवाई की तैयारी में है। अमेरिका दोनों के बीच युद्ध नहीं रुकवाना चाहता लेकिन इस वाकत भारत के प्रयासों की सराहना कर रहा है। बांग्लादेश में अस्थिरता के मद्देनजर मोदी को अपने आसपास उमड़ आईं सामरिक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक

@Chellaney

विकास मापने का नया आधार

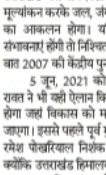

उत्तराखंड

सुरेश भाई

जुलाई के तीसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक (जीडीपी) लॉन्च किया। इसका सरल अर्थ है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में विकास कार्य से पहले मूल्यांकन करके जल, जंगल, जमीन, वायु पर उसके प्रभाव का आकलन होगा। यदि विपरीत प्रभाव की अधिक संभावनाएं होंगी तो निश्चित ही उसको रोकना भी पड़ेगा। यही बात 2007 की केंद्रीय पुनर्वास नीति में भी लिखी गई है।

5 जून, 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी यही ऐलान किया था कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां विकास को मापने के लिए जीडीपी लागू किया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने भी यह आश्वासन दिया था क्योंकि उत्तराखंड हिमालय में तेजी से भोगवादी विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, उसे रोकने के लिए छोटे-बड़े आंदोलन चलते रहते हैं। इसके बावजूद अब हर वर्ष सकल पर्यावरण उत्पादन में हम कहां खड़े हैं उसका मूल्यांकन करके जीडीपी के साथ जीईपी का लेखा-जोखा भी राज्य को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह किसी एक राज्य के लिए ही नहीं अपितु देश के लिए भी स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन इससे एक गंभीर आशंका भी पैदा होती है। यह कि संबंधित विभागों से प्रस्तावित विकास से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन का आधार क्या होगा? क्या कोई मॉनिटरिंग प्रणाली होगी? यह भी कहा जा रहा है कि राज्य द्वारा 95,112 करोड़ के लगभग दी जाने वाली पारिस्थितिकीय सेवाएं क्या हरियाली बचाने वाले निवासियों को लाभ प्रदान करेंगी या सिर्फ केंद्र से बजट का दावा पेश किया जाएगा। नीति आयोग इस विषय पर किस आधार पर फैसला लेगा? इन सब के उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे हैं।

वैसे भी समझने के लिए यह पर्याप्त है कि उत्तराखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 71 प्रतिशत वन भूमि के अधीन है, जबकि सघन वन 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है। लेकिन राज्य सरकार यही कह रही है कि जीईपी सूचकांक के आधार पर ग्रीन बोनस और केंद्र की सहायता लेने में यह लाभकारी साबित होगा। प्रति वर्ष जीईपी सूचकांक प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के प्रमुख सचिव (वन) को

दी गई है। इसका आंकलन मानवजनित और प्राकृतिक गतिविधियों के आधार पर होगा जिसमें जंगल, हवा, पानी, मृदा पर लगातार परिवर्तन जैसे-जंगल के संवर्धित सूचकांक के लिए विभिन्न वर्षों में वन विभाग द्वारा रोपे गए पौधों की संख्या और इन्हीं प्रजातियों के वृक्षों के पातन की संख्या के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसमें यह भी पता हो पाएगा कि पातन के दौरान छोटी-छोटी वनस्पतियां, जीव-जंतु बुरी तरह प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या हर वर्ष भीषण आग से जल रहे जंगल और रोपे गए पौधों के सापेक्ष प्राकृतिक वन संपदा की व्यावसायिक कटाई का मूल्यांकन करना आसान होगा? क्योंकि जिन पेड़ों को उसी वर्ष लगाया गया और यह मान लेंगे कि इतने ही इसी प्रजाति के पेड़ काटे गए तो यह अधूरी जानकारी होगी क्योंकि उत्तराखंड में हर साल चीड़, देवदार, कैल आदि प्रजातियों का बड़े पैमाने पर कटान हो रहा है।

मृदा के बारे में संभव है कि बड़े निर्माण कार्यों से केतलीव ढंग से काटे जा रहे पहाड़ों से खिसक रही मिट्टी को सीधे नदियों में डाला जाता हो और कहीं भी मिट्टी को पुनः उपयोग में लाने के लिए ढंगिग जोन नहीं है जिसके ऊपर पौधे रोपे जा सकते थे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मिट्टी की बर्बादी का मूल्यांकन संभव नहीं। जल के मामले में उपलब्ध जल की गुणवत्ता और मात्रा में तेजी से बढ़ रहे प्रभाव का सबसे जीता जागता उदाहरण तो यही है कि पहाड़ी भू-भाग में भी 60 प्रतिशत जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसके एवज में जो भी जल संरचनाएं बनी हैं, क्या उन्हें प्राकृतिक जल स्रोतों के समान स्वीकार किया जा सकता है? और कोई भी विकास संरचना यदि जल स्रोतों को बर्बाद करती है तो उसे न्यूनतम करने के क्या तरीके होंगे। जंगल के बारे में भी कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर न्यूनतम वनों को ही नुकसान हो।

भौगोलिक संरचना के आधार पर विकास की संरचना निर्धारित हो। भारी-भरकम परियोजनाओं से हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों का विनाश नहीं रोक पाएंगे तो जीईपी की हालत जीडीपी जैसी होगी। सकल पर्यावरण उत्पाद की मांग करने वाले पद्मभूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी मानते हैं कि उत्तराखंड में .9 प्रतिशत जीईपी है, जिसे 4-5 तक ले जाना पड़ेगा। लेकिन राज्य व्यवस्था तो फंड के लिए मजबूत हथियार के रूप में इसे देख रही है जबकि ग्रीन बोनस की मांग करने वाले पर्यावरणविद् जगत सिंह 'जंगली' और रक्षा सूत्र आंदोलन की टीम का कहना है कि रसोई गैस पर लोगों को आधी से अधिक सब्सिडी दी जानी चाहिए। जल पुरुष राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पर्यावरणीय आर्थिकी वहां होगी जहां लोग अहिंसक होंगे।

मानव जीवन

संत राजिन्दर

हम इस संसार में मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हैं। केवल कुछ लोग ही इस बारे में ध्यान देते हैं कि मनुष्य जन्म के अलावा और कितनी प्रजातियां हैं जो इस संसार में जन्म-मरण के चक्र में फंसी हुई हैं? हाल में हुए वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि इस संसार में सात से नौ खरब प्रजातियां पाई जाती हैं। इस तथ्य को जानने के बाद हमें पता चलता है कि मानव जन्म के मिलने की संभावना उन प्रजातियों में, जिनमें हमें भी जन्म मिल सकता था, कितनी कम है। स्वर्ग को शीशे में मानव शरीर के रूप में देखना अपने आप में खुशी मनाना है। सोचो! अगर हम कीड़े-मकौड़े, मछली, पेड़ या रेंगने वाले जीव होते तो हमारा जीवन कितना कठिन होता। यह मानव जीवन इन सभी योनियों में सरताज योनि है क्योंकि इसमें हमें विवेक दिया गया है, जिसमें हम सत और असत का निर्णय कर सकते हैं। केवल इसी मानव शरीर में ही हम अपने आपको जान सकते हैं, और पिता-परमेश्वर को पा सकते हैं। जब हम छोटी-छोटी और उत्तेजित सांस लेते हैं, तब हमें अधिक सांसों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार हमारे शरीर में सांसों की कमी होती जाती है। दूसरी तरफ प्रेम भरी जिंदगी सच्चाई, अहिंसा, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा भाव से हम अपनी सांसों को शांत, धीमा और स्थिर बनाते हैं। गहरी सांस लेने से हमारी आयु के मिनटों, घंटों और दिनों की संख्या बढ़ जाती है। इसका चुनाव हमें स्वयं करना है कि गहरी सांस लेते हैं, या छोटी अर्थात हम एक सूर्णो से भरा जीवन व्यतीत करते हैं, या ऐसा जीवन जिसमें अवगुण भरे हुए हों। अपनी सांसों का इस्तेमाल अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास और अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने के लिए भी कर सकते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो हम इस संसार में आने के अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इसके साथ-साथ हम अपने भीतर विशाल स्तर पर रूहानी खजाने, प्रभु-प्रेम, मस्ती और शांति का भी ईनाम पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी सांसों को अपनी रूहानी जागृति और दूसरों की मदद करने में लगाएं ताकि हम प्रभु द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। आइए! हम अंदर से जागृत और सचेत हों ताकि जिंदगी के हर क्षण, हर पल का हम सही उपयोग करते हुए इस अनमोल मानव जीवन को सफल बनाएं।

रीडर्स मेल

बांग्लादेश के पीड़ाजनक हालात

बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान हिन्दू मंदिर और हिन्दुओं पर हमलों से विश्व समुदाय पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिन्दुओं के कत्लेआम से मानवाधिकार का हनन भारत के लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। बांग्लादेश में हिन्दुओं को टारगेट बनाने वाली भारत विरोधी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। बांग्लादेश की घटना से सबक लेकर हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में बंदूक की नोक पर देश में तालिबानी आकाओं ने राज छीन लिया। बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देशों के तख्तापलट की अंतरराष्ट्रीय साजिश बहुत कुछ बयां करती है। बांग्लादेश में हिन्दुओं को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। श्रीलांकि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद नये प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन जरूर दिया है लेकिन हिन्दुओं पर जुल्मोसितम अभी भी जारी हैं।

कांतिलाल मांडोत, सूरत

यूक्रेन ने दिखाया दमखम

पता नहीं यह किसी युद्ध विशेषज्ञ या सामरिक मामलों के किसी वरिष्ठ जानकार ने कभी कल्पना भी की थी कि नहीं कि यूक्रेन कभी रूसी सीमा के भीतर भी प्रवेश कर पाएगा? मगर यूक्रेन ने न सिर्फ खुद को, बल्कि पूरे दुनिया के रणनीतिकारों को चौंका दिया जब उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक हजार किमी. तक कब्जा कर लिया। इस पलटवार से ल्लादिमीर पुतिन सकते में हैं। इस क्षेत्र में रूसी सेना एकदम रक्षात्मक तरीके से घुटने टेकती दिखाई दे रही है। अपने दसियों हजार नागरिकों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने के काम में लगी हुई है। दरअसल, यूक्रेन के इस आक्रामक रुख से साबित हो गया है कि रूस को जितना ताकतवर समझा जाता था, उतना वो है नहीं। अगुस्त खबरों के अनुसार रूस ने अपने 70 हजार सैनकों को युद्ध में खो दिया है। उसके पास सैनिकों की सख्त कमी हो गई है। इसीलिए तो अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों से बेरोजगार युवाओं को भाड़े के सैनिकों के रूप में सेवा में लिया जा रहा है। देखना है कि कब यूक्रेन इसी तरह से आगे भी चौंकाने का दमखम रखता है?

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

असामाजिक तत्वों पर लगाम रहे

बांग्लादेश में आरक्षण पर उपजे उबाल का खामियाजा हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय को भी उठाना पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं की नई-पुरानी एवं झूठी-सच्ची वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जा रही हैं। नतीजतन, उसका कुछ प्रभाव वहां भी ओडिशा के कई क्षेत्रों में बांग्लादेशी और बांग्लाभाषी समुदाय पर पड़ा है। कुछ असामाजिक तत्त्व बांग्लाभाषी लोगों को बांग्लादेशी कह कर परेशान कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुखी दिखी हैं क्योंकि बहुत से बांग्लाभाषी अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। कहीं ये लपटें बाकी हिस्सों तक न पहुंच जाएं, इसीलिए ओडिशा के मुख्यमंत्री से सांप्रदायिकता फैलाने वाले असामाजिक तत्त्वों से सख्ती से निपटने का अनुरोध किया गया है। बांग्लादेश की स्थिति को मुद्दा बनाकर भारत में माहौल खराब करने की जानी-अनजानी कोशिश वास्तव में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है।

माम चंद सागर, ई मेल से
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजमी द्वारा सहारा इंडिया भवन कम्युनिकेशन सेंटर, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवांग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
: समूह संपादक - डॉ. विजय राय। संपादक-संपादक - राणेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 3
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी पहलुओं के लिए उत्तरदायी

14.5 प्रतिशत योगदान पशुपालन क्षेत्र का है वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में। दुग्ध उत्पाद और मांस की खपत के लिए बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। मांसाहार को हतोत्साहन से भी इस उत्सर्जन को घटाया जा सकता है।

पेरिस ओलिंपिक

जलवायु परिवर्तन की चिंता पर सार्थक पहल

हाल ही में पेरिस ओलिंपिक 2024 का समापन हुआ है। इस दौरान अनेक नकारात्मक तथ्यों के सामने आने के बीच इस ओलिंपिक के आयोजन में कई ऐसी अनेक सकारात्मक चीजें भी रहीं जिनका उल्लेख व्यापक रूप से नहीं हो सका। वस्तुतः पेरिस ओलिंपिक के आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रति जिस प्रकार की प्रतिबद्धता दर्शाई गई, वह उल्लेखनीय है। खासकर ऐसे दौर में, जब हमारा देश जलवायु परिवर्तन की समस्या से व्यापक रूप से दुष्प्रभावित हो रहा हो, हमारे लिए यह कहीं अधिक महत्व का विषय बन जाता है

शिवेश प्रताप
लोकनीति विश्लेषक एवं तकनीकी प्रकरण सलाहकार

लगभग एक सप्ताह पहले पेरिस ओलिंपिक का समापन हो चुका है। इस आयोजन के आरंभ से लेकर समापन तक ऐसे कई विवाद सामने आए, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इस बीच पेरिस ओलिंपिक की मानवता के दूरगामी कल्याण हेतु उठाए गए बड़े कदमों पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई, जितनी होनी चाहिए थी। पेरिस ओलिंपिक खेलों ने वैश्विक खेल आयोजनों में सस्टेनेबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जिस नए मानदंड को स्थापित करने का प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है और भारत सहित कई देशों के लिए अनुकरणीय भी है, जहां कृषि आधारित आर्थिकी होने के कारण इस तरह के जलवायु परिवर्तन संबंधी विमर्श की गंभीर आवश्यकता है।

ओलिंपिक खेल मानव उत्कृष्टता और एकता का प्रतीक रहे हैं, परंतु बड़े पैमाने पर आयोजन होने से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव बढ़ती चिंता का विषय भी बनता जा रहा था। पेरिस ओलिंपिक इन चिंताओं को दूर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी को आयोजन के हर पहलू में शामिल करना चाहता था। जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते के साथ तालमेल बिठाते हुए ओलिंपिक आयोजकों ने पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को कम करने और सामाजिक व आर्थिक लाभों को अधिकतम करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई। कार्बन उत्सर्जन को कम करने से लेकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने तक आयोजकों ने जिस समावेशी ओलिंपिक का अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता दिखाई, वह प्रशंसनीय है। इसी क्रम में दो विषयों ने दुनिया को अचंभित किया- एयरकंडीशन रहित कमरे और शाकाहारी भोजन। ऐसे में हमें पेरिस ओलिंपिक द्वारा पर्यावरणीय महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए प्रमुख उपायों की चर्चा करनी चाहिए।

कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य : पेरिस ओलिंपिक 2024 की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक लंदन 2012 और रियो 2016 ओलिंपिक खेलों की तुलना में कार्बन फुटप्रिंट को 50 प्रतिशत तक कम करना था। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य सभी प्रकार के कार्बन उत्सर्जन जैसे प्रत्यक्ष, परोक्ष और दर्शकों की यात्रा से उत्पन्न उत्सर्जन सहित खेलों के हर पहलू जैसे निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, केटरिंग और खरीद के लिए एक कार्बन बजट निर्धारित किया गया था।

शाकाहारी खाद्य पदार्थों को महत्व : पशुपालन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई और अत्यधिक जल उपयोग का एक प्रमुख कारण है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 14.5 प्रतिशत योगदान पशुपालन का है। ब्रिटेन की संस्था आइएमई के अनुसार, एक किलो गेहूं के उत्पादन में पांच सौ से चार हजार लीटर पानी एवं एक किलो मांस के उत्पादन में पांच हजार से 20 हजार लीटर पानी की खपत होती है। पेरिस ओलिंपिक के आयोजक पशु उत्पादों की खपत को कम करके पौध आधारित शाकाहारी विकल्पों को बढ़ावा देकर खेलों द्वारा होने वाली पर्यावरणीय हानि को काफी हद तक कम करना चाहते थे।

वस्तुतः पौध आधारित आहार कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, जिसमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर के खतरे में प्रभावी रूप से कमी आती है। शाकाहारी और पौध आधारित विकल्पों की उपलब्धता बढ़ाकर, आयोजक न केवल विभिन्न आहार प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे थे, बल्कि एथलीटों और दर्शकों के बीच स्वस्थ खाने की आदतों को भी बढ़ावा दे रहे थे। पेरिस ओलिंपिक ने पिछले खेलों की तुलना में परोसे जाने वाले शाकाहारी खाद्य पदार्थों की मात्रा को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इस पहल में विभिन्न आहार प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखते हुए स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गई। कार्बन फुटप्रिंट को और कम करने के लिए 80 प्रतिशत खाद्य उत्पाद फ्रांस के भीतर से प्राप्त किए जाने का सम्भाव्य लक्ष्य निश्चित किया गया, जिनमें से 25 प्रतिशत पेरिस के 250 किमी के दायरे से खरीदा जा रहा था। स्थानीय और मौसमी उत्पादों पर जोर देकर न केवल स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाने पर बल दिया गया, बल्कि परिवहन उत्सर्जन को भी कम करने में प्रभावी मदद मिली है।

पेरिस ओलिंपिक में भोजन में इनोवेटिव प्लांट आधारित व्यंजन शामिल किए गए जो फ्रांस की समृद्ध पाक परंपराओं से परिचय करा रहे थे। सब्जी से लेकर सलाद और पौध आधारित प्रोटीन तक इन व्यंजनों के बहुमुखी लाभ को उजागर कर रहे थे। भारत में तमाम प्रदेशों में होने वाले खेल आयोजनों में इसी प्रकार की पहल की आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय स्तर के खाद्य को वैश्विक और राष्ट्रीय पहचान मिले और भारत जैसे हरे भरे देश में पौध आधारित खाने की एक समृद्ध परंपरा को भी बल मिलेगा।

अस्थायी कार्यक्रम स्थलों का उपयोग : सस्टेनेबिलिटी रणनीति का एक प्रमुख पहलू मौजूदा या अस्थायी स्थलों का उपयोग है, जो कुल स्थलों का 95 प्रतिशत हिस्सा था। इस पहल से नए निर्माण की आवश्यकता को कम किया गया, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आई। इसके लिए कई प्रतिष्ठित स्थलों को प्रमुख आयोजनों के लिए तय किया गया, जबकि नए स्थल स्थानीय आवश्यकताओं और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाए गए। नए स्थलों को कम-कार्बन निर्माण विधियों का उपयोग करके बनाया गया। ओलिंपिक गांव को 30 प्रतिशत कार्बन की कमी के साथ बनाया गया, जो सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पेरिस ओलिंपिक के दौरान तैयार किया गया एक मैदान जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल है। फाइल

सर्कुलर इकोनमी और सामुदायिक प्रभाव

पेरिस ओलिंपिक ने अपने आयोजन के हर स्तर पर एक सर्कुलर इकोनमी की रणनीति बनाई। यह रणनीति तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित थी : कम संसाधनों के साथ खेलों का आयोजन करना, इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और खेलों के बाद संसाधनों का दूसरा उपयोग सुनिश्चित करना। इस दृष्टिकोण से तमाम चीजों को खरीदने से अधिक किराये पर लेने या साझा करने को प्राथमिकता दी गई एवं संसाधनों के पूरे जीवनचक्र को नियंत्रित किया गया। परिवहन कार्बन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण है। पेरिस ओलिंपिक का उद्देश्य 40 प्रतिशत कम वाहनों का उपयोग करके और जलवायु अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देकर इस प्रभाव को कम करना था। लिहाजा दर्शकों व प्रतिभागियों द्वारा पेरिस की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पूरी तरह से उपयोग किया गया।

पेरिस ओलिंपिक की सस्टेनेबिलिटी की पहल का प्रभाव खेलों से परे भी विस्तारित रहा। आयोजक स्थानीय समुदाय के लिए एक स्थायी विरासत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। इसमें सीन नदी की सफाई, हरे-भरे स्थानों का निर्माण और अविकसित क्षेत्रों में निवेश शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खेलों के लाभ लंबे समय तक महसूस किए जा सकें। भारत में अगर खेल संभावनाओं के बीच हम क्रिकेट विश्वकप या अन्य प्रतियोगिताएं हेतु ऐसे मध्यम या छोटे शहरों में आधारभूत संरचना के विकास की योजनाएं तैयार कर सकते हैं, जो वहां के लिए भविष्य में सामुदायिक प्रभाव पैदा कर सके।

पेरिस ओलिंपिक की जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रतिबद्धता ने इन मुद्दों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। खेलों को कार्बन न्यूट्रल बनाने और किसी भी अपरिहार्य उत्सर्जन को प्रमाणित कार्बन आफसेट परियोजनाओं के माध्यम से संतुलित करने की योजना इस ओलिंपिक की बड़ी देन है। यह विमर्श भी पेरिस ने खड़ा किया कि हम खेलों को सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही अन्य शहरों व संगठनों को समान उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी शामिल करते हुए व्यक्तियों व समुदायों को जलवायु परिवर्तन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

पेरिस ओलिंपिक ने सस्टेनेबिलिटी और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए वैश्विक खेल आयोजनों में एक नया मानदंड स्थापित किया है। आयोजन के हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी को एकीकृत करके, आयोजक यह साबित कर रहे हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए भी एक शानदार आयोजन की मेजबानी करना संभव है। पेरिस ओलिंपिक द्वारा प्रारंभ की गई यह पहल और उपायों का लाभ न केवल स्थानीय समुदाय को मिलेगा, बल्कि यह भविष्य के आयोजनों के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में भी काम करेगा। भारत जैसे जलवायु परिवर्तन के आपातकाल से गुजर रहे देश को ऐसे आयोजनों से सीख लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कार्ययोजना पर बल देने की आवश्यकता है, जिससे खेलों और आयोजकों को पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबिलिटी के लिए अधिक जिम्मेदार बनाया जा सके।

(शिवेश प्रताप)

खरी-खरी

व्यंग्यकार की बेचैनी

पूरन सरमा

जिस समय वे मेरे यहां आए, बेहद परेशान थे। समाचार पत्र हाथ में लिए हुए शून्य में कहीं खोए थे। मैंने उनकी तंद्रा को तोड़ा, 'शायद आज कुछ नया नहीं लिख पाए हैं। व्यंग्यकार को विषयों की कमी नहीं है। आज की मुख्य खबर 'रेलें भिड़ीं' पर लिख मारिये व्यंग्य।'

वे चौंके, 'हां, मैं भी इसी पर लिखना चाहता हूं। दूसरी खबरों में दम भी नहीं हैं, परंतु रेल भिड़ने पर क्या व्यंग्य हो सकता है?'

मैं बोला, 'रचना के ऊपर आप व्यंग्य लिखते हैं और वह व्यंग्य के कालम में छपती है, इसलिए वह रचना अपने-आप ही व्यंग्य हो गई। रचना में व्यंग्य आया या नहीं, इसकी परवाह आपने कब की है?'

'रेलों के भिड़ने में व्यंग्य खोजिये,' वह बोलता रहा।

'लेकिन यदि तुम मेरे लेखन से इतने प्रभावित हो तो यह बताओ, क्या बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर व्यंग्य नहीं हो सकता?' उन्होंने गंभीर मुद्रा में कहा।

मैं बोला, 'आप मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? आपने तो ऐसी-ऐसी घटना-दुर्घटनाओं पर 'व्यंग्य' लिखे हैं, जिन पर व्यंग्य लिखने की व्यंग्यकारों ने कल्पना भी नहीं की है। व्यंग्य के लिए आप पुरस्कृत हुए हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि रेल और बांग्लादेश में से कौनसा विषय ठीक रहेगा? जहां तक मेरा मानना है, अच्छा रहे आप दोनों पर व्यंग्य लिख दें। दोनों विषय ज्वलंत हैं और विसंगत मूल्य उनमें निहित हैं।'

'बात पते की कही है तुमने। विसंगति व्यंग्य को जन्म देती है। इनमें विसंगति तुम्हारी नजर में क्या हो सकती है?'

मैंने कहा, 'इतना समझता तो मैं स्वयं व्यंग्य नहीं लिख लेता। विसंगति खोजना मेरे वश में नहीं।'

वे बोले, 'मैं सामान्य आदमी के नजरिये से इन दोनों घटनाओं को देखना चाहता हूं। मैं इन दोनों विषयों पर बहुत तीखा लिखना चाहता हूं।'

'वह तो आपकी परेशानी से लग रहा है कि आपका नित्यप्रति लिखना अनिवार्य है। चाहें तो आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि रेलें क्यों भिड़ीं और बांग्लादेश में हिंसा क्यों भड़की? आप तो शब्द शिल्पी हैं।'

दरअसल, आम लोगों को लगता है कि व्यंग्य लिखना आसान काम है, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं।

पोस्ट

जिस सरकार के शासन में ट्रेनी डाक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई हो, उसी की व्यवस्था की निगरानी में मामले पर पर्दा डालने का पूरा प्रयास किया गया हो, उसी के राज में साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश हुई हो, इसके बावजूद उसी सरकार की मुखिया ही इस मामले में धरना-प्रदर्शन करें तो इसे क्या कहा जाएगा।

अभिजीत अय्यर मित्रा@iyerwal

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वन नेशन-वन इलेक्शन की बात के अगले ही दिन हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव अलग-अलग कराने की घोषणा हुई है, जबकि 2009 से 2019 तक दोनों राज्यों के चुनाव साथ-साथ हुए हैं।

मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

बांग्लादेश में सेना द्वारा विदाई गई सरकार में चार नए सलाहकारों को शपथ दिलाई गई है। इनमें से एक सेवानिवृत्त तीन सितारा जनरल भी हैं, जो भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। वह सैन्य पृष्ठभूमि वाले दूसरे सलाहकार हैं।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

रमण शुक्ला
raman.shukla@pat.jagran.com

बिहार डायरी

सोशल इंजीनियरिंग साधने में उलझी भाजपा

सोशल इंजीनियरिंग का सर्वाधिक प्रयोग करने वाली भाजपा इस बार बिहार में राज्यसभा के लिए एक प्रत्याशी के चयन में उलझकर रह गई है। भाजपा को यह बिवशता वस्तुतः बिहार में जाति आधारित राजनीति पर निर्भरता का परिणाम है, जिसके ताने-बाने इधर के वर्षों में कुछ अधिक ही उलझ गए हैं। इसी कारण उसे कार्यकाल पूरा हुए बिना ही अपना प्रदेश अध्यक्ष तक बदलना पड़ा है। इसके बावजूद उसे वह सफलता नहीं मिली, जिसका स्वप्न केंद्रीय नेतृत्व 2015 में देख रहा था। इस बार भाजपा वैसी कोई चूक नहीं करना चाहती, जो उसके लिए फलदायी न हो। यही कारण है कि वह अभी तक राज्यसभा के लिए अपने प्रत्याशी का चयन तक नहीं कर पाई, जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के कारण राज्यसभा की दो सीटों पर उप चुनाव की नौबत आई है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, विशेषकर भाजपा के खाते में जा रहीं। उनमें से एक सीट के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का नाम लगभग तय है। पिछले दो चुनाव से लोकसभा पहुंचने में विफल रहे कुशवाहा बहुत पहले स्वयं अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके हैं। बाद में भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी उस पर सहमति जताई थी। चूंकि कुशवाहा पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए दूसरी सीट किसी अन्य जाति के खाते में जाएगी। प्रथम बरीयता अति पिछड़ा समाज है, जिसको पिछले कई अवसरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है। हालांकि, लोकसभा चुनाव में साथ निभाकर इस समाज ने उसका अच्छा प्रतिदान भी किया, लेकिन पिछड़ा-अति पिछड़ा समाज की तरह पर्याप्त अवसर व प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से दूसरी कई जातियां बिदक गईं।

बिहार प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की गत दिनों आयोजित एक बैठक के दौरान पार्टी के प्रमुख नेता। फाइल

अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और भाजपा आगे ऐसी कोई विषम स्थिति नहीं चाहती। विधानसभा की चार सीटों पर उप चुनाव भी होना है। ये चारों सीटें मगध और शाहाबाद परिक्षेत्र की हैं, जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रत्याशी के चयन में मगध और शाहाबाद को साधने का बड़ा दबाव है। संयोग से विवेक ठाकुर और मीसा भारती लोकसभा में मगध के अंश रहे क्रमशः नवादा और पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि वह वर्तमान जनाधार को कायम रखते हुए अपने लिए सामाजिक समीकरण का विस्तार करे। प्रत्याशी के चयन में ही रही देरी का यह एक बड़ा कारण है।

वस्तुतः सवर्णों के साथ होने से ही बिहार में भाजपा की संभावना है और पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग के सहयोग से उसकी आगे की राह खुलती है। बहरहाल हर वर्ग से कई दावेदार हैं और संगठन में उनका योगदान भी मूल्यवान रहा है, लेकिन केवल पिछली पृष्ठभूमि से ही आगे की राजनीति नहीं हो सकती। ऐसे में पार्टी अपने इस एक प्रत्याशी के माध्यम से उससे संबंधित समाज को साधने की मंशा रखती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण के नए कानून को निरस्त कर देने और अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर की प्रासंगिकता बताने के बाद जाति आधारित राजनीति की राह वैसे ही पेचीदा हो गई है। ऐसे में भाजपा यह कतई नहीं चाहेगी कि वह अपने किसी निर्णय से समाज विशेष में विरोधी दलों को माहौल बनाने का अवसर दे। दूसरी बात यह कि सर्वोच्च सदन में वह वैसे ही प्रतिनिधि को भेजना चाहती है, जो उसकी विचारधी कसौटी पर भी खरा हो। पिछले वर्ष राज्यसभा में उसे दो प्रतिनिधियों को भेजने का अवसर मिला। तब उसने अति पिछड़ा समाज से आने वाले भीम सिंह को अवसर दिया। बिहार सरकार में मंत्री के साथ संगठन में भी कामकाज का उन्हें ठीकठाक अनुभव था। वह अनुभव राज्यसभा में उनकी सक्रियता के रूप में दिख रहा है। बिहार सहित राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों को उन्होंने तथ्यपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संज्ञान में लाया है।

भाजपा चाह रही कि जिस प्रकार भीम सिंह ने अपने चयन की सार्थकता सिद्ध की है, उसका अगला प्रतिनिधि भी उसी प्रकार सदन में सक्रिय रहे। इसके अलावा संगठन के प्रति उसकी निष्ठा भी अक्षुण्ण होनी चाहिए। अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है। उसमें राज्यसभा के सदस्य की प्रत्यक्ष रूप से भले ही कोई भूमिका नहीं होती हो, लेकिन पदों के पीछे के कई दायित्वों के निर्वहन में भी सक्षम-समर्थ चेहरे की दरकार होती है। ऐसे में राज्यसभा के लिए प्रत्याशी के चयन की यह भी एक कसौटी है। इस कसौटी पर खरे उतरने वाले सवर्ण समाज के कुछ दावेदार संगठन में शीर्षस्थ नेताओं की पसंद से बाहर हो जा रहे। हालांकि, वे अभी निराश नहीं हुए हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या भारत को 2036 के ओलिंपिक खेलों के आयोजन की पहल करनी चाहिए?

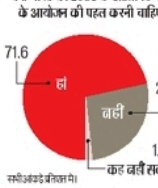

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या विपक्ष को धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का समर्थन करना चाहिए?

शनिवार जागरण हाइटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जम्मू औ कश्मीर में जम्हूरियत का रंग,
दुनिया आई पाइकार देखे अपरतन संग।
देखे अपरतन संग जंग का गया जमाना,
लिए तिरंगा हाथ गा रहे लोग तराना।
दस वर्षों के बाद तो वोटिंग का जश्न,
पाए अब सरकार नई कश्मीर औ जम्मू।

- ओमप्रकाश तिवारी

नई तकनीक

सुविधाएं बढ़ाने में सहायक

मानव के समक्ष आने वाली तमाम चुनौतियों के समाधान हेतु शोधकर्ता निरंतर प्रयासरत हैं। इस वर्ष कुछ ऐसी तकनीकें सामने आई हैं जिनसे निकट भविष्य में जनजीवन आसान हो सकता है

निरंकार सिंह
तकनीकी मामलों के जानकार

विश्व की समस्याओं को सुलझाने के साथ-साथ जनजीवन की सुविधाओं को बढ़ाने में नई तकनीकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भविष्य की तमाम चुनौतियों को भी हम नई तकनीक के माध्यम से सुलझा सकते हैं। विश्व के संबंधित विशेषज्ञों ने उनकी एक सूची तैयार की है। इनमें 10 प्रमुख नई तकनीकी उपलब्धियों को महत्वपूर्ण बताया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने दुनिया भर से 10 सबसे अच्छी तकनीक की छंटकर एक लिस्ट तैयार की है। वर्ष 2024 की 10 उभरती हुई तकनीक भविष्य में हमारी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगी।

विश्व आर्थिक मंच ने जिन 10 तकनीकों की सूची में शामिल किया है, उसमें बिजली का कम उपयोग करने के साथ पर्यावरण को ठंडा करने वाले इलास्टोकैलोरिक्स शामिल है। इसके अलावा सिंगल सेल वाले प्रोटीन से मक्वेशियों के लिए भोजन जैसी तकनीक का भी जिक्र किया गया है। उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) पहले नंबर पर है। वैसे तो एआइ का उपयोग कई वर्षों से शोधकार्यों के लिए किया जा रहा है।

तकनीकी शोध बीमारियों को समझने, नए मैटेरियल के बारे में आगे बढ़ने और मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाने में अहम योगदान दे सकता है। वहीं गोपनीयता के तरीकों को बेहतर करने की तकनीक के साथ ग्लोबल डाटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन के लिए नए मौके देते हुए पर्सनल प्राइवेसी को संभाले रखना गंभीर चुनौती है। सिंथेटिक डाटा हेल्थ संबंधी रिसर्च में पावरफुल एप्लिकेशन के साथ सूचना को संभालने के तरीके को बदलने के लिए तैयार है।

इंटेलिजेंट सरफेस : ये वाइरेलेस सरफेस आम दीवारों और सतहों को वायरलेस संचार के लिए इंटेलिजेंट कंपोनेंट में बदल देते हैं। इससे वायरलेस नेटवर्क में बिजली की खपत को भी कम किया जा सकता है। ये सरफेस स्मार्ट फैक्टरी से लेकर गाड़ियों के नेटवर्क तक में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से ऊंचाई पर स्थापित प्लेटफार्म से बैलून का इस्तेमाल करके ये सिस्टम दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बढ़ा सकते हैं। इससे दुनिया भर में ढाई अरब से अधिक लोगों के लिए डिजिटल खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। इस तकनीक की मदद से विश्व के अधिकतम हिस्से तक मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क को पहुंचाने में भरपूर मदद मिल सकती है।

इंटिग्रेटेड मेसिंग व कम्युनिकेशन : 6जी नेटवर्क के आने से एक साथ डाटा कलेक्शन (सेंसिंग) और ट्रांसमिशन (कम्युनिकेशन) की सुविधा मिलती है। यह पर्यावरण पर नजर रखने वाले सिस्टम को मजबूत बनाता है जो स्मार्ट कृषि, प्राकृतिक संरक्षण और शहरी नियोजन में मदद करते हैं। इंटिग्रेटेड सेंसिंग और कम्युनिकेशन डिवाइस बिजली और सिलिकान की खपत को भी कम करते हैं। कंप्यूटिंग पावर को बचुंबल और आगमेंटेड रियलिटी के साथ जोड़कर यह टेक्नोलाजी बुनियादी ढांचे और रोजमर्रा के कामकाज में तेजी से सुधार का दावा करती है।

इलास्टोकैलोरिक्स : जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता जा रह है, उसे ठंडा करने वाले तरीकों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। उच्च क्षमता युक्त और बिजली की कम खपत की पेशकश करते हुए इलास्टोकैलोरिक्स मैकेनिकल स्ट्रेस के तहत गर्मी को छोड़ते और सोखते हैं। आवश्यकता के अनुसार हीट पैंप करके और सिस्टम को ठंडा रखने की काबिलियत के साथ इलास्टोकैलोरिक्स वर्तमान तकनीक के लिए एक स्थायी समाधान पेश करते हैं। इसी क्रम में कार्बन सोखने वाले ऐसे माइक्रोब्स विज्ञानियों ने तैयार किए हैं जो कार्बन को सोखकर उन्हें बायोफ्यूल में परिवर्तित कर देते हैं। क्लाइमेट फ्रैंक से निपटने में यह टेक्नोलाजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कार्बन उत्सर्जन एक बड़ा कारण है। इसे नियंत्रित करने में कार्बन कैप्चर माइक्रोब्स नई उम्मीद बांधते हैं।

मवेशियों के लिए वैकल्पिक भोजन : मवेशियों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने भी एक बड़ी चुनौती है। समूचा विश्व जहां आज मनुष्यों को पोषण से भरपूर खाना उपलब्ध कराने में जुझ रहा है, ऐसे में सिंगल सेल प्रोटीन, शैवाल और फूड वेस्ट से पशुओं के लिए मिलने वाले प्रोटीन फीड कृषि आधारित उद्योगों के लिए बड़ा अवसर है। वहीं ट्रांसप्लांट के लिए जीनोमिक्स जैसी तकनीक जेनेटिक तौर पर तैयार अंगों का मानव में सफल रूप से प्रत्यारोपित करने में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी प्रगति को दर्शाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए यह तकनीक अंग उपलब्ध करा सकती है। उपरोक्त तकनीकों के उपयोग से नई चुनौतियों का सामना करते हुए आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है।

गर्मी को सोखने में काफी हद तक सक्षम साबित हो सकते हैं इलास्टोकैलोरिक्स। प्रतीकात्मक

****

दैनिक जागरण

चित्त को एकाग्र किए बिना लक्ष्य संधान संभव नहीं

गैर जिम्मेदार सरकार

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कालेज में हमले एवं तोड़फोड़ की घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए यह सही कहा कि यह शासन की पूर्ण विफलता है। इस मेडिकल कालेज में एक अराजक भीड़ ने उस समय घुसकर तोड़फोड़ की थी, जब वहां की प्रशिक्षु महिला डाक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा था, क्योंकि इस भयावह घटना की सही तरह जांच होती नहीं दिख रही थी। इसी कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी। ऐसा करते समय भी उसने राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की थी। इस आलोचना के लिए ममता बनर्जी सरकार अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि उसने घटना के बाद इस मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के त्यागपत्र के चार घंटे बाद ही उन्हें एक अन्य मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल बना दिया था और वह भी तब, जब पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने वाले दुष्कर्म एवं हत्या के इस मामले में उनकी भूमिका बहुत ही संदिग्ध थी। उन्होंने प्रशिक्षु महिला डाक्टर के माता-पिता को गलत जानकारी देकर गुमराह करने का काम तो किया ही था, उन्हें कई घंटे तक बेटी के शव के पास भी नहीं जाने दिया था। कोलकाता पुलिस का आचरण भी बहुत ही संदिग्ध रहा। उसने प्रिंसिपल से पूछताछ करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यह पहला ऐसा मामला नहीं, जिसमें अपराध की किसी गंभीर घटना पर ममता सरकार और बंगाल पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया हो।

हर कोई इससे परिचित है कि संदेशखाली की घटनाओं पर बंगाल पुलिस और ममता सरकार ने क्या रवैया अपनाया था। दोनों ने दोषियों का बचाव करने की हरसंभव कोशिश की थी और इसी कारण इस मामले की जांच भी सीबीआइ को सौंपनी पड़ी थी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामूहिक दुष्कर्म की एक अन्य घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता को ही दोषी ठहरा दिया था। समझना कठिन है कि ममता सरकार महिलाओं के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों में भी इतनी संवेदनहीनता क्यों दिखाती है? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की शाखा की तरह क्यों काम करती है? यह समझ आता है कि पुलिस पर राज्य सरकार का कुछ न कुछ दबाव होता ही है, लेकिन यह तो अकल्पनीय है कि किसी राज्य की पुलिस वहां के सत्तारूढ़ दल की इकाई की तरह से कार्य करने लगे। यदि बंगाल कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से बदहाल है तो इसके लिए एक बड़ी हद तक ममता सरकार और उसकी पुलिस ही उत्तरदायी है। यह विचित्र है कि आरजी कर मेडिकल कालेज की दिल दहलाने वाली घटना पर उचित कार्रवाई करने के स्थान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना-प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं।

पर्यटन विकास

उत्तराखंड में पर्यटक और तीर्थ यात्रियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार अब पर्यटन और तीर्थ स्थलों में सुविधाएं विकसित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है। इसके तहत राज्य में एक से पांच करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 33 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ रुपये तक की सब्सिडी समेत अन्य रियायत दी जाएगी। विशेष यह कि योजना केवल उत्तराखंड के निवासियों और यहां के उद्यमियों के लिए है। इससे भी बड़ी बात यह कि योजना के तहत जो भी उद्यम स्थापित होंगे, उनमें राज्य के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। देखा जाए तो उत्तराखंड की आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ऐसा किया जाना नितांत जरूरी था। यहां तीर्थ व पर्यटन स्थलों की बहुतायत है और इनसे व्यापक स्तर पर रोजगार भी सृजित हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा, जब इस दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए। हालांकि, बीते वर्षों में ऐसा हो नहीं पाया। हम न तो कोई तीर्थ सर्किट विकसित कर पाए, न उन पर्यटन स्थलों को ही पहचान दिला पाए, जो विशिष्टता में देश-दुनिया के पर्यटन स्थलों से किसी मायने में कम नहीं हैं। सुविधाओं की बात करें तो अभी तक हम शीतकालीन चारधाम यात्रा का भी मजबूत स्वरूप विकसित नहीं कर पाए। जबकि शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड की तस्वीर बदलने में सक्षम है। अब सरकार को उम्मीद है कि नई योजना से पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में न केवल बूम आएगा, बल्कि पलायन पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा। हां। सरकार को इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि योजना का उपयोग सिर्फ सब्सिडी हड़पने के लिए न हो, बल्कि वह सचमुच धरातल पर उतरे। इसके लिए पुराने अनुभवों से सबक लिए जाने की जरूरत है।

निरंतर टकराव वाली राजनीति

आशुतोष झा

यदि विपक्ष यह मानने को तैयार नहीं कि बहुमत वाली सरकार बन चुकी है तो सत्ता पक्ष स्वीकारने से बच रहा कि विपक्ष मजबूत होकर उभरा है

अवधेश राजपूत

लोकसभा चुनाव खत्म हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य पर अभी तक वही माहौल बरकरार है। चुनाव के बाद बहुमत की सरकार बन चुकी है। दो संसदीय सत्र निपट चुके हैं। नई सरकार का पहला बजट भी पारित हो गया, लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की शब्दावली बिल्कुल वैसी ही है, जैसी चुनाव के समय इस्तेमाल की जा रही थी। सत्तापक्ष का आरोप है कि विपक्ष देश में अराजकता फैलाना चाहता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम की भारत में पुनरावृत्ति की भी बात की। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए महीनों गुजर जाने के बाद भी विपक्षी नेताओं के हाथ से संविधान की वह प्रति छूट नहीं रही, जिसे लहराकर उन्होंने चुनाव में फर्जी नैरेटिव बनाया था कि भाजपा संविधान बदल देगी। विपक्षी नेताओं द्वारा जाति आधारित जनगणना का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। कुल मिलाकर, राजनीतिक दल चुनाव से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। मानसून सत्र में यह स्पष्ट दिखा, जो एक खतरनाक चलन है। खतरनाक इसलिए, क्योंकि जन्मत ने अगले पांच साल के लिए राजन काम करने के लिए चुना है और विपक्ष को मजबूती से अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए।

वैसे तो मौजूदा राजनीतिक माहौल के लिए चुनावी राजनीति भी जिम्मेदार है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से चुनावी मंच ऐसा होता है जहां आजादी का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। वहां नेता आरोप लगाकर चलते बन रहे हैं। वहां किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। इसके उलट संसद जिम्मेदारी और जवाबदेही का मंच होता है। संसद में वही टिकता है, जो तथ्यात्मक और वैचारिक स्तर पर मजबूत हो। सरकार के पास तो अपना एजेंडा होता है, लेकिन विपक्ष की यहां कड़ी परीक्षा होती है कि वह तर्कों और तथ्यों से कितना सबल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब संसद में संख्याबल के मोर्चे पर कमजोर होने के बावजूद विपक्ष सरकार को झुकने के लिए मजबूर करता रहा है, लेकिन अब दृश्य बदलने लगे हैं। सरकार गठन के बाद से दो महीने के भीतर जो दो सत्र हुए, उन्हें लेकर कहा जा सकता है कि तीन बड़े अवसर थे जहां विपक्ष अपना लोहा मनवा सकता था। पहला अवसर था-राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, दूसरा अवसर था बजट पर चर्चा का और तीसरा अवसर वक्फ संशोधन विधेयक। यह वह वक्त था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के दूसरे बड़े चेहरे अभिभाषण और बजट के लिखित दस्तावेज सामने रखकर यह गिनाते कि चुनावी मंच से उन्होंने जो आरोप लगाए थे, वे पुष्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा संभव नहीं था तो आंकड़ों के साथ बताते कि सरकार ने अब तक विकास का जो दावा किया है, वह कितना सही है या गलत और वे एक रोडमैप भी दिखाते। बजट को तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो की कापी बता रही थी। वह यह भी बताती कि इसके लिए राजस्व कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से अर्जित किया जा सकता है। राहुल गांधी यह भी बताते कि एमएसपी की संपूर्ण गारंटी के लिए उनके पास कैसा रोडमैप है और संभव था तो सरकार को इस मोर्चे पर मजबूर करते। दरअसल इसके जरिये राहुल यह साबित कर सकते थे कि वह अपनी क्षमता के आधार पर सरकार में आने के लिए तैयार हो चुके हैं न कि सिर्फ परिवार के आधार पर जैसा कि भाजपा की ओर से आरोप लगता है। वास्तविकता में उन्होंने किया क्या-प्रधानमंत्री समेत कई उद्योगपतियों के खिलाफ वही चुनावी आरोप मढ़े, जिन्हें जनता ने फिर से खारिज कर दिया।

यह एक सच्चाई है कि समूचा विपक्ष मिलकर उतनी सीटें नहीं जीत पाया जितनें अकेले भाजपा ने जीतीं। प्रधानमंत्री ने चुनाव में जाने से पहले 'एक अकेला सब पर भारी' की जो बात कही थी, वह एक हद तक सच हो गई। व्यक्तिगत आरोप के मामले में प्रत्यारोप होगा ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने आगे का सोच भी रखा। बजट सत्र की चर्चा अभिभाषण की चर्चा से आगे नहीं बढ़ पाई। जिस जनता ने वोट दिया है, वह जानना चाहती है कि किसी मुद्दे पर उसके नेता का सोच क्या है। वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विपक्ष के कई नेताओं ने विरोध किया। यह वह अवसर था, जब खासकर कांग्रेस को आगे बढ़कर मानना चाहिए था कि 2013 में जो हुआ, उसमें सुधार की जरूरत आ गई है। राहुल गांधी तो पहले भी मनमोहन सिंह कैबिनेट के निर्णय को फाड़कर यह बता चुके थे उनकी सरकार ने गलत फैसला लिया था। अपनी सरकार की पुरानी गलती को मानकर राहुल अपनी छवि को बिस्तार दे सकते थे। यह सकारात्मक भूमिका होती। अच्छी बात यह रही कि बहुत लंबे समय बाद बीते सत्र में कोई सदन पूरे दिन के लिए स्थगित नहीं रहा। हालांकि सदन की कार्यवाही केवल घंटों में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी आंकनी चाहिए। अफसोस की बात है कि सदन के अंदर परिपक्वता कम होती जा रही है। जिस तरह दोनों सदनों में सीधे तौर पर आसन पर सवाल खड़े किए गए, वह पहले कभी नहीं हुआ। सदन अखाड़ा बन गया है। सदन चला तो सही, लेकिन बांग्लादेश की अराजक स्थिति से भारत को जोड़ने के कुछ विपक्षी नेताओं के बयान, किसी फोगट के तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराए जाने के मुद्दे को राजनीतिक मोहरे की तरह उपयोग करने की कोशिश यही सोचने को मजबूर करती है कि विपक्षी दल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि बहुमत के गठबंधन की सरकार बन चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा घटित होगा कि उन्हें सरकार गठन का अवसर मिलेगा। इस तरह की राजनीति का असर इंटरनेट मीडिया पर भी दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवाओं की हिस्सेदारी है। वहां भी एक विषाक्त माहौल तैयार हो रहा है।

विपक्ष की इसका गुस्सा है कि सत्तापक्ष यह क्यों नहीं मान रहा कि वह चुनाव हार गया और सत्तापक्ष उनके आरोपों पर मुस्कुराने के बजाय हमलावर क्यों हो रहा है? दूसरी ओर सत्तापक्ष यह तो देख रहा है कि विपक्ष मजबूत होकर आया है, परंतु इसे स्वीकारने को तैयार नहीं। टकराव वाली राजनीति देश के लिए ठीक नहीं।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)

response@jagran.com

सुधार की राह तकते आश्रय गृह

डा. विशेष गुप्ता

आश्रय गृहों की अनदेखी के कारण उनमें अमानवीय घटनाओं का सिलसिला कायम है

अव्यवस्था का शिकार आशा किरण आश्रय गृह। प्रेट्र

दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित आशा किरण नामक आश्रय गृह में पिछले दिनों 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें आठ महिलाएं और पांच पुरुष थे। इस गृह में कुछ मृतक पांच साल तथा कुछ विगत दो दशक से रह रहे थे। यह आश्रय गृह दिल्ली सरकार के सामाजिक विभाग द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संचालित होता है। इसमें कुल रहने की क्षमता 250 लोगों की है, परंतु 980 लोग रह रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहीं रेखा शर्मा ने बताया कि इस गृह में आश्रय लेने वाले लोग अनेक बिना उचित भोजन एवं पानी के रह रहे थे। हालांकि दिल्ली प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, परंतु ऐसे मामलों में अतीत की जांच बताती है कि उनका परिणाम कुछ सुखद नहीं रहता। यही वजह है कि इस प्रकार के आश्रय गृहों की लगातार अनदेखी हो रही है। इससे इन गृहों में ऐसी अमानवीय घटनाओं का सिलसिला कायम है।

कहना न होगा कि यह केवल एक आश्रय गृह की दास्तां कथा है। दिल्ली में ऐसे करीब 200 गृह संचालित हैं, जो बेघर परिवारों, असहाय स्त्री-पुरुषों तथा नशे के शिकार लोगों के लिए आश्रित हैं। देश में आश्रय गृहों की संख्या 2,500 के आसपास हैं। इनमें लगभग 1,500 गृह सरकारी स्तर पर स्वीकृत हैं। शेष सामाजिक, धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। हैरत की बात है कि इन आश्रय गृहों में लाखों लोग आवश्रित तो हैं, परंतु जिन उद्देश्यों को लेकर इन गृहों की स्थापना की गई थी, उन पर अधिकांश खरे नहीं उतर पा रहे हैं। सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के बाद भी हजारों अनाथ और बेसहारा लोग आज भी सड़कों अथवा रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते दिखाई देते हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन आश्रय गृहों की स्थापना इसलिए की गई थी, ताकि बेघर हुए परिवारों, परित्यक्त महिलाओं, पुरुषों, अनाथ शिशुओं एवं किशोरों तथा बुद्धजनों को आपात स्थिति में वहां रहने के लिए एक अस्थायी घर और जरूरत का सामान तथा एक सुरक्षित एवं स्वच्छ परिवेश उपलब्ध कराया जा सके। देश में शिशु से लेकर बुद्धजनों तक उनकी प्रकृति के अनुसार अलग-अलग प्रकार के आश्रय गृह हैं। इनमें अनाथ अथवा सड़क एवं झाड़ियों में फेंके गए नवजात शिशुओं के लिए शिशु सदन, अनाथ एवं बेसहारा अथवा घरों से पलायन किए हुए दस साल से अधिक उम्र के किशोर अथवा किशोरियों के लिए किशोर एवं किशोरी गृह, बेसहारा अथवा पारिवारिक हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए नारी निकेतन तथा बुद्धजनों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह इत्यादि प्रमुख हैं। देश के प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने वाले किशोरों के लिए किशोर संप्रेक्षण गृह हैं।

इनके अतिरिक्त मंदबुद्धि अथवा दिव्यांगता से जुड़े कुछ आश्रय गृह भी सरकारी अनुदान से संचालित किए जाते हैं। शेष काफी संख्या में महिला एवं बुद्धजनों से जुड़े आश्रय गृह ट्रस्ट एवं चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा भी संचालित किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रविधान है कि सरकार अपने नागरिकों को आश्रय उपलब्ध कराए, ताकि देश के नागरिक गरिमापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए सरकार का सामाजिक कल्याण मंत्रालय अनुदान भी उपलब्ध कराता है, लेकिन कई बार इसके संचालकों की गिद्धदृष्टि इन आश्रय गृहों को बदहाल कर देती है, जिस कारण इन गृहों में रहने वाले लोग उपेक्षा, अव्यवस्था और बीमारियों का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। इससे इनमें एक अच्छे नगरिक बनने की संकल्पना कमजोर हो जाती है। इससे सरकार एवं समाज की साख को चोट पहुंच रही है। समाज के विखंडन ने भी इसमें अपनी खास भूमिका अदा की है। किशोर-किशोरियों, परिवारिक हिंसा से ग्रस्त महिलाओं एवं सामाजिक संबंधों में शक के दायरे का विस्तार तथा अपराधी बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि ने इन गृहों की सीमित संख्या को ध्वस्त कर दिया है। लिहाजा ये सभी गृह अतिरिक्त बोझ की मार झेल रहे हैं। इसका दुष्परिणाम यह है कि इनमें से अधिकांश गृहों का आंतरिक ढांचा चरमरा गया है। कहीं-कहीं तो किशोर-किशोरियों के ये गृह उनके पलायन करने के साथ यौन व्यभिचार के केंद्र तक बनते देखे गए हैं।

राम का सद्चरित्र, कृष्ण की दूरदर्शिता, सीता के त्याग, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, स्वामी विवेकानंद का पांडित्य एवं श्रवण कुमार की मातृ-पितृ भक्ति जैसे गुण अब भारतीय परिवारों से दूर हो चले हैं। परिवार, पारिवारिक मूल्य, नैतिकता एवं उनकी उपादेयता पर कुतर्क हावी हैं। इससे रिश्तों की टूटन एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो चली है। सरकार के साथ समाज की यह अपेक्षा रही है कि समाज के सभी अंग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ समाज में एक अच्छे नगरिक की भूमिका में रहेंगे, मगर सदैव ऐसा नहीं हो पाता। कई बार समाज में बिखरते और टूटते परिवार और सामाजिक परिवर्तन की तेज आंधी पारिवारिक रिश्तों को तो तोड़ती है, साथ में परिवार से जुड़े बच्चों, किशोर-किशोरियों, स्त्री-पुरुषों तक को पलायन को मजबूर कर देती है। ऐसे में अगर आश्रय गृह न हों तो समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक व्याधियों का प्रवाह बढ़ेगा। निश्चित ही ऐसे लोगों की तमाम विषम व्याधियों से बचाने के लिए ये आश्रय गृह इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन आश्रय गृहों के अंदरूनी ढांचे को संतुलित बनाने के लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्यों की सरकारें मिलकर आवश्यक कदम उठाएं। तभी इन गृहों में रहने वाले लक्षित समूहों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। ऐसा करके ही इन गृहों में रहने वालों को मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।

(लेखक समाजशास्त्र के पूर्व प्रोफेसर एवं उप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

स्वतंत्र चिंतन

स्वतंत्र चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को नाना प्रकार के बंधनों से परे ले जाकर स्वतंत्र रूप से सोचने-विचारने की क्षमता प्रदान करती है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल अपनी सोच में नवीनता और रचनात्मकता लाने में मदद करता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनता है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों के विचारों को सुनना और सहन करना है, भले ही वे हमें प्रिय न लें।' यह विचार बताता है कि स्वतंत्र चिंतन का आधार सहिष्णुता और विविधता का सम्मान है।

जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोचता है तो वह विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया उसे एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, जो उसके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपनी आस्था, परंपरा और मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसता है। ऐसा चिंतन व्यक्ति को उन विचारों से मुक्त करता है जो उसे अंधविश्वास, कट्टरता और संकीर्णता में जकड़े रखते हैं। स्वतंत्र चिंतन का अभ्यास व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है, जो भावी चुनौतियों का सामना करने में उसकी तैयारी को निखारता है।

जब समाज के सदस्य स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, तो वे नवीन विचारों को जन्म देते हैं जो समाज के विकास में योगदान करते हैं। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करती है, जहां हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होता है। स्वतंत्र चिंतन के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अनुशासनहीन या अराजक बन जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने सोच में ईमानदारी और तर्कशीलता को बनाए रखें। स्वतंत्र चिंतन एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाती है, बशर्ते इसका सही दिशा में उपयोग किया जाए।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

अनेक ब्रह्मांड की संभावना को बल

प्रदीप

ब्रह्मांड के रहस्य हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहे हैं। ब्रह्मांड की सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक यह है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है या हमारे ब्रह्मांड जैसे अन्य ब्रह्मांडों (मल्टीवर्स) का भी अस्तित्व है? मल्टीवर्स की अवधारणा लंबे समय से टीवी सीरियलों और साइंस फिक्शन फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय कथानक रही है। हमारे ब्रह्मांड के रहस्यमय विस्तार को समझने के क्रम में हाल ही में आइआइटी के एक पीएचडी छात्र ने 'ग्रैविटेशन एंड कास्मोलाजी एंड यूरोफिजिक्स लेटर्स' में प्रकाशित अपने शोधपत्रों में जुड़वा ब्रह्मांड की अवधारणा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है।

इस शोध का मानना है कि बिग बैंग के दौरान पदार्थ के हर कण के निर्माण के साथ प्रति-पदार्थ (एंटीमैटर) का एक संगत कण भी बना और इनका एक साथ निर्माण यह बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के साथ-साथ एक प्रति-ब्रह्मांड (एंटी-यूनिवर्स) भी अस्तित्व में आया।

एक हालिया शोध से एक बार फिर यह संभावना जगी है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह अनेक ऐसे और भी हो सकते हैं

एक से अधिक ब्रह्मांड होने की बात सबसे पहले अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने 1895 में कही। उन्होंने इसके लिए 'मल्टीवर्स' शब्द का उपयोग किया, परंतु आज की अनेक ब्रह्मांड की संकल्पना जेम्स की कल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। आज अनेक ब्रह्मांड होने की संकल्पना आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के दो अनसुलझे सवालों के जवाब देती प्रतीत होती है- पहला यह कि बिग बैंग से पहले क्या था? दूसरा यह कि भौतिकी के नियम ऐसे ही क्यों हैं, जैसे कि हम जानते हैं? पहले का उत्तर है कि इसके अनुसार असीमित बार बिग बैंग हुआ होगा, जिससे नया ब्रह्मांड पैदा हुआ होगा। तथा इसलिए (दूसरे का जवाब) भौतिकी के नियमों की असीमित संभावनाएं बनी होंगी, और हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के ये नियम असीमित नियमों में से एक हैं। अगर हम मान लें कि वास्तव में ऐसे ब्रह्मांडों का अस्तित्व है तो हो सकता है कि वहां पर जीवन भी हो।

आधुनिक वैज्ञानियों ने अनेक ब्रह्मांड होने की संभावना को लेकर कई तरह के सिद्धांत विकसित किए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत 'समानांतर ब्रह्मांड' का है। इसका विचार पहली बार 1954 में प्रिंस्टन विश्वविद्यालय के एक रिसर्च स्कालर हुग एवेरेट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड की ही तरह दूसरे कई समानांतर ब्रह्मांड हो सकते हैं और वे सभी हमारे ब्रह्मांड से संबंधित हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी का गणित भी यह सुझाव देता प्रतीत होता है कि अपने अलग-अलग ब्रह्मांडों में किसी भी स्थिति के सभी संभव परिणाम होते हैं। हालिया शोध से मल्टीवर्स की अवधारणा दौबारा चर्चा में आ गई है। निश्चित रूप से यह शोध इस विचार को कल्पना के दायरे से वैज्ञानिक क्षेत्र में लाने का एक उल्लेखनीय प्रयास है। **(लेखक विज्ञान संचारक हैं)**

मेलबाक्स

बड़े परिवर्तनों की प्रतीक्षा में भारत

शुक्रवार यानी 16 अगस्त के अंक में प्रकाशित स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण से संबंधित समाचार और संपादकीय उत्साहवर्धक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वर्तमान कार्यकाल में बड़े बदलावों की ओर संकेत दिया है। समान नागरिकता कानून और एक देश एक चुनाव के साथ-साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत देश में चुनावों में एक तिहाई नारीशक्ति की भागीदारी देश को नई दिशा प्रदान करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि राजनीति में वे युवा सम्मिलित हों, जिनके परिवार राजनीति से बाहर रहे हों, राजनीतिक पटल पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में केवल कुछ परिवारों का ही वर्चस्व है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि शिक्षित युवा, किसान, वैज्ञानिक, डाक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, उद्यमी आदि राजनीति में आएं, जो राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकें। समान नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को एक आधिकारिक विस्तृत प्रस्तोतरी पत्र सरकारी घोषणा के साथ लाना चाहिए, जिसमे समाज के सभी वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यक, आरक्षित और वनवासी समाज की सभी आशंकाओं का स्पष्टीकरण और समाधान हो। वर्तमान परिदृश्य में विपक्षी समझ नहीं पा रहे कि विरोध किसका करना है, संसद में करना है या सड़क पर, भारत विरोधी विदेशी शक्तियों के इशारों पर खेलना है या उन विदेशी शक्तियों को ही सरकार का विरोध आउटसोर्स कर देना है? जनता भी चाहती है कि अब भारत में बड़े बदलाव हों और भारत का महाशक्ति के रूप में उद्भव हो।

विनोद जौहरी, दिल्ली

लोकतंत्र की मजबूती के प्रयास

गिरीश्वर मिश्र ने 'सुगम हो राष्ट्र निर्माण का पथ' आलेख में समाज व राजनीति की जिस सच्चाई से अवगत कराया है, वह समाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित आमजन के लिए गौर करने लायक है। राजनीति में प्रवेश करने वालों ने इसे व्यवसाय बना लिया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाइयां होती हैं, मगर इनकी वजह से जो भय कायम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपराध सिद्ध करने में इतने बरस लग लग जाते हैं कि सजा का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर भी हमारा लोकतंत्र मजबूत है तो इसलिए कि इसमें लोगों का विश्वास कायम है। लेकिन हमें सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहने होंगे।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस सभा में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण साफ्र अभिमति हों। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

स्वतंत्रता दिवस

अब तक की यात्रा

भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस गर्व से मना रहा है। यह समय अब तक की यात्रा पर विचार करने का है। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के समय माहौल गर्व, स्मृतियों एवं उम्मीदों से भरा है। यह दिवस केवल औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का नहीं, बल्कि देश की अब तक की गई यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम जहां खड़े हैं, वह विजयों व चुनौतियों से भरे 'रोलर कोस्टर' जैसा है। एक राष्ट्र के रूप में हम अपनी उपलब्धियों पर गौर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी नजरें भविष्य की ओर रख कर आगे के रास्ते का अनुमान लगाना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की यात्रा दृढ़ता और विकास की उल्लेखनीय यात्रा है। 'विभाजन की विभीषिका' और औपनिवेशिक शोषण के बोझ से उबर कर राष्ट्र एकता और प्रतिबद्धता की भावना से ऊपर उठा। शुरुआत के वर्ष चुनौतियों से भरे थे जिनमें आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक उथलपुथल तथा राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य शामिल थे। इसके बावजूद भारत मजबूत बना रहा। 'हरित क्रांति' ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर देश में बदला, जबकि 'श्वेत क्रांति' ने देश को दुनिया में सबसे बड़ा दुध उत्पादक बना दिया। भारत ने अंतरिक्ष की खोज में तेजी से कदम बढ़ाए और वह चंद्रमा तक पहुंच गया। राष्ट्र ने अपना मजबूत औद्योगिक आधार भी बनाया। लेकिन यह रास्ता हमेशा सरल नहीं था। भारत को युद्धों, राजनीतिक उथलपुथल तथा आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक में आपातकाल का समय एक अंधेरा अध्याय था जिसने लोकतंत्र की दृढ़ता की परीक्षा ली। 1991 में आर्थिक उदारीकरण एक परिवर्तनकारी मोड़ था जिसने भारत को विश्व मंच पर पहुंचा दिया, लेकिन इसने असमानता और सामाजिक विसंगतियों के रूप में नई चुनौतियां भी पैदा कीं। नई सहस्राब्दी में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में लंबी छलांग लगाई। 'आईटी क्रांति' ने देश को वैश्विक तकनीक केन्द्र में बदल दिया, जबकि अंतरिक्ष की खोज तथा नाभिकीय तकनीक के क्षेत्र में प्रगति ने भारत की वैज्ञानिक शक्ति प्रदर्शित की। शिक्षा, स्वास्थ्यरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर जोर देने से सामाजिक प्रगति को महत्वपूर्ण स्थान मिला।

शिक्षा अधिकार कानून तथा धारा 377 को आपराधिकता से मुक्त करने जैसे उल्लेखनीय विधायनों ने सामाजिक न्याय के प्रति देश की प्रतिबद्धता प्रकट की। लेकिन अब भी चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, पर्यावरणीय चिन्ताओं तथा समावेशन के लिए संघर्ष देश को याद दिलाते हैं कि उसकी यात्रा अभी जारी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की हालिया चुनौती ने जोखिमों को उजागर करने के साथ ही भारत की दृढ़ता भी रेखांकित की। इससे देश वैक्सीन उत्पादन और वितरण में विश्व का नेता बन कर उभरा। आज राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। देश को पर्यावरण क्षरण का मुकाबला करते हुए आर्थिक वृद्धि को टिकाऊ व समावेशी बनाना सुनिश्चित करना है। इसमें भारत के नौजवान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे जो जनसंख्या संरचना के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा समूह हैं। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और पंथनिरपेक्ष संरचना पर डटे रहना होगा। स्वतंत्रता दिवस पर हवा में फहराने वाले तिरंगे हमें याद दिलाते हैं कि हमने लाखों लोगों के बलिदानों और प्रयासों से बहुत कुछ प्राप्त किया है। इससे हम अपना देश बनाने में सफल हुए हैं और आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद संभावनाओं से भरा है। दुनिया की सर्वाधिक 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश भारत अब एकजुट होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह दुनिया के लिए अवश्य आदर्श बनेगा। जय हिंद।

बांग्लादेश में जारी उथलपुथल

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथलपुथल का प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनय पर पड़ना अवश्यंभावी है। नई दिल्ली ने सीमा पर निगरानी तेज की है।

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

बांगलादेश में वर्तमान समय में जारी राजनीतिक उथलपुथल का प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनय पर पड़ना अवश्यंभावी है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से नई दिल्ली ने सीमा पर निगरानी तेज की है। लगभग एक सप्ताह पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अपना देश छोड़ दिया। इससे उनके देश तथा पूरे क्षेत्र में चिन्ता पैदा हो गई है। 'बीबीसी' के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों के बजाय शेख हसीना के परिवार ने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उनको देश छोड़ने के लिए मनाया। हसीना के बेटे ने कहा, 'हमने उनको मनाया कि हिंसक भीड़ के पहुंचने से पहले वे देश छोड़ दें।' शेख हसीना के देश छोड़ने के फौरन बाद हिंसक भीड़ ने उनके आवास पर धावा बोल दिया था। बांग्लादेश में इस उथलपुथल के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक कारण थे। उथलपुथल में बाहरी शक्तियों के शामिल होने तथा शेख हसीना से नाराज राजनीतिक विरोधियों की संलिप्तता ने उनका तख्ता उलटने का माहौल तैयार कर दिया था।

बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में देश की संसद को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया कि उनके भारत आने से बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर संभवतः प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश में पैदा राजनीतिक उथलपुथल और हिंसा में लगभग 560 लोगों की जानें गईं। इससे पैदा अशांति के कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़ कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हालांकि, शेख हसीना के भारत में शरण लेने से दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हो सकते हैं और संभवतः इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा और विदेश संबंधों पर भी पड़ेगा। 15 साल लंबे अपने शासनकाल के प्रारंभ में शेख हसीना को बांग्लादेश के एक लोकतांत्रिक व सेक्यूलर नेता के रूप में देखा जाता था। उन्होंने बांग्लादेश की तेज आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर उसकी किस्मत बदल दी थी। लेकिन बाद में वे असहिष्णु हो गई थीं तथा उनमें तानाशाही प्रवृत्तियां दिखने लगी थीं। उन्होंने मीडिया में अपने आलोचकों पर हमला बोला था तथा अनेक राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद कर दिया था। हालांकि, इस दौरान उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ हार्दिक संबंध बनाए रखे थे। इसके कारण बांग्लादेशी जनता के एक हिस्से में भारत-विरोधी भावनायें भी जोर पकड़ रही थीं।

भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों की निकटता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया था कि पिछले साल उनकी शेख हसीना से दस बार मुलाकात हुई थी। भारत-बांग्लादेश मैत्री परस्पर लाभदायक थी। शेख हसीना ने भारत से मैत्री का ध्यान रखते हुए भारत पर निशाना लगाने वाले आतंकियों को अपने देश से भगा दिया था तथा उनमें से अनेक को पकड़ कर भारत के हवाले कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने भारत को पारगमन सुविधायें भी दी थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव जीत कर तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद वे भारत आने वाली पहली राजकीय अतिथि थीं।

1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के बीच विशेष संबंध बने हुए थे। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या के बाद शेख हसीना भारत में 6 साल रही थीं। इसके बाद वे अवामी लीग का नेतृत्व करने ढाका चली गईं। 5 जुलाई को बांग्लादेश में शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन स्वतंत्रता संग्राम के वारिसों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का विरोधी था। इसको मिला कर बांग्लादेश में 56 प्रतिशत सरकारी पद आरक्षण के दायरे में आ गए थे। इसका बांग्लादेश की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। शेख हसीना सरकार द्वारा इस आरक्षण के कारण देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसमें हिंसा के चलते 200 लोग मारे गए थे। हालांकि, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को बहुत घटा दिया था, लेकिन तब तक माहौल बिगड़ गया था। बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बढ़ते असंतोष को अभिव्यक्त करने के लिए 'लांग मार्च' का आयोजन किया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शेख हसीना और अमेरिका के बीच तनाव उस समय बढ़ गया, जब उनके देश छोड़ने के बाद अमेरिका ने उनका वीसा रद्द कर दिया।

अमेरिकन विदेश विभाग ने बांग्लादेश में दीर्घकालीन शांति एवं राजनीतिक स्थायित्व बनाने के लिए 'अंतरिम सरकार' गठन के महत्व पर जोर दिया था। ब्रिटेन तथा पश्चिम के कई अन्य देशों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा है जो सामान्य स्थिति बहाल करने की जिम्मेदार है। नई दिल्ली ने एक निगरानी समिति का गठन करने के साथ स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर नियंत्रण बढ़ा दिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बेगम खालिदा जिया तथा अन्य विपक्षी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। खालिदा जिया के दो कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंध कमजोर हुए थे। उनकी दिल्ली यात्रा का कोई नतीजा नहीं निकला था। खालिदा जिया की रिहाई के बाद उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। बेगम जिया ने लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ ही शांति और एकता पर जोर दिया है। शेख हसीना और खालिदा जिया के बेटे अपनी पार्टियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इन दोनों तथा अन्य विपक्षी नेताओं की संभावित वापसी के बाद बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आ सकता है।

शेख हसीना के बेटे के अनुसार वे किसी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें अभी पार्टी का नेतृत्व करने के बारे में तय करना है। इस बीच शेख हसीना ने तख्तापलट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उनके बेटे ने दावा हिया है कि शेख हसीना को इस्तीफा देने का समय नहीं मिला और वे अब भी प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेशियों ने व्हाइट हाउस के सामने और ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन किये हैं। नई दिल्ली पूरी स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है। उसे खासकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ ही सीमा और क्षेत्रीय सुरक्षा की चिन्ता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्ता है। अपने खिलाफ अत्याचारों के विरोध में हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में अनेक हिंदुओं की हत्या की गई, उनके बिजनेस संस्थानों को निशाना बनाया गया तथा हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के आश्वासन के बावजूद हिंदू-विरोधी हिंसा जारी है। प्रगति कर रही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से गिर रही थी। इसका कारण शेख हसीना के कठोर नीतियों, हिंसा, बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति को बताया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं तथा ढांचागत संरचना के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। ऐसे में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भारत को अपनी 'बांग्लादेश नीति' पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा भी चिन्ता का विषय है जहां से आना जाना बहुत आसान है। भारत ने आरोप लगाया है कि ऐसी सीमा के कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आ जाते हैं। भारत की मित्र शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने घुसपैठियों के भारत में प्रवेश की समस्या से निपटने के प्रयास किए थे। लेकिन इसके एकमद उलट बांग्लादेश में लगभग दस साल चली बेगम खालिदा जिया की सरकार ने इस समस्या से ही इनकार कर दिया था।

बांग्लादेश में जारी उथलपुथल को देखते हुए नई दिल्ली ने 'देखो और प्रतीक्षा करो' की रणनीति अपनाई है। यह एक सकारात्मक कदम है। बांग्लादेश में अब स्थिति चुनावों के समय और बेगम खालिदा जिया तथा शेख हसीना की पार्टियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। यदि बांग्लादेश में चुनाव के बाद नया नेतृत्व उभरता है तो नई दिल्ली को अपना दृष्टिकोण तय करना होगा। क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वह बांग्लादेश को सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायक हो सकता है।

शांतिपूर्ण, स्थिर व समृद्ध बांग्लादेश भारत के हित में है। भारत को इसे सुनिश्चित करने के सारे कदम उठाने चाहिए। स्थिति अभी बदल रही है और भविष्य अनिश्चित है। चुनावों की घोषणा के बाद बांग्लादेश में स्थिति स्पष्ट होगी। बेगम जिया और शेख हसीना की योजनायें अभी सामने आनी हैं, लेकिन 'वंशवादी' शासनों की संभावित वापसी स्थिति को जटिल बनाए रखेगी।

कार्य वातावरण में खेलों को जोड़ना जरूरी

> कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके, कंपनियां भी स्वस्थ और अधिक लचीले कार्यबल में योगदान दे सकती हैं।

साक्षी सेठी
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

समकालीन कार्य वातावरण में, जहां तनाव, गतिहीन जीवनशैली और उच्च मांगें आम हैं, कार्यस्थल में खेल गतिविधियों को शामिल करना बहुत जरूरी हो गया है। पारंपरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से परे, खेल अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं जो कर्मचारी कल्याण को बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। कार्यस्थल में खेल गतिविधियों को शुरू करने के सबसे सम्मोहक कारणों में से एक कर्मचारी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर उनका सकारात्मक प्रभाव है। आज, कई आधुनिक नौकरियों में लंबे समय तक बैठना शामिल है, जिससे मोटापा, हृदय संबंधी समस्याएँ और मस्कुलोस्केलेटल विकार जैसी समस्याएँ होती हैं। खेलों में नियमित भागीदारी शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देकर, मुद्रा में सुधार करके और पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करके इन प्रभावों का प्रतिकार कर सकती है। इसके अलावा, खेल गतिविधियां एक प्राकृतिक तनाव निवारक के रूप में काम करती हैं। कार्यस्थल में खेल गतिविधियों पर विभिन्न अध्ययनों और शोधों ने लगातार कर्मचारी कल्याण, उत्पादकता और समग्र संगठनात्मक संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। शोध यह भी सुझाव देता है कि शारीरिक गतिविधि पुरानी बीमारियों, जैसे हृदय रोग और मोटापे के जोखिम को कम करती है, जो अक्सर गतिहीन कार्य वातावरण से बढ़ जाती हैं। शारीरिक व्यायाम करने से एंडोर्फिन निकलता है, जो तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है।

कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके, कंपनियां भी स्वस्थ और अधिक लचीले कार्यबल में योगदान दे सकती हैं, जिससे अनुपस्थिति कम होगी और समग्र मनोबल में सुधार होगा। कार्यस्थल में खेल गतिविधियों के लाभ व्यक्तिगत कल्याण से कहीं आगे बढ़कर संगठन की समग्र सफलता तक पहुंचते हैं। एक स्वस्थ, व्यस्त और प्रेरित कार्यबल कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्यों में सकारात्मक रूप से योगदान करने की अधिक संभावना रखता है। खेल कंपनी की छवि को बढ़ा सकते हैं, इसे संभावित कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए एक आकर्षक स्थान बना सकते हैं और कर्मचारी प्रतिधारण में सुधार कर सकते हैं। खेल गतिविधियों में निवेश करने वाली कंपनियों को अधिक सकारात्मक कार्य वातावरण देखने की संभावना है। इसके अलावा, जो कंपनियां खेल और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देती हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवा लागत में कमी, कम टर्नओवर दर और कर्मचारी संतुष्टि के उच्च स्तर का अनुभव होने की संभावना है। ये कारक अधिक सकारात्मक कार्य वातावरण में योगदान करते हैं, जहाँ कर्मचारी मूल्यवान और समर्थित महसूस करते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खेल समाज में एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, जो विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को एक साथ लाते हैं। चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर, खेल आयोजन समुदाय और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय खेल टीमें अक्सर एकता के प्रतीक के रूप में काम करती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों, जातीयताओं और सामाजिक वर्गों के नागरिकों को अपने देश का समर्थन करने के लिए एक साथ लाती हैं। इसके अतिरिक्त, खेल सांस्कृतिक अंतर को पाट सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय समझ और शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसा कि ओलंपिक जैसे आयोजनों में देखा जाता है।

वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य, चरित्र विकास, सामाजिक एकीकरण और आर्थिक विकास में योगदान देता है। व्यक्तियों और समुदायों को आकार देने में खेलों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। जैसे-जैसे समाज विकसित होता रहेगा, खेलों का महत्व बढ़ता जाएगा, जिससे एकता को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे।

कार्यस्थल में खेल गतिविधियों की आवश्यकता स्पष्ट है। वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर, टीम निर्माण और सहयोग को बढ़ावा देकर, जुड़ाव और प्रेरणा को बढ़ावा देकर और समग्र संगठनात्मक सफलता में योगदान देकर कर्मचारी कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

जैसे-जैसे कंपनियां आधुनिक कार्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करना जारी रखती हैं, उनके कल्याण कार्यक्रमों में खेलों को शामिल करने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं, जिससे एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक उत्पादक कार्यबल बन सकता है। खेल गतिविधियों में निवेश करके, संगठन एक सकारात्मक और गतिशील कार्य संस्कृति बना सकते हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता दोनों को समर्थन देती है।

आप की बात

विधानसभा चुनाव

इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा हैं। लोकसभा चुनाव में इन चारों राज्यों में इंडिया ब्लॉक ने शानदार सफलता प्राप्त की है जबकि भाजपा 2019 का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई है। हरियाणा में किसान आंदोलन और अग्निवीर बड़े मुद्दे रहेंगे, जबकि झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हेमंत सोरेन को पुनः सत्ता मिलने के कारण भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ी चुनौती नहीं मिलेगी क्योंकि जनता 370 के खिलाफखड़ी दिखाई देती है और आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा चुनावी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा जहां पर सभी राजनीतिक दल दो गठबंधनों में बट जाएंगे। यह बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी द्वारा पेश चुनौती का सामना स्थानीय नेताओं द्वारा किया जाएगा। मराठा आरक्षण एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान सरकार के लिए इससे पार पाना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। यदि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी-एमवीए का और विस्तार कर इसमें सपा समेत अन्य विपक्षी दलों को शामिल किया जाता है तो फिर पूरी लड़ाई परोक्ष रूप से विपक्ष बनाम भाजपा में बदल जाएगी। ऐसी संभावना के दुरगामी परिणाम 2029 के लोकसभा चुनाव तक जा सकते हैं।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

कोलकाता की निर्भया

कोलकाता में महिला जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर अस्पतालों में नाइट ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के समक्ष आने वाले खतरों को उजागर कर दिया है। विडंबना है कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून मौजूद होने के बावजूद थोड़े-थोड़े अंतराल के निर्भया कांड की पुनरावृत्ति होती रहती है। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी को पुलिस घटनास्थल से सबूत मिटाने के प्रयास कर रही है। कोलकाता में निर्भया कांड का विरोध कर रही डाक्टरों पर रात में अराजक तत्वों द्वारा किया जाने वाला हमला, उनके द्वारा वार्ड में की गई तोड़फोड़ तथा पुलिस उच्चाधिकारी द्वारा पूरे मामले पर लीपापोती का प्रयास करते हुए उल्टे मीडिया पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास अत्यन्त निंदनीय है। ममता बनर्जी इसके पहले भी अनेक मामलों में दोषी अधिकारियों का बेशर्मी से बचाव करते दिखी हैं। इसके कारण एक समय पूरे देश ही नहीं, दुनिया भर में सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संगीत व कला का केन्द्र माना जाने वाला बंगाल आज लगातार अपनी गरिमा खोते हुए गुंडाराज में बदलता जा रहा है।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद

स्वतंत्रता का अर्थ

स्वतंत्रता का मतलब केवल गुलामी से आजाद होना बिलकुल नहीं है, वरन इसका अर्थ स्वेच्छा एवं स्वाभिमान व आत्मसम्मान से अपना जीवन जीना, हीन मानसिकता से मुक्ति, समानता व समरसता का अधिकार, शोषण व अत्याचार से आजादी, कुविचारों और रूढ़िवादी परंपराओं को तिलांजलि, अपनों से बड़ों का सम्मान, अनुजों से स्नेह और विचारों की अभिव्यक्ति है। सबको अपनी इच्छा से जीवन जीने का संवैधानिक व मौलिक अधिकार है। जब नारी न घर में सुरक्षित है और न ही बाहर तो ऐसी स्वतंत्रता किस काम की। सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सरकार को गंभीरतापूर्व विचार कर कानून में बदलाव लाने चाहिए। इनका जमीनी स्तर पर त्वरित क्रियान्वयन भी उतना ही जरूरी होगा। आज असहिष्णु जीवन और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने हमें गुलाम बना दिया है। सच्ची आजादी का अर्थ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैयक्तिक, दैहिक, शैक्षिक आध्यात्मिक, वैचारिक और सात्विक स्वतंत्रता है। यदि हम हीनभाव और दुराचार से बाहर नहीं आएंगे तो यह माना जाएगा कि हम परतंत्र है। मन के कुविकारों पर संयम का अंकुश ही सही अर्थों में आजादी है। इसे आदर्श बनाना चाहिए।

- नलिन खोड़ेवाल, इंदौर

जमानत की व्यवस्था

जेल में बंद कैदियों के लिए जमानत को लेकर सर्वोच्च न्यायलय का संदेश स्पष्ट है। मगर देखने में आता है कि अनेक कारणों से पुलिस प्रशासन किसी भी आरोपी को जमानत न मिलने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। देश की जेलों में कुछ विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा चार्जशीट ही पेश नहीं की जाती है तो कई मामलों में मुकदमों के अंबार के नीचे उनकी जमानत की अर्जी दब कर रह जाती है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे-मोटे अपराधों के आरोपी गरीब व निरक्षर लोगों को उठाना पड़ता है। बड़े नेताओं की तरह आम आदमी तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। पैरोल व्यवस्था भी भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत बन गई है। राम रहीम जैसे पावरफुल लोगों को जल्दी-जल्दी पैरोल मिल जाती है। ऐसे देखते हुए न्याय व्यवस्था में बड़े परिवर्तन की जरूरत है। किसी भी आरोप में तीन माह तक सुनवाई न होने पर स्वतः जमानत का प्रावधान होना चाहिए। छोटे-मोटे अपराधों में जेल की सजा के बजाय त्वरित अर्थदंड की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे राजस्व वसूले की तरह वसूल किया जाए।

-सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते हैं।

हिन्दुस्तान
1936

जनादेश का समय

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के साथ ही हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर सियासी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही खासकर जम्मू-कश्मीर में चुनाव की ज्यादा प्रतीक्षा हो रही थी। वहां चुनाव को ज्यादा समय तक टालना अब संभव नहीं था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा खींच रखी थी, अतः अब तीन चरणों में मतदान के साथ चुनाव की घोषणा का स्वागत होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्तूबर को मतदान होंगे, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्तूबर को मत डाले जाएंगे और नतीजे 4 अक्तूबर को आ जाएंगे। गौर करने की बात है कि पिछले दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने इन दोनों प्रदेशों का दौरा किया था। सबसे ज्यादा उत्साह इस बात का है कि कश्मीर में लोग चुनाव में भाग लेने को लालायित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा भी है, 'हमने लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर में लोगों की लंबी कतारें देखी हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और बुलेट के बजाय बैलेट को प्राथमिकता देते हैं।'

जम्मू-कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता 11,800 से अधिक मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। इस बार मतदान का प्रतिशत अच्छा रहने की संभावना है। कश्मीर में माहौल बदला है और ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्यधारा में आ रहे हैं। विगत दिनों से आतंकियों ने जिस तरह से हिंसा का सिलसिला चला रखा है, उससे भी पता चलता है कि आतंकी नहीं चाहते कि चुनाव हो और हालात सुधरें। कश्मीर में लोगों ने अगर लोकतंत्र को मजबूत कर दिया, तो फिर आतंकवाद को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विश्वास जताया है कि जम्मू-कश्मीर के लोग विघटनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। चुनाव आयोग की दृढ़ता सराहनीय है। वहां चुनाव कराने में किसी भी तरह के भय की जरूरत नहीं है और सुरक्षा के तमाम जरूरी इंतजामात रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आयोग ने साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए किसी भी आंतरिक या बाह्य दखल को मंजूरी नहीं दी जाएगी। कोई शक नहीं कि चुनाव से भी जरूरी काम कश्मीर में सुरक्षा बहाल रखना है। सुरक्षा एजेंसियों को अपनी खुफिया ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंसा होने के बाद नहीं, बल्कि हिंसा होने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां मुंहतोड़ जवाब दें। अब राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है और लोगों को भी हिंसा के विरुद्ध पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर को जून, 2018 के बाद से ही चुनी हुई सरकार का इंतजार है। उसका इंतजार अब पूरा होने वाला है।

जम्मू-कश्मीर को छह वर्ष बाद चुनी हुई सरकार मिलने जा रही है, तो वहीं हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सत्ता के लिए मैदान में उतरेगी, तो कांग्रेस वापसी के लिए।

जहां जम्मू-कश्मीर को नई सरकार मिलेगी, वहीं हरियाणा की 90 सीटों पर भाजपा तीसरी बार जीतने के इरादे से उतरेगी। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत है। किसानों की नाराजगी को मुद्दा बनाया जा रहा है। भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का अंदाजा है, उसने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च में ही अपना मुख्यमंत्री बदला है। हालांकि, हरियाणा में कांग्रेस की कुछ बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां से लोकसभा की आधी सीटों और आधे से भी ज्यादा वोटों पर उसका कब्जा हो गया है। अतः इस बार हरियाणा भी सबकी निगाह में होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 17 अगस्त, 1949

बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली, १६ अगस्त। राजधानी में भारतीय स्वतन्त्रता का वार्षिक समारोह कल बहुत भव्य और शानदार तरीके से मनाया गया। यह समारोह सवेरे ६ बजे राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधान सेनापति जनरल करियप्पा द्वारा पुष्पांजलि-अर्पण के साथ आरम्भ होकर रात को सरकारी भवन में गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य द्वारा आयोजित स्वागत-समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। स्वाधीनता समारोह का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह भव्य और विशाल आयोजन था, जबकि राजधानी और दूर-दूरसे आई हुई लगभग चार लाख जनता ने अपने प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू को अपने कार्यकाल में तीसरी बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर २१ तोपों की सलामी के साथ भारत का राष्ट्रीय झण्डा फहराते हुए देखा। भारत की जल, थल और नभ सेनाओं ने प्रधानमन्त्री को सलामी दी और भारतीय वायुसेना के एक दस्ते ने आकाश में उड़ते हुए तिरंगे झण्डे को झुककर सलाम किया।

पं. जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झण्डा फहराने के बाद भाषण देते हुए तीन बातों पर विशेष जोर दिया- एक तो शांतिमय तरीकों से काम करते हुए देश में शांति स्थापित रखना। दूसरी, छोटी और व्यक्तिगत बातों में न पड़कर देश के बड़े सवालों पर विचार करना और तीसरी, अपनी ताकत पर भरोसा रखना। नेहरू जी ने कहा, आज हमारे लिए एक बड़े इम्तिहान का समय है। अगर हमने जरा भी कमजोरी और मायूसी दिखाई, तो लाखों किसानों और मजदूरों के खून-पसीने के बल पर जो आजादी मिली है, उसे हम अपने हाथों से गंवा देंगे और आने वाली सन्ततियों को हमें जवाब देना होगा। भारत की विदेश-नीति स्पष्ट करते हुए नेहरूजी ने कहा कि हम सब देशों के साथ प्रेम और दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं। भारत दुनिया के किसी गिरोह में शामिल नहीं होगा, मगर विश्व की शांति कायम रखने में वह पूरा योग देगा। जहां हम किसी अन्य देश के अन्दरूनी मामलों में दखल देना नहीं चाहते वहां हमें यह भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई और हमारे मामलों में दखल दे और हमारी आजादी में खलल डाले। नेहरूजी ने अन्त में जनता से आर्थिक दृष्टि से भारत को समृद्ध और सम्पन्न बनाने के लिए रचनात्मक कार्यों में जुट जाने की अपील की।

कश्मीर में भी बज उठी चुनावी रणभेरी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए को खत्म करने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। 4 अक्तूबर को जो नतीजे आएंगे, उनसे राज्य के भविष्य का आभास होगा।

अश्वनी कुमार | वरिष्ठ पत्रकार

जम्मू-कश्मीर में दस साल बाद विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनावों की घोषणा के बाद लोगों में एक बार फिर उम्मीद की लहर जागी है। लोग अपने इलाके की तस्वीर बदलना चाहते हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में लोग जिस तरह वोट डालने बाहर निकले, उसे देखते हुए उससे कहीं ज्यादा वोट विधानसभा चुनावों में डाले जाने की उम्मीद है। यह विधानसभा चुनाव इसलिए भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अलगाववादी नेता इस बार या तो जेलों में बंद हैं या चुप्पी साधे बैठे हैं।

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म करने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। पुराने राज्य जम्मू-कश्मीर के दो टुकड़े हो गए थे। एक तरफ, जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित, तो दूसरी तरफ लद्दाख केंद्रशासित। इस बार सभी समीकरण यहां बदल गए हैं। यहां लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। जिस तरह से लोगों ने इस बार लोकसभा चुनावों में वोट डाले और 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे ध्यान में रखना चाहिए। साल 1990 में यहां आतंकवाद शुरू हुआ था, उसके बाद के चुनावों में पांच से 15 प्रतिशत मतदान होता था, लेकिन पिछली बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर 55 प्रतिशत मतदान हुआ।

पिछली बार भाजपा और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने मिलकर चार साल सरकार चलाई। साल 2014 के विधानसभा चुनावों में पीडीपी को 28 सीटें मिली थीं, जबकि भाजपा को 25, पर चार साल बाद गठबंधन सरकार तब गिर गई, जब भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। तब से महबूबा मुफ्ती और भाजपा के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है।

इस बार सितंबर और अक्तूबर में तीन चरण में होने वाले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप-प्रधान उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि वे दोनों विधानसभा चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे, जब तक कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए वापस नहीं दिया जाता और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है।

गौरतलब है, वे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला अपनी बारामुला लोकसभा सीट और महबूबा मुफ्ती अपनी अनंतनाग सीट से काफी वोटों से हार गए थे। उमर अब्दुल्ला को सबसे ज्यादा झटका तब लगा, जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद से वह करीब दो लाख वोटों से हार गए थे। ऐसे ही, महबूबा अपनी अनंतनाग लोकसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुज्जर नेता, मियां अल्ताफ से हार गईं। तब से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री सदमे में हैं।

बहरहाल, 5 अगस्त, 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के समीकरण बदल गए हैं। पहले पुराने राज्य में 87 सीटें होती थीं, पर इस बार 90 सीटें हैं। कश्मीर से 47 और जम्मू क्षेत्र की 43 सीटें हैं। 1987 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेताओं का काफी दबदबा रहता था। बताते हैं, जिस पार्टी को जमात-ए-इस्लामी और आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन मिलता था, उसकी सरकार बनती थी। हालांकि, इस बार अलगाववाद और उग्रवाद का दबदबा खत्म हो गया है। बम और बंदूक का खौफ मिट गया है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं न के बराबर हैं, तो चुनावी नतीजे रोचक होंगे। बदले हुए माहौल में वोट डाले जाएंगे।

उमर अब्दुल्ला ने भले ही एलान किया है कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वैसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि वे किसी से गठबंधन करेंगे या नहीं। लोकसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू की दो सीटों और कश्मीर की तीन सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था। महबूबा और उमर आपस में भी लड़ने वाले थे, पर बाद में दोनों हट गए थे।

इस बार के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाजपा और कांग्रेस के अलावा सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अल्ताफ बुखारी के लिए चुनाव लड़ना आसान न होगा। हाल ही के लोकसभा चुनावों में पड़े वोटों को अगर देखा जाए, तो 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस सात सीटों पर आगे है। यहां सरकार बनाने के लिए 46 सीटें आनी चाहिए। इसी तरह, भाजपा के लोकसभा डेटा को अगर देखा जाए, तो उसको 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, पर ये सभी सीटें जम्मू में हैं।

सबसे ज्यादा जद्दोजहद महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को करनी पड़ेगी। पीडीपी को इस बार पांच विधानसभा सीटों में बढ़त मिली थी, जबकि 2014 चुनावों में उसको 28 सीटें मिली थीं। बारामुला लोकसभा से जीते हुए सांसद इंजीनियर रशीद भी पीडीपी को कड़ा मुकाबला देने वाले हैं। हालांकि, इंजीनियर रशीद जेल में बंद हैं, पर उनके दोनों बेटे चुनावी मुद्रा में दिख रहे हैं। गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद की जम्मू ऐंड कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उतरी कश्मीर की बारामुला लोकसभा सीट के तहत आने वाली में 14 विधानसभा सीटों में बढ़त ली है, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए सिरदर्द है। इन दोनों पहचान रखने वाली पार्टियों को इस बार साख बचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सत्ता में रह चुकी हैं, कश्मीर में विकास की कमजोर रफ्तार के लिए इन दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराने वालों की संख्या भी कम नहीं है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को अपने पुख्ता जवाब के साथ मैदान में उतरना होगा।

भाजपा और कांग्रेस को भी इन विधानसभा चुनावों में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोनों पार्टियों का वोटबैंक जम्मू की 43 सीटों पर ही केंद्रित है। पिछले दस साल में भाजपा को जम्मू में काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में शासन की वजह से जम्मू का सारा व्यापार खत्म हो गया है और बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी फूट की वजह से भी पार्टी के वोटबैंक को नुकसान पहुंच रहा है।

बहरहाल, जम्मू-कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है और मुख्य चुनावी मुद्दों पर बात कहां जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुच्छेद 370, 35ए, बेरोजगारी, आतंकवाद, राज्य का दर्जा दिए जाने और केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते को लेकर भी खूब बातें होंगी और देखना है कि लोग किसे ज्यादा सुनते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

कोलकाता से उठी प्रतिरोध की लहर क्या बदलाव लाएगी

प्रभाकर मणि तिवारी | वरिष्ठ पत्रकार

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्वाधीनता दिवस से पहले आधी रात को हजारों महिलाओं के हुजूम ने जिस तरह इस महानगर की सड़कों पर उतरकर अपने लिए आजादी की मांग की, उसने बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर उतरी भीड़ की तस्वीरें ताजा कर दी। हालांकि, इन दोनों के चरित्र में फर्क था। ढाका में सरकार और अल्पसंख्यक हिंदू तबके के खिलाफ नाराजगी का स्वरूप हिंसक था, लेकिन कोलकाता की आक्रोशित भीड़ का प्रदर्शन लोकतांत्रिक था। इसका मकसद आरजी कर अस्पताल में जुनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराना था।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बीते सप्ताह एक जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन देश भर के डॉक्टर इस घटना के खिलाफ हड़ताल पर चले गए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं, अब भी अस्पतालों में कामकाज सामान्य नहीं हो सका है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस के कामकाज पर असंतोष जताते हुए यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। अब वही इस मामले की जांच कर रही है। मगर इस घटना ने विपक्षी दलों को ममता सरकार के खिलाफ एक मजबूत हथियार भी दे दिया है। विपक्ष का आरोप है कि महिला मुख्यमंत्री और 11 महिला सांसदों के बावजूद जब राजधानी के ही सरकारी अस्पताल में ऐसी घटना हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति समझी जा सकती है। कोलकाता की सड़कों पर उतरी महिलाओं में इस बात की ज्यादा नाराजगी है कि घटना के बाद सरकार व अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में कथित लीपापोती का प्रयास किया। मेडिकल छात्रों में सबसे ज्यादा गुस्सा प्रिंसिपल संदीप घोष के रवैये पर था। घटना के तीन दिनों बाद उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया, पर चंद घंटों के बाद ही उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है।

महिला डॉक्टर के साथ क्रूरता के विरोध की आग कोलकाता से निकलकर अब प्रदेश के अन्य हिस्सों और दूसरे महानगरों में फैल चुकी है।

इस घटना के विरोध में कोलकाता की सड़कों पर उतरी एक छात्रा का कहना था कि ऐसी घटना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार और संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन की ओर से पहले पीड़िता के घरवालों को बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, कुछ देर बाद उन्हें सूचना दी गई कि उसने आत्महत्या कर ली है। माता-पिता के अस्पताल पहुंचने पर पुलिस कार्रवाई का हवाला देकर तीन घंटे तक उन्हें बेटी का शव तक नहीं देखने दिया गया।

कोलकाता में घटी इस घटना का जिस स्तर पर विरोध हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी तुलना निर्भया कांड के बाद उपजी स्थिति से की जा सकती है। 'रीक्लेम द नाइट' अभियान के तहत महिलाओं ने जिस तरह आधी रात के बाद तक कोलकाता की सड़कों पर कब्जा जमाए रखा, हाल के वर्षों में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। इंग्लैंड से शुरू हुआ यह अभियान अपने हक के लिए महिलाओं की लड़ाई का पर्याय बन गया है। विरोध की यह आग कोलकाता से निकलकर राज्य के अन्य हिस्सों और देश के दूसरे महानगरों में फैल चुकी है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में इस अभियान पर दो गुट बन गए हैं। एक इसके समर्थन में है और दूसरा विरोध में। अलग-अलग इलाकों में आयोजित अभियान में कुछ तृणमूल नेता भी शामिल हुए। इस अभियान में शामिल होने वाले तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय की दलील थी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। दूसरी ओर, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का कहना है कि एक घटना के बहाने कुछ लोग बंगाल को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।

बहरहाल, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सरकार इस घटना से सबक लेते हुए महिला सुरक्षा की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अपने शरीर को पहले समझें

एक मंत्री था। किसी कारणवश राजा उस पर नाराज हो गया। राजा ने एक ऊंची मीनार पर मंत्री को कैद रखने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। मंत्री अपनी मौत की राह देखने लगा। मंत्री की पत्नी पतिव्रता थी। एक रात मीनार के नीचे आकर उसने पति से ऊंची आवाज में पूछा, 'मैं कैसे आपकी रक्षा करूं?' मंत्री ने कहा, 'कल रात एक लंबा मोटा रस्सा, एक मजबूत डोरी, एक बंडल सूत, रेशम का पतला सूत, एक भृंग और थोड़ा-सा शहद लेती आना।' पत्नी कुछ चकित हुई, पर पति की आज्ञा के अनुसार अगली रात वह सभी वस्तुएं ले आई। मंत्री ने उससे कहा, 'रेशम का सूत मजबूती से भृंग के पैर में बांध दो, उसकी मूंछों में एक बूंद शहद लगा दो और उसका सिर ऊपर की ओर करके उसे मीनार की दीवार पर छोड़ दो।'

पतिव्रता ने सभी आज्ञाओं का पालन किया। तब उस कीड़े ने अपना लंबा रस्सा पार करना शुरू किया। सामने शहद की महक पाकर उसके लोभ से वह धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा और मीनार की चोटी पर जा पहुंचा, मंत्री ने झट उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेशम के सूत को भी। इसके बाद उसने पत्नी से कहा, 'बंडल में जो सूत है, उसे रेशम के सूत के छोर से बांध दो। इस तरह वह भी उसके हाथों में आ गया। इसी उपाय से उसने डोरी और मोटे रस्से को भी पकड़ लिया। अब कोई कठिन काम न रह गया। रस्सा ऊपर बांधकर वह नीचे उतरा और भाग खड़ा हुआ।

हमारी इस देह में श्वास-प्रश्वास की गति मानो रेशमी सूत है। इसके धारण या संयम कर सकने पर पहले स्नायविक शक्तिप्रवाह रूप (नर्व करेंट) सूत का बंडल, फिर मनोवृत्ति रूप डोरी और अंत में प्राण रूप रस्से को पकड़ सकते हैं। प्राणों को जीत लेने पर मुक्ति प्राप्त होती है। हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम मन को उतनी दूर तक एकाग्र नहीं कर सकते, जिससे हम शरीर के भीतर की अति-सूक्ष्म गतियों को समझ सकें। मन जब बाह्य विषयों का परित्याग करके देह के भीतर प्रविष्ट होता है और अति-सूक्ष्म अवस्था प्राप्त करता है,

हम अपने शरीर के संबंध में बहुत कम जानते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि हम मन को उतने एकाग्र नहीं कर सकते, जिससे हम शरीर के भीतर की अति-सूक्ष्म गतियों को समझ सकें।

तभी हम उन गतियों को जान सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म अनुभूति से संपन्न होने के लिए हमें पहले स्थूल से आरंभ करना होगा। देखना होगा, सारे शरीर यंत्र को चलाता कौन है और उसको अपने वश में लाना होगा। वह प्राण है, इसमें कोई संदेह नहीं।

हमारा मन स्नायविक शक्तिप्रवाहों से संचालित हो रहा है, इसीलिए उन पर विजय पाने से मन और शरीर, दोनों हमारे अधीन हो जाते हैं। ज्ञान ही शक्ति है और वह शक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए हमें प्राणायाम- प्राण के नियमन- से प्रारंभ करना चाहिए।

स्वामी विवेकानंद

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

न आजादी एक दिन में मिली और न ही इसका जश्न सिर्फ एक दिन का है। तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए स्वतंत्रता एक दैनिक संघर्ष है। आपको सभी तूफानों, सभी किस्म के विभाजनों के बावजूद अपने झंडे को बुलंद रखना होगा।

राहुल की सीट को लेकर विवाद अनुचित

यह साल 2018 की घटना है। उस वक्त 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कर्तव्यपथ पर राहुल गांधी पहुंचे थे। चूंकि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं मिली थीं कि उसके मुखिया को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल पाता, इसलिए बतौर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल समारोह में पहुंचे थे। उनको छठी कतार दी गई थी बैठने के लिए। तब राहुल गांधी ने एक मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनको अंतिम कतार में भी जगह मिलती, तो वह राष्ट्रीय समारोह में खुशी-खुशी शामिल होते। जब उनकी सोच ऐसी है, तो फिर क्यों लाल किले पर उनकी जगह को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। वास्तव में, राष्ट्रीय समारोहों में शामिल होना ही अपने आप में गर्व का विषय है और राहुल गांधी को इसीलिए पीछे की सीट दी गई थी, क्योंकि औलंपिक खिलाड़ियों के बीच बैठाया गया। इस पर कांग्रेस खिन्न हुई है। यह शोर मचा रही है कि विपक्ष के नेता कोई मामूली हस्ती नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। कांग्रेसी भाई बात तो सही कह रहे हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यदि राहुल को ओलंपिक युवा खिलाड़ियों के बीच भी बैठाया गया, तो इसे कांग्रेस को अवसर में बदलना चाहिए। आखिर कैबिनेट मंत्रियों के बीच अकेले बैठकर क्या करते राहुल? राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी तो समारोह में नहीं आए थे। ऐसे में, राहुल गांधी को युवाओं के बीच में बैठकर अच्छा लगना चाहिए था और उनको लगा भी होगा। किंतु कांग्रेसी हैं कि बात का बतंगड़ बनाकर ही मानेंगे। लिहाजा, इस बात को तूल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए।

जिनको हम सम्मान देते हैं, उनको स्वाभाविक ही अग्रिम पंक्तियों में बिठाते हैं। अलबत्ता, कांग्रेस को यह संतोष करना चाहिए कि कोई दल राज्यसभा के उसके नेता के राष्ट्रीय समारोह में न पहुंचने को मुद्दा नहीं बना रहा, जबकि मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे और बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने वहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। राष्ट्रीय समारोह में न आकर पार्टी के आयोजन में शिरकत करना क्या ठेश का अपमान नहीं है?

मुंजन, टिप्पणीकार

खत्म कीजिए टकराव

लगभग दस साल बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर पहुंचे थे, जहां उनको पांचवीं पंक्ति में ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच बैठाया गया। इस पर कांग्रेस खिन्न हुई है। यह शोर मचा रही है कि विपक्ष के नेता कोई मामूली हस्ती नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ अग्रिम पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। कांग्रेसी भाई बात तो सही कह रहे हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यदि राहुल को ओलंपिक युवा खिलाड़ियों के बीच भी बैठाया गया, तो इसे कांग्रेस को अवसर में बदलना चाहिए। आखिर कैबिनेट मंत्रियों के बीच अकेले बैठकर क्या करते राहुल? राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी तो समारोह में नहीं आए थे। ऐसे में, राहुल गांधी को युवाओं के बीच में बैठकर अच्छा लगना चाहिए था और उनको लगा भी होगा। किंतु कांग्रेसी हैं कि बात का बतंगड़ बनाकर ही मानेंगे। लिहाजा, इस बात को तूल देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए।

विनय शंकर त्रिपाठी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

बैठने पर विवाद

नेता प्रतिपक्ष के साथ यह सलूक गलत

लगता है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सितारे गर्दिश में हैं। जब से सरकार बनी है, रोज कोई-न-कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ताजा मसला स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आखिरी से दूसरी पंक्ति में बिठाने का है। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और कायदे से उनकी सीट कैबिनेट मंत्री के साथ ही पहली या दूसरी पंक्ति में होनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं किया गया और उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ पीछे बिठाया गया। राहुल गांधी की विनम्रता देखिए कि वह बिना किसी आपत्ति के अपनी निर्धारित जगह पर बैठ गए और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि यह वह राहुल गांधी नहीं हैं, जिनकी छवि खराब करने के लिए कभी एक पूरा तंत्र काम कर रहा था। तब उनको न जाने कैसी-कैसी उपमाओं से विभूषित किया जाता था। मगर इस चुनाव के बाद उनका कद इतना बढ़ गया है कि उनसे जुड़ी हरेक घटना उनके समर्थकों की संख्या बढ़ाने में ही मददगार बन जाती है। यही कारण है कि 15 अगस्त की राहुल की तस्वीर को सोशल मीडिया में खूब साझा किया जा रहा है और यह सवाल पूछा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया?

मीडिया में रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो कथित बयान आया है, वह भी गले नहीं उतरता। बयान में कहा गया है कि ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान होना था, इसलिए राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई। बेशक, ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या इसी तर्क के आधार पर केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे नहीं बैठना चाहिए था? साफ है, राहुल गांधी को पीछे बिठाने की कोई राजनीतिक मजबूरी रही हैं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि षड्यंत्रकारियों का दांव उल्टा पड़ गया। यह जानते हुए भी कि लोकंत्र में जनता के सवाल सत्ता पक्ष के लिए सहज नहीं होते, भारत में सत्तारूढ़ दल के लोग वक्त-बेवक्त जोखिम लेने का प्रयास करते रहते हैं, जिसका उनको नुकसान ही होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है।

रही बात राहुल गांधी की, तो आम जनता के बीच उनकी छवि विनम्र और मिलनसार व्यक्ति की है। संभवतः इसीलिए भी ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच बैठे उनकी तस्वीर ज्यादा वायरल हुई। मीडिया की पड़ाई के दौरान बताया जाता है कि एक तस्वीर का प्रभाव हजार शब्दों से ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ यहां हुआ है। साफ है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को यह इज्जत मिलनी चाहिए, जिसके वह हकदार हैं।

अरुण पुरुषार्थ, वरिष्ठ अधिकारी

औद्योगिक विकास

पिछले दस वर्षों में इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, इटली और रूस को पछाड़ते हुए भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस श्रेय के कई कारक हैं। भारत में आजादी से पहले और बाद में क्रमबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास हुआ है। एक स्पष्ट औद्योगिक नीति के साथ आर्थिक सुधार नीति तथा वर्तमान सरकार की संरक्षण नीति को इसका श्रेय दिया जा सकता है। एक नजर

आत्मनिर्भरता की राह पर भारतीय उद्योग

अश्विनी महाजन, अर्थशास्त्री

डॉलर की बाजार कीमत के आधार पर भारत लगभग 4 खरब डालर, और क्रय शक्ति समता के आधार 13 खरब डालर से भी ज्यादा की जीडीपी के साथ, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले दस सालों में भारत इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील, इटली और रूस को पछाड़ते हुए पांचवें क्रमांक पर पहुंचा है। लेकिन निर्माण और उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में मात्र 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही रखता है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन जीडीपी की प्रगति में उद्योगों के योगदान की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान कहीं अधिक रहा और देश आयातों पर अत्यधिक निर्भर रहा।

स्वतंत्रता के पहले के प्रयास

वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के बाद कई नई कपड़ा और जूट मिलें देश में स्थापित हुईं। कोयले का उत्पादन बढ़ा, रेलवे का भी तेजी से विस्तार हुआ और लोहा तथा इस्पात उद्योग की नींव भी इसी दौरान रखी गई। प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत के कारखानों में बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी। इंग्लैंड और अन्य देशों से आयात कम हुए और स्वयं विदेशी सरकार ने भी युद्ध के उद्देश्य से काफी सामान खरीदना शुरू कर दिया।

स्वदेशी आंदोलन के दबाव में कुछ चुनिंदा भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु आयात शुल्क लगाने के लिए सरकार राजी हो गई। इससे 1924 और 1939 के बीच कई उद्योगों को संरक्षण के कारण लोहा, इस्पात, सूती वस्त्र, जूट, चीनी, कागज और माचिस उद्योगों का विकास हुआ। 1939 के द्वितीय विश्वयुद्ध ने भारतीय उद्योगों के साजो-सामान की मांग और तेजी से बढ़ाई। कई नए उद्योग लगे, जिन्हें 'वार बेबी' यानी युद्ध की संतानें भी कहा जाता था।

आजादी के बाद औद्योगिक रणनीति

जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में औद्योगीकरण के नाम पर मात्र कुछ उद्योग ही थे, जिनमें अधिकांशतः उपभोक्ता वस्तु उद्योग ही थे। पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी, बड़े औद्योगिक प्लांट, बुनियादी और अन्यान्य प्रकार के पूंजीगत उद्योग भारत में नहीं थे। ऐसे में आजाद भारत में औद्योगिक विकास की नींव रखने के लिए सरकार ने एक रणनीति तैयार की। इसके तहत बड़े पूंजीगत उद्योग, मशीनों के निर्माण के लिए बड़े मशीन उद्योग, मूलभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, रसायन उद्योग आदि की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाए।

आजादी के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार द्वारा भारी निवेश के बाद बड़ी संख्या में लोहा और इस्पात, रसायन, मशीनरी, सीमेंट, एल्युमीनियम, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली सरीखे मूलभूत उद्योग स्थापित हुए। लेकिन कुल मेन्युफैक्चरिंग उत्पादन में वृद्धि बहुत सीमित थी। वर्ष 1950-51 और 1970-71 के बीच मेन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर मात्र 5.6 प्रतिशत रही। 1970-71 और 1980-81 के बीच तो यह केवल 4 प्रतिशत ही थी। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने के कारण अंतरराष्ट्रीय वस्तु निर्यातों में भारत का हिस्सा 1950-51 में 2.1 प्रतिशत से घटता हुआ 1980-81 तक मात्र 0.4 प्रतिशत रह गया।

1991 के आर्थिक सुधार

1991 तक आते-आते ऐसी स्थिति आ गई कि आयातों और निर्यातों में बड़े अंतर के कारण भारत भुगतान संकट का जबरदस्त शिकार हो गया। हमें लेनदारों को आश्वस्त करने के लिए अपना सोना प्रतिभूति के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजना पड़ा। ऐसे में सरकार जिसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, ने कहा कि गलत नीतियों की वजह से देश का औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है और उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण ही एकमात्र रास्ता है। विदेशी निवेश के लिए विभिन्न क्षेत्रों को खोलना ही आर्थिक सुधार कहलाने लगा। इस नीति के अंतर्गत डब्लूटीओ में हस्ताक्षर करते हुए देश की सीमाओं को न्यूनतम टैरिफ आयातों के लिए खोल दिया गया। गैर टैरिफ बाधाएं भी समाप्त कर दी गईं और विदेशी निवेश को भी खुली छूट दे दी गई। इससे देश की जीडीपी में मेन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 19 प्रतिशत से घटते हुए मात्र 16 प्रतिशत के करीब आ गया।

ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आदि नीतियों के अंतर्गत भारतीय उद्योग क्षेत्र को वापस लाने के प्रयास हुए लेकिन उनका सीमित लाभ ही मिला।

संरक्षण की नीति पर जोर

वर्ष 2018 के बाजार में पहली बार संरक्षण की नीति आंशिक रूप से अपनाई गई। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उत्पादन तथा निर्यात दोनों बढ़े। 2020 की महामारी के दौरान सरकार ने एक बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए आत्मनिर्भर भारत नीति की शुरुआत की।

इस नीति के अंतर्गत उन तमाम वस्तुओं का उत्पादन अब देश में करने का प्रयास शुरू हुआ है, जो चीन से असमान और धोखाधड़ी की तरकीबों के कारण बाधित हुआ। सरकार द्वारा उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के माध्यम से रसायन, एपीआई, मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फर्नीचर, वस्त्र एवं परिधान, कागज, खिलौने, साइकिल, मशीनरी, एलईडी, लैपटॉप, सेमी कंडक्टर इत्यादि समेत 15 उद्योगों को चुना गया। इससे उम्मीद की जा रही है कि उद्योगों को पुनः स्थापित किया जा सकेगा। इसके सुखद परिणाम के रूप में खिलौनों में आयात घटा है। निर्यातों में वृद्धि हुई है। मोबाइल फोनों का बड़ी मात्रा में निर्यात हो रहा है। जिन उद्योगों में पीएलआई दी गई है, वहां बड़ी मात्रा में निवेश भी हो रहा है। इनके अलावा देश में प्रतिरक्षा के साजो-सामान के उत्पादन और निर्यात में भी बड़ी वृद्धि हुई है।

स्थिर कीमतों पर औद्योगिक वृद्धि दर

9.5% औद्योगिक विकास दर रही, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार

सकल मूल्य वृद्धि का तिमाही अनुमान (वर्तमान कीमतों पर)

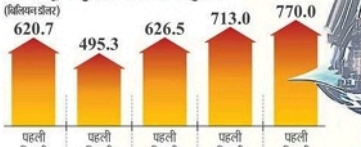

तीन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की वार्षिक वृद्धि दर

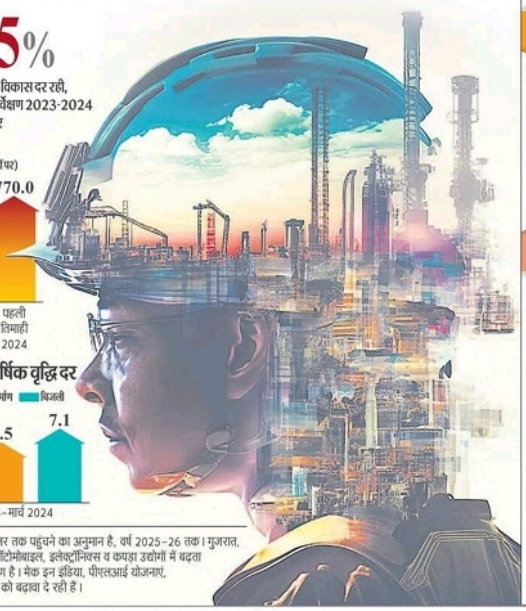

नीतियों का भी योगदान

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के 1 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, वर्ष 2025-26 तक। गुजरात, महाराष्ट्र व तमिलनाडु प्रमुख अग्रणी राज्य हैं। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व कपड़ा उद्योगों में बढ़ता निवेश औद्योगिक क्षेत्र में तेजी का एक बड़ा कारण है। मेक इन इंडिया, पीएलआई योजनाएं, डीपीआईआईटी आदि योजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

निर्माण उपक्षेत्रों में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

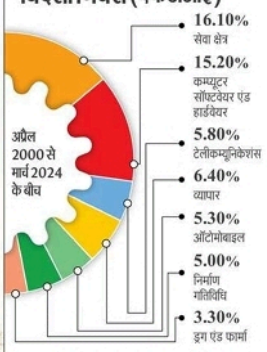

8.2% रही सकल उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2024 में, यह साल में चार में से तीन तिमाहियों में 8 प्रतिशत अधिक रही

4.5% महंगाई दर में कमी का अनुमान वित्त वर्ष 2025 में, आरबीआई के अनुसार

2.35 करोड़ हो जाएगी गिग कार्यबल में शामिल लोगों की संख्या, वर्ष 2029-30 तक बढ़कर

विनिर्माण निर्यात में आई जबरदस्त तेजी

इन दिनों भारतीय विनिर्माण निर्यात में तेजी दर्ज होती देखी जा रही है। बीते वर्ष यह उल्लेखनीय उपलब्धि रही। आईबीईएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 447.46 खरब डॉलर का वार्षिक निर्यात हुआ। यह 6.03 फीसदी की वृद्धि दर के साथ अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निर्यात आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2022 में यह 422 अरब डॉलर था।

रोजनामचा

वर्ग पहेली 7697

ऊपर से नीचे
2. प्रबल अभिलाषा; गहरी चाह (3)
3. हलका; मंद (2)
4. जिसका नाम आदर से लिया जाता हो; अति प्रसिद्ध; नामवर (4)
5. चरपरापन; स्वाद का तीखापन झाल; ईर्ष्या; डाह; द्वेष (6)
6. कई जन्मों तक; हर जन्म में; सदा (6)
7. नवां; नवें स्थान का (3)
11. जांच; परीक्षा; पहचान (3)
13. जुदाई; भिन्नता; पृथकता (4)
16. कठोर पदार्थ; कठोर पिंड; व्यर्थ पदार्थ; प्रस्तर (3)
17. सपेरों के बजाने की तुमड़ी (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली (उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं
1. खरी-खोटी सुनाना; डांटना-फटकारना (3,2,3)
6. जकड़ा हुआ होने का भाव; कसाव; पाश; पकड़न; बंधन (4)
8. भलमनसाहत; शिष्ट व्यवहार; सात्विक व्यवहार (4)
9. पानी; सलिल; कचलोहु; पंछा (2)
10. पृथ्वीपति; महीपाल; राजा (3)
12. अच्छा; बढ़िया; सच्चा; स्पष्ट; छल-कपट रहित, (2)
14. अस्थिरता; चंचलता; चपलता; द्रवत्व (4)
15. अनबन; झगड़ा; खट-खट (4)
18. अनादर करना; अपमान करना; मानहानि करना (5,3)

वर्ग पहेली 7696 का उत्तर

सुडोकू

7680 *मध्यम

5		1			8		9	2
7								
			9	3				5
8				7		2		
		2	8		5	3		
		6		4				8
9				2	7			
								6
2	4		6			8		9

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

8	3	1	6	2	7	5	4	9
7	9	2	8	5	4	6	1	3
6	4	5	3	9	1	8	2	7
5	8	3	9	6	2	1	7	4
2	1	9	4	7	8	3	5	6
4	6	7	5	1	3	9	8	2
1	5	4	2	3	6	7	9	8
9	2	6	7	8	5	4	3	1
3	7	8	1	4	9	2	6	5

हल : सुडोकू नं.7679

व्रत और त्योहार

पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

17 अगस्त, शनिवार, शक संवत् : 26 श्रावण (सौर) 1946, पंजाब पंचांग : 02 श्रावण मास प्रविष्टे 2081, इस्लाम : 11 सफर सन 1446, विक्रमी संवत : श्रावण शुक्ल द्वादशी प्रातः 8.46 मिनट तक पश्चात त्रयोदशी सूर्योदय पूर्व 5.52 मिनट तक तदनंतर चतुर्दशी। सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। शनि प्रदोष व्रत। त्रयोदशी का क्षय।

वास्तु सलाह

आचार्य मुकुल रस्तोगी

मुझे ऐसा लगता है कि विवाह के 20 वर्ष बाद भी मुझे परिवार में सम्मान नहीं मिलता। कोई उपाय हो तो बताएं? -अंशु, बनारस

- कमरे में बेड के पीछे खिड़की हो तो उसे बंद कर दें। बेड को दक्षिण की दीवार पर लगाएं।
- एक रेड जेस्पर का पिरामिड कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें।
- नित्य प्रति सूर्य को रोली व गुड़ डालकर जल दें।

बेहतर परिवेश
सुरक्षित निवेश
उत्तर प्रदेश

सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार एवं उद्योगों के लिए सर्वथा अनुकूल नीतियों से उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश आकर्षित हुआ है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट एवं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने देश-विदेश के निवेशकों को इस प्रदेश के पोटेंशियल एवं असीम संभावनाओं से परिचित कराया है। इन दोनों आयोजनों के माध्यम से लगभग 45 लाख करोड़ रुपये के एमओयू के सापेक्ष अब तक 16 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो चुका है, शेष परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य गतिमान है।

■ उद्यम के लिए बेहतर माहौल

उत्तर प्रदेश में लगातार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े आयोजनों से उद्यमियों का मनोबल बढ़ा है। कानून-व्यवस्था में सुधार ने उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है।

सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

■ निवेश फ्रेंडली नीतियां

योगी सरकार के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था बेहतर होने से उद्योग जगत को प्रोत्साहन मिला है। प्रदेश में नई औद्योगिक नीति लागू होने का फायदा भी सभी क्षेत्रों के उद्योगों को मिल रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था बेहतर हुई है और बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास हुआ है।

आरके चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

निवेश प्रोत्साहन के लिए 28 सेक्टोरल पॉलिसी लागू
सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से 43 विभागों की 487 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 6-6 औद्योगिक गलियारों का विकास कार्य प्रारंभ
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, आईटी पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब का विकास
लखनऊ एवं हरदोई में पी.एम. मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, 15000 करोड़ रुपये का निवेश
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन
96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित
देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर अग्रसर
एक जनपद-एक उत्पाद कार्यक्रम (ओडीओपी) को मिली वैश्विक पहचान
निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये हुआ
यू.पी. इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एम.ओ.यू., 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं क्रियान्वित
यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एम.ओ.यू., 1.10 करोड़ रोजगार के अवसर होंगे सृजित
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) 4.0 के माध्यम से 10.11 लाख करोड़ रुपये निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन प्रारंभ
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में लगातार अचीवर स्टेट
अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का क्रियान्वयन
वर्ष 2020-21 से 2023-24 की अवधि में जीएसडीपी में 15.7% की वृद्धि
21.60 लाख युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण
सितंबर, 2024 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में अभी तक 66 देशों के 2500 एक्जीबिटर्स द्वारा पंजीयन

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 156

टेलीमार्केटिंग कॉल से निजात

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस सप्ताह के आरंभ में एक आदेश जारी किया जिसका उद्देश्य स्पैम फोन कॉल पर अंकुश लगाना है। इसमें रिकॉर्डिड संदेश भी शामिल हैं। टेलीमार्केटिंग करने वालों की ओर से अवांछित और स्पैम कॉल हाल के महीनों में तेजी से बढ़ी हैं जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं की निजता का हनन हो रहा है और इस समस्या का कोई हल भी नजर नहीं आ रहा है। दूरसंचार नियामक और सरकार दोनों ने अतीत में अवांछित कॉल से निपटने के कई तरीके अपनाने का प्रयास किया और इसके लिए कानून भी बनाया। इनमें से अंतिम था टेलीकॉम कॉमर्शल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिफरेंस रेग्युलेशंस, 2018। परंतु जो भी उपाय अपनाए गए वे अक्सर मनचाहे परिणाम पाने में नाकाम रहे। गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियां जहां तकनीक की मदद से उपभोक्ताओं पर ऐसी कॉल की बमबारी कर रही हैं, वहीं दूरसंचार सेवा प्रदाता भी अक्सर इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाते। ट्राई का ताजा निर्देश इन स्थितियों को बदलना चाहता है। इसके लिए उसने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश दिया है कि वे वाणिज्यिक कॉल करने वाले किसी भी गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों के सभी दूरसंचार संसाधनों को दो साल के लिए पूरी तरह रोक दे। यदि उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो किसी अन्य सेवा प्रदाता को भी टेलीमार्केटर का मौका नहीं देने दिया जाएगा।

ट्राई के आदेश के अनुसार अगर शिकायत किसी गैरपंजीकृत टेलीमार्केटर से संबंधित हो तो मूल सेवा प्रदाता संदेश भेजने वाले को पहले उल्लंघन के बारे में एक चेतावनी भेजेगा। दूसरे अवसर पर संदेश भेजने वाले पर छह महीने तक की रोक लगाई जाएगी और तीसरे या उसके बाद वाले अवसर पर संदेश भेजने वाले के सभी दूरसंचार संसाधनों को दो साल की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

इसके बाद संदेश भेजने वाले को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाना चाहिए और किसी भी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा इन्हें नए दूरसंचार संसाधन नहीं मुहैया कराए जाने चाहिए। यह इस आदेश की एक महत्त्वपूर्ण बात है। ट्राई के निर्देश में एक और अहम बात यह है कि स्पैम कॉल करने वाली कंपनी के सभी दूरसंचार संसाधन समाप्त कर दिए जाएंगे, न कि कोई खास सिग्नल।

ट्राई ने स्पष्ट किया है कि कारोबारी ग्राहक अक्सर सैकड़ों संकेतकों के साथ प्रोटोकॉल प्राइमरी रेट इंटरफेस लाइन के माध्यम से वाणिज्यिक वॉयस कॉल करते हैं। परंतु अब तक सेवा प्रदाताओं द्वारा कारोबारी ग्राहकों के खिलाफ की गई कार्रवाई आमतौर पर उनके सभी दूरसंचार संसाधनों के बजाय एक विशेष संकेतक को बंद करने तक सीमित है।

स्पैम का आकार और उनका पैमाना बहुत बड़ा है और उसका अंदाजा दूरसंचार नियामक द्वारा समर्थित अनुमानों से लगाया जा सकता है। वर्ष 2023 में देश में गैर पंजीकृत टेलीमार्केटर्स के खिलाफ 12 लाख से अधिक शिकायतें की गईं और 2024 में शुरुआती छह महीनों में ही 7.90 लाख से अधिक शिकायतें की जा चुकी हैं। चूंकि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है इसलिए यह ठोस है परंतु इसके प्रभाव का आकलन केवल समय के साथ ही किया जा सकता है। ट्राई का काम है कुछ अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के अलावा दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। उसके अन्य लक्ष्यों में दूरसंचार सेवाओं का नियमन और कंपनियों के लिए सेवा गुणवत्ता के मानक तय करना है। उस संदर्भ में स्पैम संचार को रोकना नियामक के लिए पहले ही प्राथमिकता वाला काम होना चाहिए था। अब जबकि एक ठोस कदम उठा लिया गया है तो उपभोक्ता भी बिना किसी बाधा के आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उसके लिए ट्राई, दूरसंचार विभाग और सेवा प्रदाताओं को साथ मिलकर और सक्रिय होकर काम करना होगा।

विनय सिन्हा

नीतिगत उपाय पूरा करेंगे विकसित भारत का सपना

भारत को विकास का अपना लक्ष्य हासिल करना है तो बजट में घोषित प्राथमिकताओं के लिए नीतिगत स्तर पर सुधार फौरन आरंभ करना जरूरी है। बता रहे हैं एम गोविंद राव

केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने के बाद मचा शोरगुल थम चुका है और अब सभी नजर से देखना होगा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि में क्या रणनीति अपनानी होंगी और नीतिगत स्तर पर क्या प्रयास करने होंगे। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में किसी विकसित देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) 14,005 डॉलर है। भारत की जीएनआई 2,600 डॉलर के करीब रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि यह विकसित देशों के समूह में इतनी जल्दी शामिल नहीं होने जा रहा है। भारत को इस समूह में आना है तो उसे प्रति व्यक्ति जीएनआई 5.3 गुना बढ़ानी होगी। दूसरे शब्दों में उसे अगले 23 वर्ष तक प्रति व्यक्ति जीएनआई में औसतन 7.5 प्रतिशत सालाना और कुल जीएनआई में औसतन 9 प्रतिशत सालाना वृद्धि करनी होगी।

एक और बात यह है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में ठहराव वर्ष 2045 में आएगा। आर्थिक समीक्षा में दिए गए अनुमानों के अनुसार कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में वर्ष 2030 तक सालाना लगभग 80 लाख नए रोजगार सृजित करने होंगे। इन दोनों पहलुओं के साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे पूरा करने के लिए यानी जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद कर हरित ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने के लिए उसे भारीभरकम निवेश करना होगा।

आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निवेश और उत्पादन में बड़े स्तर पर वृद्धि करनी होगी। फिलहाल वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात 5 है, जिसके हिसाब से निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए, जो अभी 34 प्रतिशत ही है। इसमें जो कसर रह जाएगी, उसकी भरपाई उत्पादकता बढ़ाकर करनी होगी। लिहाजा नई तकनीक का इस्तेमाल करना और कार्यबल को अधिक शिक्षित एवं हुनरमंद बनाना समान रूप से जरूरी है। ये कठिन चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए प्राथमिकताएं दोबारा तय करनी होंगी और नीतिगत सुधार अविलंब लागू करने होंगे।

जुलाई में पेश केंद्रीय बजट में नौ क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताएं परिभाषित कर वृहद निर्देशों का उल्लेख किया गया है। ये प्राथमिकताएं हैं कृषि क्षेत्र में उत्पादकता एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता बढ़ाना, रोजगार एवं कौशल विकास, मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना, उद्योग एवं सेवाएं, शहरी विकास, नवाचार और नई पीढ़ी के सुधार। ये व्यापक प्राथमिकताएं हैं किंतु इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुधार के विशिष्ट उपाय करना जरूरी है। इन प्राथमिकताओं एवं नीतिगत संकेतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से सही मार्ग चुनने एवं आवश्यक सुधार एवं बदलाव करने में सहायता मिलेगी।

निवेश एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है कारोबार के लिए सस्ती पूंजी उपलब्ध कराना और प्रत्यक्ष लाभ के साथ अप्रत्यक्ष लाभ भी सुनिश्चित करना होगा। वर्ष 2021-22 से ही राजकोष को मजबूत करने और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक रोकना कठिन नहीं होगा किंतु इसे और कम कर 3 प्रतिशत के मूल लक्ष्य तक लाना तथा केंद्र सरकार पर कर्ज बोझ को जीडीपी के 40 प्रतिशत तक रोकना जरूरी है ताकि निजी क्षेत्र के लिए भी कर्ज लेने की गुंजाइश बनी रहे। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घरेलू बचत कम होकर 5.3 प्रतिशत रह गई है। इसे देखते हुए सरकार को मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाओं से जुड़े लक्ष्यों पर दोबारा विचार करना चाहिए और उन्हें अगले बजट में प्रस्तुत करना चाहिए। अगला बजट बमुश्किल छह महीने में आना है। वित्तीय क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने और सरकारी उधारी में ज्यादा अनुशासन लाने के लिए सांविधिक तरलता अनुपात में कमी करना भी इतना ही जरूरी है।

केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर बुनियादी ढांचे में निवेश पर अधिक ध्यान देना होगा। इसके लिए राजस्व व्यय को साधना होगा और बेहद जरूरी व्यय ही करना होगा। केंद्र स्तर पर छोटा-मोटा राजस्व व्यय कम किया जा चुका है। खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में और कमी के लिए अब कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार करने होंगे। ये सुधार केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को करने होंगे। शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा पर व्यय भी अच्छा खासा बढ़ाना होगा।

अच्छी बात यह है कि कर संग्रह में इजाफा जारी रहेगा और तकनीक के ज्यादा इस्तेमाल से इसमें वृद्धि तेज होनी चाहिए। अगले बजट में पुरानी आयकर प्रणाली खत्म कर व्यक्तिगत आयकर को तार्किक बनाने और कर दरों या स्लैबों की संख्या घटाकर 3 करने से कर प्रणाली और सरल हो जाएगी। इस बजट में विदेशी कंपनियों पर लागू होने वाली कर दर कम होकर 35 प्रतिशत रह गई है और इसे देसी कंपनियों के बराबर 30 प्रतिशत पर लाना उचित होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को दुरुस्त करना भी जरूरी है। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को मिल रही रियायत कम करने, जीएसटी के दायरे से बाहर वस्तुओं को इसकी जद में लाने, कर श्रेणी घटाकर दो करने और बड़े कर चोरों पर नकेल कसने से ही ऐसा हो पाएगा।

उत्पादन में योगदान देने वाले कारकों (फैक्टर-मार्केट) में सुधार खासकर श्रम सुधार करना रोजगारों की संख्या एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अपना आकार बढ़ाना होगा और छोड़ करने की क्षमता विकसित करने के लिए तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना होगा। अंकुश लगाने वाले या बाधा बनने वाले श्रम कानून एमएसएमई को कारोबार बढ़ाने की क्षमता प्रभावित करते हैं। केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को पहले ही चार संहिताओं में बांट दिया है और अब इन्हें लागू करना जरूरी है। चूंकि श्रम समवर्ती सूची में आता है, इसलिए राज्यों को भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अब देखना यह है कि इस वर्ष के बजट में घोषित प्रोत्साहन कितने असरदार साबित होते हैं। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारी को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) देना, नई भर्ती के पहले चार वर्षों में कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों के लिए भर्तियों की संख्या से जुड़े प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को नए कर्मियों के लिए किए गए ईपीएफओ अंशदान में से हर महीने 3,000 रुपये तक सरकार द्वारा लौटाए जाना आदि शामिल हैं। शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रस्ताव में भी 12 महीने के लिए 5,000 रुपये भुगतान की बात कही गई है।

व्यापार के मोर्चे पर भारत को अपना संरक्षणवादी रुख भी बदलना होगा। कुछ वस्तुओं पर शुल्क कम करने से अधिक खुली नीति का संकेत मिलता है। सरकार ने अगले छह महीने के दौरान शुल्कों की समीक्षा की घोषणा की है और इस पर अमल हुआ तो एक तय अवधि के भीतर दरें घटाने तथा एकीकृत करने में मदद मिलेगी। यह कदम भारतीय विनिर्माण उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएगा। शुल्क घटाने तथा बाजार को और खोलने के लिए सरकार को अधिक द्विपक्षीय समझौतों को तेजी देनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल धीरे-धीरे खत्म करने और हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की तरफ कदम बढ़ाने से शुरुआत में जोखिम होंगे। इसके लिए और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए धन की अधिकतर जरूरत सरकार ही पूरी करेगी।

अंत में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पूरे तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा। दोनों को इस पर एकाग्रचित्त होना पड़ेगा, सौहार्द बनाए रखना होगा, संवाद करना होगा और समन्वय के साथ मजबूत संघवाद रखना होगा।

(लेखक 14वें वित्त आयोग के सदस्य थे। ये उनके निजी विचार हैं)

कौन होगा स्टालिन का उत्तराधिकारी?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अगस्त के आखिर में प्रदेश के लिए निवेश जुटाने अमेरिका जाएंगे। वह करीब तीन सप्ताह तक विदेश में रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है और अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह वह भी प्रवासियों को लुभाने जा रहे हैं। परंतु इतने समय के लिए बाहर रहने पर अपनी जगह राज्य की बागडोर संभालने के लिए किसी व्यक्ति का चयन उत्तराधिकारी के चयन में बदल सकता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में अब दो वर्ष से भी कम बचे हैं (प्रदेश में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं), इसलिए उन पर दबाव होना स्वाभाविक है।

सबकी नजरें उनके बेटे उदयनिधि पर टिकी हैं, जो फिलहाल राज्य में प्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार में खेल मंत्री हैं। सरकार में अन्य मंत्रियों का कहना है कि उदयनिधि को पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। ऐसे लोगों में उच्च शिक्षा और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री आर एस राजकन्नपन और आवास एवं शहरी विकास मंत्री एस मुत्तुस्वामी जैसे लोग शामिल हैं। ऐसा बोलने वालों में सबसे नया नाम है नागर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू का।

राजकन्नपन पहले द्रमुक छोड़कर अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक में चले गए थे मगर पार्टी में लौट आए हैं और यह जताने के लिए अधीर हुए जा रहे हैं कि पार्टी के साथ उनका जोड़ अब एकदम पक्का है। इस माह के आरंभ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। उसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी बात में संशोधन किया और कहा कि लोग उन्हें उप मुख्यमंत्री कह सकते हैं लेकिन '19 अगस्त' के बाद। मुत्तुस्वामी भी पहले अन्नाद्रमुक में ही थे मगर वह 2010 में करुणानिधि के जीवित रहते ही द्रमुक में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए उदयनिधि का नाम लिया है।

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

परंतु नेहरू को गंभीरता से लेना होगा। वह त्रिची से पांच बार के विधायक हैं। वह कभी पार्टी छोड़कर नहीं गए हालांकि स्टालिन के साथ भी उनके मतभेद रहे हैं, जिन्हें वह राजनीति में देर से आने वाला व्यक्ति मानते हैं। बहरहाल लोक सभा चुनावों के बाद द्रमुक में पार्टी के विस्तार के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति बनाई गई, जिसमें उन्हें रखा गया था। इससे लगता है कि सब कुछ भुला दिया गया है और उन्हें माफ कर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट है कि उदयनिधि के मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले नेहरू वही गलती नहीं दोहराना चाहते। उन्होंने भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और ऐसा हुआ तो 'हम सब खुश होंगे।' किंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा कि स्टालिन 'किसी को भी उप मुख्यमंत्री' बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।

अब कुछ बातें उदयनिधि के बारे में भी। सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी के बाद वह देश भर में सुर्खियों में आ गए। उन्होंने सनातन धर्म को जाति व्यवस्था के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए उसकी तुलना संक्रामक रोग से कर दी और उसका सफाया करना जरूरी बताया। इस पर मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी खिंचाई की मगर उदयनिधि ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और वह देश भर की अदालतों में मुकदमे लड़ रहे हैं। उन्होंने तमिल फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें उन्हें थोड़ी-बहुत सफलता मिली। उन्होंने फिल्म निर्माण कंपनी रेड जाइंट्स भी शुरू की और 2021 के विधानसभा चुनावों के समय राजनीति में उतर गए। वह चेन्नई के चेपक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए।

किंतु स्टालिन को शायद खुद ही अपने पुत्र की स्वीकार्यता और गंभीरता पर संदेह है। वह एक से ज्यादा बार कह चुके हैं कि उदयनिधि अभी इस जिम्मेदारी के लिए 'तैयार' नहीं हैं। मगर वह यह भी मानते हैं कि पार्टी में उनका कद बढ़ाने की 'मांग बढ़ी' है। द्रमुक के जनक एम करुणानिधि ने स्टालिन को अपने मंत्रिमंडल में तब शामिल किया जब वह 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे। 2009 में जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया तब वह 55 वर्ष के थे। करुणानिधि 2018 में निधन तक पार्टी के मुखिया बने रहे।

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उदयनिधि नहीं तो भला कौन? इसके जवाब में 86 वर्ष के दुरईमुरगन का नाम उठता है, जो अभी जल संसाधन मंत्री हैं। उनकी उम्र से चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस उम्र में भी उनके बाल पूरी तरह काले हैं। अगस्त में बतौर विधायक उनके 53 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह पहली बार 1971 में कटपडी विधानसभा से जीते और आठ बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह दो बार रानीपेट से भी विधायक रहे। पार्टी में कुछ ही लोग हैं जो उनकी वरिष्ठता या वफादारी को चुनौती दे सकते हैं।

परंतु उदयनिधि को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। उनसे वरिष्ठ लोग सोच सकते हैं कि उन्हें एक नेता के रूप में अभी और मंझना है। किंतु कांग्रेस जैसे गठबंधन साझेदार के नेता भी मानते हैं कि वह उस पार्टी में उत्तराधिकारी के रूप में स्वाभाविक पसंद होंगे, जहां उत्तराधिकार का संघर्ष किसी लंबे धारावाहिक से कम नहीं चलता। द्रमुक की राजनीति हमेशा दिलचस्प होती है और आने वाले दिनों में यह और रोचक होने जा रही है।

आपका पक्ष

बड़े परिवर्तनों की प्रतीक्षा में भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए भाषण में अपने वर्तमान कार्यकाल में बड़े बदलावों की ओर संकेत दिया है। समान नागरिकता कानून और एक देश एक चुनाव के साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत देश में चुनावों में एक तिहाई नारीशक्ति की भागीदारी देश को नई दिशा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि राजनीति में वे युवा सम्मिलित हों जिनके परिवार राजनीति से बाहर रहे हों, राजनीतिक पटल पर गहरा प्रभाव डालेगा क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में केवल कुछ परिवारों का ही वर्चस्व है। यह भी आवश्यक है कि शिक्षित युवा, किसान, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, उद्यमी राजनीति में आएं जो राजनीति की दिशा और दशा को बदल सकें। अल्पसंख्यक और वंचित वर्ग से भी शिक्षित युवा राजनीति में आने चाहिए जो शिक्षा, रोजगार, स्वावलंबन के लिए ध्येयनिष्ठ होकर कार्य करें और आज की विघटनकारी, कट्टरपंथी, जातिवादी, जोड़तोड़ की राजनीति से समाज को मुक्ति दिलाएं। समान नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को एक आधिकारिक विस्तृत प्रश्नोत्तरी सरकारी घोषणा के साथ लाना चाहिए जिसने समाज के सभी वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यक, आरक्षित और आदिवासी समाज की सभी आशंकाओं का स्पष्टीकरण और समाधान हो और किसी प्रकार की निर्मूल आशंकाएं, अफवाह, झूठ, नकारात्मक विमर्श न प्रचारित हो सकें। ये बहुत संवेदनशील विषय हैं और दुर्भावनापूर्ण प्रचार से देश में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। एक देश एक चुनाव भी कठिन प्रशासनिक और विधायी प्रक्रिया है परंतु देश में प्रगति के मार्ग में बार बार के चुनाव बड़ी बाधा हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'सदैव अटल' में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की छठी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

डॉक्टरों को राजनीति नहीं मिले न्याय

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 9 अगस्त को एक डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के बाद विरोध- प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश के डॉक्टर इस घटना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और डॉक्टरों से जुड़े विभिन्न संगठनों ने भी उनका समर्थन किया है। पिछले एक सप्ताह से जारी विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे देश में मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की यह घटना दिल्ली में वीभत्स निर्भया कांड को याद दिलाती है। हालांकि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के साथ आरोपी को कड़ी सजा दिलाने की पुरजोर कोशिश होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आरोपी को बचाने तथा मामले की लीपापोती की भी अलग से जांच होनी चाहिए। अगर डॉक्टर इसी तरह हड़ताल पर लंबे समय तक रहेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए तथा डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए। वैसे भी देश में एक डॉक्टर पर मरीजों की संख्या अंतराष्ट्रीय मानक से काफी ज्यादा ही है। केंद्र सरकार को मामले में दखल देकर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को अपनी तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान-डी 3 के जरिये भू प्रक्षेण उपग्रह ईओएस-08 का प्रक्षेपण किया। इसरो ने भू प्रक्षेण और एसआर-ओ डेमोसैट उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। रॉकेट को पूर्व निर्धारित समयानुसार सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया।

कल्पमेधा

प्राचीन धर्मों ने कहा है कि नास्तिक वह है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह है, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता।

- विवेकानंद

जम्हूरियत का जश्न

आखिरकार जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गईं। वहां दस वर्ष बाद चुनाव होने जा रहे हैं। स्वाभाविक ही, वहां के राजनीतिक दलों में उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल, वहां चुनाव न कराए जा सकने की वजह से लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थम-सी गई थी। राजनीतिक गतिविधियां भी ठहरी हुई थीं। इसलिए मांग की जा रही थी कि जितना जल्दी हो सके, वहां चुनाव कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि तीस सितंबर तक वहां चुनाव करा लिए जाएं। अब निर्वाचन आयोग ने तीन चरण में वहां चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। लंबे समय बाद वहां इतने कम चरण में चुनाव होंगे। हालांकि इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के लिए भी मतदान होंगे, जो एक ही चरण में कराए जाएंगे। मगर सबकी नजर जम्मू-कश्मीर पर बनी हुई है। वहां परिसीमन का काम पिछले वर्ष ही पूरा कर लिया गया था, जिसमें तीन नई सीटें जुड़ गई थीं। अब वहां भी नब्बे सीटें हो गई हैं। हालांकि परिसीमन को लेकर वहां के राजनीतिक दलों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया था और उनका आरोप था कि उनसे सुझाव नहीं लिया गया। मगर अब वह असंतोष थम गया लगता है।

किसी भी राज्य को लंबे समय तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने से वहां के विकास कार्यों पर तो बुरा असर पड़ता ही है, नागरिकों का लोकतंत्र पर भरोसा भी कमजोर होने लगता है। दस वर्ष पहले हुए पिछले चुनाव में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, तो भाजपा से सहयोग से पीडीपी ने सरकार बनाई थी। वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। समय से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया और वहां राज्यपाल का शासन लगा दिया गया था। उसके एक वर्ष बाद विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद से वहां उपराज्यपाल का शासन चला आ रहा है। केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही कि वह जल्द वहां चुनाव करा कर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटा देगी। मगर स्थितियां सामान्य न होने के तर्क पर चुनाव टलते रहे। माना जा रहा था कि लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएंगे, मगर निर्वाचन आयोग ने अलग से चुनाव कराना उचित माना। देर से ही सही, अब निर्वाचन आयोग की परीक्षा है कि वह किस प्रकार वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है।

कई मामलों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा जम्मू-कश्मीर संवेदनशील राज्य है। वहां हर वक्त आतंकी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। कई लोगों का मानना है कि अगर विधानसभा चुनाव ठीक से संपन्न होंगे, तो आतंकी गतिविधियों पर विराम लगाने में भी कामयाबी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला, उससे उम्मीद की जाती है कि जम्हूरियत के जश्न में लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई है। अब निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती यह है कि वह इस चुनाव में पारदर्शिता बरते। लोकसभा चुनाव को लेकर उसे कई प्रकार के आरोपों का सामना करना पड़ा, जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनसे सबक लेते हुए वह जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों को सचमुच जम्हूरियत का जश्न बनाने में कामयाब होगा।

प्रतिगामी सत्ता

दुनिया भर में तालिबान को कट्टर धार्मिक विचारधारा और प्रतिगामी मूल्यों के वाहक के तौर पर ही जाना जाता है। मगर उम्मीद की जाती थी कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद उसके भीतर कुछ बदलाव आएगा और वह देश के समग्र विकास की दिशा में सोचेगा। अफसोस कि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है, जिससे वहां के लोगों, खासकर महिलाओं में अपने बेहतर जीवन और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में बताया गया है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद कम से कम चौदह लाख लड़कियों को जानबूझ कर माध्यमिक शिक्षा से वंचित कर दिया है। यूनेस्को के मुताबिक, पिछले वर्ष अप्रैल में हुई गणना के बाद इसमें तीन लाख की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसमें उन लड़कियों की संख्या भी जोड़ ली जाए, जो प्रतिबंध लागू होने से पहले स्कूल नहीं जा रही थीं, तो अब देश में लगभग पच्चीस लाख यानी अस्सी फीसद लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।

इस तरह, अफगानिस्तान का समाज एक तरह से अधूरे विकास के दौर से गुजर रहा है, जिसमें वहां की महिलाओं की पढ़ाई-लिखाई को धर्म और परंपरा के खिलाफ माना जाता है। हालांकि 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था, तो उसने कठोर इस्लामी शासन से राहत देने का आश्वासन दिया था। मगर अगले ही वर्ष वहां लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में नहीं जाने दिया गया और उनके अकेले लंबी यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि वहां की महिलाओं का जीवन कैसा होगा। विचित्र है कि एक ओर तालिबानी शासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की इच्छा रखता है, लेकिन दूसरी ओर वहां की महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई तक से वंचित रखना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तालिबान अपनी महिलाओं को हर दायरे से बाहर रख कर भले अपनी तथाकथित परंपरा को बचा लेने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह वहां एक अधूरा समाज बनेगा, जिसमें महिलाओं का जीवन दोयम दर्जे का होगा। कोई भी समाज महिलाओं को हाशिये पर रख कर मानवीय होने का दावा नहीं कर सकता।

गिरते भूजल से बढ़ती मुसीबतें

यह पहला अवसर नहीं है, जब पंजाब के भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे अध्ययन हो चुके हैं और हर बार खराब होते भूजल के खतरों से आगाह किया गया है।

अमरपाल सिंह वर्मा

पंजाब का भूजल एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक अध्ययन और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में दिया गया एक जवाब है। दोनों का सार एक ही है कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। कई जिलों का भूजल लोगों को बीमार कर सकता है। अंदेशा है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पंजाब का भूजल सूख जाएगा। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अध्ययन के मुताबिक पंजाब में, खासकर मालवा क्षेत्र के लोगों को उच्च 'टीडीएस' वाले भूजल और उथले कुओं (60 मीटर से कम गहरे) का पानी पीने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें उच्च स्तर के जहरीले प्रदूषक, खासकर यूरेनियम और फ्लोराइड पाए गए हैं। दूषित भूजल पीने से वयस्कों और बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इससे पता चलता है कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों- फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा और बरनाला में भूजल मानव उपभोग के लिए बेहद असुरक्षित है। इन क्षेत्रों में उथले कुएं पीने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हैं।

हाल में केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पंजाब का भूजल अब पीने योग्य नहीं रह गया है। कई जिलों के पानी में घातक धातु का मिश्रण है, जिससे कैंसर हो सकता है। मंत्री ने बताया है कि भूजल के नमूनों में नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, सेलेनियम, क्रोमियम, मैगनीज, निकल, कैडमियम, लेड और यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्त्व पाए गए हैं।

यह पहला अवसर नहीं है, जब पंजाब के भूजल को लेकर कोई अध्ययन हुआ है। पहले भी कई बार ऐसे अध्ययन हो चुके हैं और हर बार खराब होते भूजल के खतरों से आगाह किया गया है। पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित आइआइटी ने एक शोध में चेताया था कि पंजाब के 94 फीसद लोग जिस भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह दूषित हो चुका है। यह अनेक रोगों का कारण बन रहा है। आइआइटी ने अपने अध्ययन में पिछले बीस वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया था। उसमें पाया गया कि पंजाब के भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है और अब यह इतना नीचे जा चुका है कि पानी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। शोध के अनुसार पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है।

वर्ष 2021 में आइआइटी कानपुर के एक शोधपत्र में भी गिरते भूजल स्तर की समस्या को दर्शाया गया था। उसके मुताबिक पिछले चार-पांच दशक में पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिर गया है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर और पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के अध्ययनों में भी खराब होते भूजल की जानकारी मिलती है। इससे पहले 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड की ओर से पंजाब में प्रखंडवार भूजल संसाधन मूल्यांकन में पाया गया था कि पंजाब के ज्यादातर जिलों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। कुछ जिलों में गिरते भूजल स्तर को गंभीर माना गया था।

अब तक हुए सभी शोधों में एक बात समान है कि इस संकट का सबसे बड़ा कारण अत्यधिक भूजल दोहन है। पंजाब एक कृषि बहुल सूबा है। यहां की 74 फीसद से अधिक सिंचाई की आवश्यकता भूजल से पूरी होती है। वहां एक तरफ अत्यधिक भूजन दोहन हो रहा है, दूसरी तरफ खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन भूजल में मिल कर उसे जहरीला बना रहे हैं। विभिन्न शोधों से पुष्टि होती है कि पंजाब के भूजल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रेट और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ गई है। इससे लोग विभिन्न रोगों के शिकार हो रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार मध्य पंजाब के अधिकांश स्थानों पर भूजल स्तर पहले ही 150-200 मीटर तक पहुंच चुका है। अगर ऐसा ही रहा तो वर्ष 2039 तक इसके 300 मीटर से नीचे गिरने का अंदेशा है।

> **अब तक हुए सभी अध्ययन जहां पंजाब में भूजल प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वहीं नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2019 की एक रपट में तो यहां तक कहा गया कि अगर भूजल दोहन की मौजूदा दर जारी रही, तो आगामी 22 वर्षों में राज्य का इस्तेमाल करने लायक भूजल खत्म हो जाएगा। बोर्ड की इस रपट को पांच साल बीत चुके हैं। इस दौरान इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।**

विभिन्न शोधों में अत्यधिक भूजल दोहन की बड़ी वजह धान की खेती को माना जाता है। कृषि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भूजल संकट से निपटने के लिए धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के पक्ष में हैं, पर किसान इसकी खेती इसलिए करने पर मजबूर हैं कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। कपास की खेती गुलाबी सुंडी और सफेद मक्खी के प्रकोप ने तबाह कर दी है। इसलिए अब कपास का रकबा घट रहा है। पंजाब के किसानों को धान से अच्छी आमदनी हो रही है। अगर वे धान के बजाय दूसरी फसलों की खेती शुरू भी कर दें तो उन्हें उनकी सुनिश्चित खरीद और वाजिब दाम मिलने को लेकर अंदेशा है। कुछ विशेषज्ञ खेती के लिए मुफ्त बिजली को अत्यधिक भूजल दोहन की वजह बताते हैं। वे सलाह देते हैं कि अगर नलकूपों के लिए सरकार मुफ्त बिजली देना बंद कर दे तो भूजल दोहन में कमी आ सकती है। उधर, सरकारों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कोई भी सरकार मुफ्त बिजली बंद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। विशेषज्ञ सूबे की नहर आधारित सिंचाई तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए ब्रिटिश काल की नहर प्रणालियों को फिर से तैयार करने पर जोर दे रहे हैं।

अब तक हुए सभी अध्ययन जहां पंजाब में भूजल प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति दर्शाते हैं, वहीं नीति निर्माताओं को जल्द सार्थक कदम उठाने के लिए आगाह भी करते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2019 की एक रपट में तो यहां तक कहा गया कि अगर भूजल दोहन की मौजूदा दर जारी रही, तो आगामी 22 वर्षों में राज्य का इस्तेमाल करने लायक भूजल खत्म हो जाएगा। बोर्ड की इस रपट को पांच साल बीत चुके हैं। इस दौरान इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है।

शोधकर्ताओं ने समय-समय पर हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सामुदायिक स्तर पर 'रिवर्स आस्मोसिस' (आरओ) संयंत्र स्थापित करने, सामुदायिक जल भंडारण टैंकों में नहर के पानी के साथ भूजल को मिलाने और घरों में आरओ आधारित जलशोधक स्थापित करने के सुझाव दिए हैं। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अध्ययन से सामने आए सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत पर बल दिया है। विश्वविद्यालय ने प्रभावी जल प्रबंधन और उपचारात्मक रणनीतियों को विकसित और लागू करने के लिए भूजल निगरानी बढ़ाने के लिए कहा है। जितने भी आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा विशेषज्ञों ने की है, उन्हें धरातल पर उतारने के लिए जल्द ही काम करना होगा। इसके लिए जहां किसानों और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है, वहीं सरकारी एजंसियों, उद्योगों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों का समन्वित सहयोग भी लेना होगा। यह एक ऐसी समस्या है, जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा, तो पंजाब के साथ पूरा देश इसके दुष्परिणाम झेलेगा। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर पंजाब का भूजल सूख गया तो यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

आधी जीत आधी हार

लोकेंद्र सिंह कोट

खेल हमारे बहुत करीब होते हैं, क्योंकि पराक्रम हमारे अंदर से उसी के माध्यम से प्रकट होता है। यों तो हर खेल जीत या हार के लिए ही रचा गया और अपने अंदर के पराक्रम, वीरता को सुशोभित करने के लिए ही खेल को प्रत्येक संस्कृति में रचाया-बसाया गया। शारीरिक श्रम से श्रेष्ठ रक्त संचालन, स्फूर्ति, मानसिक क्रियाशीलता बढ़ाने और आपसी सामंजस्य, एकता, सौहार्द के संप्रतीक खेल खेलने वाले के साथ-साथ देखने वाले के लिए भी जीवन का पर्याय बन पड़ते हैं। हार के करीब जाकर जीत का अनुभव हमारी तत्रिकाओं को विशेष प्रोत्साहन देता है। कभी हमारी भृकुटियां तन जाती हैं, तो कई बार उत्साह कई गुना हो जाता है। प्रार्थना या दुआओं में जुड़े हाथ बड़ी हुई धड़कनों के साथ कितनी बार ऊपर वाले को पुकारते हैं, पता नहीं। इस अर्थ में कहें तो क्या ऊपरवाला भी सोचता होगा इस तरह के खेल के चक्कर में कि मुझे धर्मसंकट में डाल रहा है, गजब है!

आमतौर पर किसी खेल में दो देशों की मजबूत टीमों के बीच मैच होता है, तो रोमांच बना रहता है। जीतने और हारने को लेकर उत्सुकता जिस स्तर की होती है, वह दर्ज करने के लायक होती है। मगर इसके विपरीत कोई मैच अगर किसी कमजोर मानी जाने वाली से हो तो जीत भले ही बड़ी हो, मगर जीतने पर शायद उतना उत्साह नहीं होता। हमारी बुराई और अच्छाई में कई बार महीन-सा अंतर गौर किया जा सकता है। ऐसे ही जीवन की कल्पना सभी के लिए, जहां सब स्वीकार्य हो। जीवन को भी करीब से देखा जाए, तो ऐसे ही कोई हमारे लिए बुरा है और कोई अच्छा। अच्छा जीत से संबद्ध है, तो हार बुराई से। समय गुजरने के साथ कई बार बुरे लोग भी उतने बुरे नहीं रह जाते या अच्छे हो जाते हैं और जो अच्छे हैं, वे कई बार बुरे हो जाते हैं। जीवन बहुत ही मायावी है, किसी रोमांचकारी खेल की तरह। कभी कोई जीतता है तो कभी कोई हारता है। अगर पता हो कि कौन पक्ष जीतेगा तो एक ईमानदार खेल प्रेमी के भीतर उस खेल के मैच को लेकर कोई उत्साह नहीं पैदा होगा। इसी तरह जीवन भी है। सरलता से मिली सफलता और जीतोड़ मेहनत कर मिली सफलता में भी उतना ही अंतर है। जो जीत ठोकरें खाकर मिलती है, वह सिखाती इतना है कि जीवन तर जाता है। वह गर्व को महसूस कराती है। वहीं सीधे और आसानी से मिली सफलता सिखाती भी कम है और उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। वह घमंड लाती है।

> **जीवन बहुत ही मायावी है, किसी रोमांचकारी खेल की तरह। कभी कोई जीतता है, तो कभी कोई हारता है। अगर पता हो कि कौन पक्ष जीतेगा, तो एक ईमानदार खेल प्रेमी के भीतर उस खेल के मैच को लेकर कोई उत्साह नहीं पैदा होगा। इसी तरह जीवन भी है। सरलता से मिली सफलता और जीतोड़ मेहनत कर मिली सफलता में भी उतना ही अंतर है।**

किसी मैच में जीत ने मन के समीकरण ही बदल दिए। एक अलग उत्साह और एक-एक पल की चर्चा। 'यह नहीं किया होता तो वह नहीं होता' जैसे विश्लेषण उस खेल को पराकाष्ठा तक पहुंचा देते हैं और मन के किसी कोने में मन यह भी कह रहा होता है कि सामने वाली टीम भी शानदार और प्रतिबद्ध होकर खेली। वास्तव में उसकी प्रतिबद्धता ने ही हमारे उत्साह को इतना ज्यादा कर रखा है। प्रतिद्वंद्वी टीम की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता ने ही हमें यह अपार खुशी दी है और इस तरह एक टीम हार कर भी परोपकार कर रही है। इसलिए कोई भी हारने वाली टीम के साथ एक गोपनीय-सी सहानुभूति जुड़ ही जाती है। यह सही है कि किसी भी खेल में कोई भी टीम कभी भी हारना नहीं चाहती, मगर व्यवहार में सच यह है कि कोई एक टीम हार कर किसी एक को जीतने का मौका दे रहा होता है। इसलिए प्रत्येक हार आधी हार है और प्रत्येक जीत आधी जीत।

जीवन में भी कई तरह की प्रतिद्वंद्विता रहती है और जब भी हमारा प्रतिद्वंद्वी किसी भी जगह हारता है, कुछ गलत करता है, गिर जाता है तो हमें एक छिपी हुई राहत मिलती है। बल्कि इससे ज्यादा कई बार अपने प्रतिद्वंद्वी की हार से खुशी होती है। यह एक आम मानवीय कमजोरी है। मगर उस थोड़ी-सी खुशी को पाने के लिए उस प्रतिद्वंद्वी को हमें अपने अंदर कितना समाया हुआ रखना पड़ता है! उसके पल-पल की खबर के साथ हमारे अंदर कहीं न कहीं वह जी रहा होता है। हम खुश होकर भी बहुत कुछ हार रहे होते हैं। हम भी अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह ही बनने लगते हैं और उसका जाप करते हुए एक दिन हम उसी की तरह बन जाते हैं। उसके बाद दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। जीवन का खेल ही निराला है। इसलिए संत कहते हैं कि इस जीवन को खेल समझो, उसमें ज्यादा संलग्न मत रहो, वरना यह जुनून कहीं का नहीं छोड़ेगा।

किसी खेल के मैच के बहाने एक ही सवाल मन में घूमने लगा है कि अब खेल क्या वास्तव में खेल रह गए हैं! घनघोर व्यावसायिकता के चलते 'जेंटलमेन्स गेम' अब 'जेंटल' न होकर अपनी अलग ही शक्ल ले चुके हैं। कई बार बेचारा खेल तो हाशिये पर होता है और मध्य में दौड़ता रहता है सिर्फ पैसा। सट्टेबाजी के आरोपों, आपसी छीटाकशी, मारपीट के प्रकरण और ऐसे विज्ञापनों की होड़, जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मगर इनके बीच से निकलकर खेल शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व विकास का अपना मूलभूत संदेश वे भी पा रहे हैं या नहीं। यह भी जरूर हो गया है कि खेल से ज्यादा उसके आसपास का आभामंडल ही आजकल के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। किसी ने कहा है कि एक खिलाड़ी हमेशा सच्चा और ईमानदार होता है। लेकिन वर्तमान में यह उक्ति कितनी ठीक बैठती है, उस पर विचार करना आवश्यक है।

दुनिया मेरे आगे

प्रकृति से समन्वय

यह सच्चाई है कि जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के चलते हमारी खाद्य श्रृंखला को विभिन्न प्रकार के अप्रत्याशित और अभूतपूर्व खतरे पैदा हो गए हैं। इस महत्त्वपूर्ण विषय में जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी समिति की ताजा रपट में भी चेताया गया है। हालांकि देश के विद्वान कृषि विज्ञानी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों का अध्ययन करके आगामी खतरों से निपटने के प्रबंध करने में व्यस्त हैं, फिर भी बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत यह खतरा भी लगभग स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को इस प्रकार समझा जा सकता है कि वर्तमान में किसी भी सब्जी या फल का कोई मौसम नहीं रह गया है। हर सब्जी और फल लगभग साल भर और हर मौसम में उपलब्ध होता है। शायद यही कारण है कि लगभग प्रत्येक सब्जी या फल का स्वाद भी बदल गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि क्षेत्र और फसलों की पैदावार में भी बदलाव आ सकता है। पर वे सब परिवर्तन हमें जीवन के बुनियादी ढांचे की तरफ लौटने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जीवन केवल अपनी मर्जी से नहीं चलता, इसके लिए प्रकृति से समन्वय भी आवश्यक है।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

जोखिम के बीच

कोलकाता में एक जूनियर डाक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना ने एक बार फिर इस तथ्य की ओर ध्यान खींचा है कि अस्पतालों में डाक्टरों को किस तरह के खतरों के बीच काम करना पड़ता है। देश में डाक्टर की सुरक्षा के लिए सख्त कानून मौजूद होने के बावजूद थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद निर्भया कांड जैसी त्रासद घटना की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को हर जगह नई तकनीकें, एआइ से लैस कैमरे लगाने होंगे। साथ ही वहां महिलाओं को मिर्च पाउडर जैसी प्राथमिक सुरक्षात्मक उपाय और इस तरह की अन्य वस्तुएं रखनी चाहिए, ताकि विकट स्थिति में वह अपराधियों का मुकाबला कर सके। दूसरी ओर, डाक्टरों का विरोध उचित है, मगर हड़ताल से हजारों मरीजों को जिस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसकी जवाबदेही पर फिरकाना ध्यान है। फांसी की सजा होने के बावजूद अगर अपराधी बेखौफ है, तो यह पुलिस प्रशासन की कमजोरी का नतीजा है।

- विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

वृक्षों का खयाल

प्राचीन वृक्षों को, जो खोखले या गिरने की कगार पर हों, उनका उपचार किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतु में तेज हवा या आंधी से कमजोर वृक्ष गिर जाते हैं, उनका उपचार किया जाना चाहिए, ताकि जानमाल की हानि से बचा जा सके। बरगद के पेड़ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी आयु काफी लंबी होती है। पशु-पक्षियों और इंसानों के लिए ये घने वृक्ष छांव के साथ सुखद आसरा प्रदान करते हैं। इसे लगाने से प्रतीक्षालय बनाने के खर्चे का भार भी कम होगा। वृक्षारोपण के साथ पौधों की देखभाल भी आवश्यक है। वृक्षों को प्राचीन समय से लोग पूजते आ रहे हैं तो इसके पीछे मुख्य कारण भीषण गर्मी में ठंडी सुखद छांव प्राप्त होना, शुद्ध हवा, उदर-पोषण, सांस्कारिक जीवन के अंतिम पड़ाव में दाह-संस्कार में उपयोगी बनना, पृथ्वी के तापमान को कम और वर्षा के बादलों को अपनी ओर आकर्षित कर वर्षा कराना, दैनिक जीवन की आवश्यकता की आर्थिक रूप से पूर्ति करना पेड़ का कर्तव्य माना जाता है।

- संजय वर्मा 'दृष्टि', धार, मप्र

चुनौती के सामने

हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन को अच्छी कामयाबी मिली है, जबकि भाजपा 2019 का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई। हरियाणा में किसान आंदोलन और अग्निपथ बड़े मुद्दे रहेंगे, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन के कारण भाजपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। जम्मू-कश्मीर में जनता 370 के खिलाफ दिखाई देती है और आतंकवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा चुनावी घमासान महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, जहां सभी राजनीतिक दल दो धड़े में बंट जाएंगे। भाजपा के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की ओर से पेश चुनौती का सामना स्थानीय नेताओं द्वारा किया जाएगा।

- वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 17 अगस्त 2024

आयोग का अच्छा क़दम

370 हटने के बाद पहला असेंबली चुनाव

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान कर दिया। पिछले लोकसभा चुनावों के अनुभव की रोशनी में यह देखना सुखद है कि इस बार आयोग ने चुनावों की अवधि को काफी छोटा रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की समयसीमा | पिछले पांच वर्षों से निर्वाचित सरकारों से वंचित जम्मू-कश्मीर में चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर अधिकतम 30 सितंबर की समयसीमा भी तय कर दी थी। यह अच्छा है कि उसका सम्मान करते हुए इलेक्शन कमिशन ने चुनावों की समयसीमा खत्म होने से काफी पहले शुरू कर दी, लेकिन आखिरी चरण का मतदान एक अक्टूबर तक खिंचने से, फिर भी नहीं बचा जा सका।

कश्मीर-हरियाणा के चुनाव घोषित

अलग-अलग चुनाव | चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय जरूर है, लेकिन सरकार और प्रशासन के अलग-अलग स्तंभों की कार्यदेशा में न्यूनतम सामंजस्य की अपेक्षा गलत नहीं कही जाएगी। ऐसे में जब केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करती आ रही है और एक दिन पहले लालकिले से दिए गए भाषण में भी प्रधानमंत्री ने इसकी जरूरत को रेखांकित किया था, तब महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्यों के चुनाव भी साथ करवाए जाने की उम्मीद की जा रही थी। जम्मू-कश्मीर को विशेष मामला माना जाए तो भी वहां 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने के बाद छह महीने की अवधि के अंदर कार्यकाल पूरा करने वाली सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने में कोई संवैधानिक बाधा नहीं थी।

लोकतंत्र की बयार | जम्मू-कश्मीर के लिए चुनाव इस लिहाज से खास हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। इससे पहले लोकसभा चुनावों में मतदाताओं की जो उत्साहपूर्ण शिरकत देखने को मिली, उसके मद्देनजर इन चुनावों से वहां एक नए दौर की शुरुआत की उम्मीद करना अस्वाभाविक नहीं कहा जाएगा।

अलग-अलग नतीजे | हरियाणा के चुनाव इस लिहाज से दिलचस्प हो गए हैं कि लगातार दो बार सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों के नतीजे उसके मनमाफिक नहीं आए। इसके बाद वहां कांग्रेस को अपने लिए ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के नतीजे इस कदर अलग-अलग आते रहे हैं कि ऐसी उम्मीदों को एक हद से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती। कुल मिलाकर देखें तो नतीजे जो भी आएं, चुनाव हमारी लोकतांत्रिक चेतना का संदेश बनकर आते हैं। उम्मीद है कि इस बार भी यह संदेश दुनिया को अधिकाधिक मजबूती से मिलेगा।

दो टूनी चार

बैंकों को बदलना होगा

रमेश तिवारी

अरसे पहले एक बैंक मैनेजर के केबिन में बैठा था। वहां एक व्यक्ति आया, जो लॉकर में नॉमिनेशन देना चाहता था। लेकिन बैंक मैनेजर का कहना था कि आपका लॉकर पत्नी के साथ जॉइंट है, इसलिए इसमें नॉमिनेशन की क्या जरूरत? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो? बैंक अधिकारी ने कहा कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर का बयान अजीब था। तब से लेकर अब तक असंख्य घटनाएं देख-सुन चुका हूं, जिसमें पति-पत्नी क्या, पूरा परिवार असमय मौत का शिकार हो गया।

नतीजा यह है कि बैंकों में करोड़ों रुपये जमा हो गए हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं। इस साल मार्च में देखा गया कि बैंकों के पास 78,213 करोड़ रुपये पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं है। एक साल की तुलना में इसमें 26 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खातों में पड़ी रकम पर 10 या इससे अधिक वर्षों से कोई दावा करने वाला न हो, तो जमा राशि को आरबीआई के एक फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड कहा जाता है। इस फंड में भी 62,225 करोड़ रुपये पड़े हैं।

किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी ओर से जमा रकम या लॉकर उसकी ओर से नामांकित व्यक्ति हासिल कर सकता है। हालांकि नामांकित व्यक्ति संरक्षक की तरह होते हैं, जमा रकम के मालिक नहीं। कानूनी उत्तराधिकारी ही असली मालिक होते हैं। अभी तक बैंकों में केवल एक नॉमिनेशन देने की प्रथा चली आ रही है। अगर किसी नामांकित व्यक्ति की ही मौत हो जाए तो उसके पक्ष में किया गया नॉमिनेशन खत्म हो जाता है। इससे जमाकर्ताओं और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मुकदमेबाजी को भी बढ़ावा मिलता है।

कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को कैसे बांटे, इसके लिए वसीयत की दरकार होती है। हालांकि वसीयत की इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया आज भी कष्टदायक देखी जाती है। इसमें भी तत्काल सुधार की जरूरत है। वसीयत को कानूनी चुनौती दिए जाने पर प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है। ये डिमांड की जा रही है कि नामांकित व्यक्तियों को ही संपत्तियों में कानूनी रूप से मालिक के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए।

अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंक में खाता रखने वालों को अब ये सुविधा मिलेगी कि वो चार लोगों का नॉमिनेशन दे सकें। ये चारों एक के बाद एक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि पहला व्यक्ति क्लेम करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो नॉमिनेशन के क्रम में दूसरे दूसरे नामांकित व्यक्ति को बुलाया जाएगा। दूसरा न रहे तो तीसरा, फिर तीसरा न रहे तो चौथे को बुलाया जाएगा। कोई चाहे तो चारों को एक साथ भी रख सकता है। ये पहले ही तय कर दिया जाएगा कि चारों को किस अनुपात में जमा धन दिया जाएगा। हाल में संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया गया, जिसमें ये प्रावधान है।

इस मोर्चे पर अभी कई काम होने बाकी हैं। बैंक में हर जमा के लिए अलग क्लेम की जगह सेंट्रलाइज्ड क्लेम की व्यवस्था होनी चाहिए। नॉमिनेशन देने या उसमें बदलाव करने की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होनी चाहिए। नॉमिनी का वेरिफिकेशन संभव हो तो जमाकर्ता के जीते जी कर लेना चाहिए।

ऑफ दि ट्रैक

चांद पर जीवन

दिलीप लाल

इंसान का सबसे बड़ा सपना है चांद और मंगल पर बसना। इलॉन मस्क जैसे कुछ उद्योगपतियों को तो पूरी उम्मीद है कि यह सपना जल्द ही हकीकत में बदलेगा। इसमें कितना वक्त लगेगा, इस बारे में फिलहाल कोई डेडलाइन तो तय नहीं की जा सकती, लेकिन इस बीच साइंस कम्युनिटी से आए एक सुझाव के चलते नई हलचल पैदा हो गई है। हम ने नूह की कहानी सुनी है कि कैसे उन्होंने धरती पर आई बाढ़ से जीवन को बचाने के लिए ईश्वर के आदेश पर एक बड़ी नाव का निर्माण किया, जिस पर दुनियाभर की प्रजातियों को शरण मिली। नाव तो नहीं, लेकिन कैसा हो कि एक स्पेस शिप विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके जीव-जंतुओं के फ्राइज़ोब्लास्ट सेल्स को लेकर चांद के लिए उड़ान भरे। अमेरिका के नैशनल ज़ूलॉजिकल पार्क की साइंटिस्ट Mary Hagedorn यह अनोखा आइडिया लेकर आई हैं। उनका कहना है कि धरती पर बदल रही जलवायु के चलते 10 लाख से अधिक प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। समय रहते कुछ न किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां इनको केवल तस्वीरों में देख पाएंगी। चूंकि धरती का मौसम तेजी से बदल रहा है, ऐसे में कोशिकाओं को प्रिजर्व करने के लिए चांद के क्रेटर्स सबसे मुफीद जगह है, जहां प्राकृतिक रूप से तापमान बहुत कम होता है। बाद में, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के जरिये क्लोनिंग की मदद से उस जीव को दोबारा बनाया जा सकता है। मैरी जिस तकनीक से सेल्स को सुरक्षित रखने की बात कर रही हैं, उसे cryopreservation कहते हैं।

चुनावी राजनीति के तक़ाज़ों ने जातिवादी जकड़नों को मज़बूती दी है

सियासत ने बढ़ाई जाति की खाई?

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय राजनीति और समाज में जाति बहुत पेचीदा मुद्दा रहा है। जाति व्यवस्था को सामाजिक कोढ़ बताने वालों का मानना था कि विकास और आधुनिकता के आने से जाति व्यवस्था अपने आप टूटती जाएगी। गांधी मानते थे कि अछूतोद्धार के जरिए समाज में बराबरी का संदेश जाएगा। उन्होंने इसकी कोशिश भी की। दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर मानते थे कि सामाजिक विकास यात्रा में पीछे छूट गए लोगों को आरक्षण देकर पहले सबल बनाया जाना चाहिए। वह तबका सबल होगा तो जाति व्यवस्था में बराबरी का भाव आएगा।

कांशीराम की सोच | लोहिया सोचते थे कि पिछड़ों को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाकर आगे लाया जाए तो सामाजिक समानता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही सोच दीनदयाल उपाध्याय की भी रही। लेकिन बहुजन आंदोलन के अगुआ कांशीराम की मान्यता रही कि पिछड़ों और दलितों को सत्ता मिले तभी जाति टूटेगी।

वोट बैंक का असर | चारों वैचारिकी के आधार पर देखें तो सामाजिक रूप से जाति टूटती नजर आ रही है, लेकिन जैसे-जैसे आरक्षण की राजनीति आंबेडकर की बुनियादी सोच से आगे बढ़ने लगी, राजनीतिक रूप से जातियां अपने-अपने दायरे में और मजबूत होती गईं। 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी' की सोच बढ़ने लगी। इसलिए हर जाति नए सिरे से गोलबंद होने लगी। अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और बढ़ाने के लिए ये जातियां अपने किले को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत करने लगीं। वोट बैंक की राजनीति ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।

जाति तोड़ने की सोच | सत्ता के लिए बहुमत हासिल करने के लक्ष्य को लेकर लगातार सक्रिय राजनीति ने जातीय समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में उनकी मांगों को उछालना शुरू किया। हर राजनीतिक समूह अपने हिसाब से अपनी समर्थक जातियों की राजनीतिक मांगों को जायज ठहराने लगा। इस पूरी प्रक्रिया में सामाजिक रूप से जाति को तोड़ने की सोच पीछे छूटती चली गई। दिलचस्प यह है कि जब कोई जातीय समूह किसी खास राजनीतिक ताकत का साथ छोड़ने लगा तो उसके हक और अधिकारों की मांग उस राजनीतिक ताकत के लिए गौण होने लगी। पूरी भारतीय राजनीति इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रही है।

मिलता गया विस्तार | संविधान में दलितों और आदिवासी समूहों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते वक्त डॉ. आंबेडकर ने इसे अनंतकाल तक चलाने से चेताया था। संविधान में शुरुआती दस साल के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था रखी गई थी। लेकिन जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था ना सिर्फ आंबेडकर की सोच से आगे निकल गई है, बल्कि वह अनंतकाल तक चलते रहने के लिए अभिशप्त दिखती है। दरअसल जाति जनगणना की मांग राजनीतिक समूहों द्वारा जातीय समूहों को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश मात्र है कि वे उनके उस लक्ष्य के साथ खड़े हैं जसे वे जीवन-मरण का प्रश्न मानते हैं।

जाति का मुद्दा

- गांधी, आंबेडकर और लोहिया की सोच अलग
- कांशीराम ने सत्ता पर पकड़ को माना अहम
- वोट की राजनीति ने बढ़ाई जाति की जकड़

उन्माद फैलाने का भाव | चाहे गांधी रहे हों या आंबेडकर या फिर लोहिया, उनके विचारों और सिद्धांतों का बुनियादी मकसद सत्ता की राजनीति नहीं, सामाजिक समानता के जरिए भारतीय समाज का निर्माण था। लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले आधुनिक समूहों के साथ यह बात नहीं दिखती। समाजवादी धारा की मौजूदा राजनीति की प्रभावी ताकतों के पास भारतीय समाज बनाने का कोई ठोस सामाजिक कार्यक्रम नहीं है। उनमें जातीय उन्माद बढ़ाने और फैलाने का भाव ज्यादा नजर आता है। कांग्रेस की राजनीति अतीत में ऐसी अतिवादी नहीं रही है, लेकिन अब उसकी भी राजनीति उसी राह पर चल रही है।

सवर्णों में भी दोयम | गौर करने की बात है कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाकी जातियों को गुस्से से भरने में ये शक्तियां मशगूल हैं, उन्हीं जातीय समूहों में कुछ ऐसी जातियां भी हैं, जिनकी दोयम हैसियत रही है। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों में महाब्राह्मण और शाकद्वीपीय समुदाय को लिया जा सकता है, जिनसे सामान्य ब्राह्मण समाज भी परहेज करता रहा है। क्षत्रिय और बनिया के बीच भी ऐसी कई छोटे समुदाय हैं, जो मौजूदा जातीय विमर्श में पिछड़े नजर आते हैं। लेकिन इस राजनीति की इस ओर ध्यान देने की फुरसत नहीं है।

दरार बढ़ाती राजनीति | सच तो यह है कि जब भी जाति व्यवस्था कुछ कमजोर पड़ती दिखती है, राजनीति उसकी दरार को और बढ़ाने के लिए आगे आ जाती है। जातीय समूह भी अपने पारंपरिक भाईचारे को भूल अपने पड़ोस के ही जातीय समुदाय के खिलाफ राजनीति की ओर से पकड़ाई गई तलवार लेकर निकल पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आखिरकार सामाजिक ताना बाना ही छिन्न-भिन्न होता है। हालांकि हर राजनीतिक समूह इसी ताने-बाने को बनाए रखना अपना उद्देश्य भी बताता है।

जाति पूछने की आदत | संसद में अनुराग ठाकुर द्वारा राहुल गांधी की जाति का सवाल उठाने पर उठे राजनीतिक बवाल के बीच कुछ सवाल भी बनते हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी या अखिलेश यादव ने कभी किसी की जाति नहीं पूछी? अपनी भारत यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो वहां एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ असहज सा सवाल पूछ लिया, जिस पर उन्होंने उससे जाति पूछ ली थी। इसी तरह अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले ही साल लखनऊ में एक रिपोर्टर ने असहज सा सवाल पूछ लिया था, तो उन्होंने भी उस रिपोर्टर से उसकी जाति पूछकर जलील किया था।

कथनी-करनी का फर्क | सार्वजनिक जीवन बिताने वालों से उम्मीद की जाती है कि वह दूसरों से जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार खुद भी करें। अखिलेश हों या कांग्रेस, उनकी प्रतिक्रियाओं से उनकी चिढ़ दिख रही है। इसे राजनीति में कथनी और करनी के अंतर का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

www.nbt.in

अमरनाथ यात्रा कैसे बदली

अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे कठिन तीर्थयात्राओं में से है। तकरीबन दस साल पहले मेरी पहली अमरनाथ यात्रा हुई थी। तब पहलगाम मार्ग अवरुद्ध होने से पहले जत्थे को बालटाल मार्ग से भेजा गया था। बालटाल से लगभग दस घंटे पैदल यात्रा करके अमरनाथ गुफा पहुंचे और वहां रात्रि विश्राम किया। सुबह स्वयंभू हिमलिंग के दर्शन करके बालटाल मार्ग से ही पैदल वापसी की। खास बात है कि अमरनाथ गुफा पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता, इसलिए प्रसाद की कोई दुकान नहीं थी।

दस वर्ष बाद पिछले महीने फिर से यह पावन यात्रा करने का संयोग बना। लेकिन दस साल में कई बदलाव भी आ चुके हैं। 2014 में बैंक के जरिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था, जो 2024 में बायोमीट्रिक ऑनलाइन हो गया। इससे रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा पूरी तरह से समाप्त हो गया। पहचान के लिए प्रत्येक यात्री को चिप आधारित RFID कार्ड दिए गए। यात्रियों के लिए जम्मू में भी ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी। जम्मू पहुंच कर सबसे पहले मैंने ऑनस्पॉट रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास में पहुंचे और RFID कार्ड सत्यापन के बाद अंदर प्रवेश किया। रात्रि विश्राम के बाद सुबह चार बजे CRPF की सुरक्षा में अमरनाथ यात्रियों के वाहन पहलगाम के लिए रवाना हुए।

खुद अपनी आंख से

कुलदीप त्यागी

शिवखोड़ी में यात्री बस में आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व प्रबंध थे। जगह-जगह भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों के जवान आधुनिक हथियारों के साथ तैनात थे। पहलगाम में आर्मी बेस कैंप में पहुंच कर रात्रि विश्राम किया और यहां से जीप द्वारा हम आधार स्थल चंदनवाड़ी पहुंचे। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी में RFID सत्यापन के बाद हमने पैदल यात्रा शुरू की। बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन ने चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप की कठिन चढ़ाई को कम करके एक नया आसान रास्ता बनाया है, जिससे रास्ते की लंबाई लगभग 3.5 किमी बढ़ गई है।

रास्ते में जगह-जगह यात्रियों के लिए भंडारे लगे थे। पिस्सू टॉप से शेषनाग तक का रास्ता बहुत कठिन रहा और धीरे-धीरे करके वहां तक पहुंचे। शेषनाग झील के दर्शन करके सुरक्षा जांच के बाद हमने बेस कैंप में प्रवेश किया। अमरनाथ यात्रा में एक खास बात यह है कि यहां टेंटों और खच्चरों की पूरी व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में है। शेषनाग से अगले दिन सुबह आगे की यात्रा हर-हर महादेव के जयकारे लगाकर खच्चर से शुरू की। पंचतरणी होते हुए गुफा तक पहुंचे और भगवान शिव के हिमलिंग स्वरूप के दर्शन किए। 2022 में हुए भूस्खलन के बाद अमरनाथ घाटी में रात्रि में यात्रियों के रुकने पर प्रतिबंध है। इसलिए रात से पहले ही यात्रियों को बालटाल या पंचतरणी के लिए वापस भेजा जाता है। हमने दर्शन के बाद वापसी यात्रा शुरू की और रात डेढ़ बजे बालटाल पहुंच गए। दस साल बाद जो बदलाव दिखे, उनमें एक यह भी था कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने प्रसाद की दुकानें भी खोल ली हैं, जबकि गुफा में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता। रास्ते में और लोगों की भी प्रसाद की दुकानें दिखीं जहां 100-100 रुपए में प्रसाद बेच रहे थे।

चलते-चलते...

कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसा स्मार्ट फैब्रिक तैयार किया है, जो शरीर की गर्मी और सोलर एनर्जी से बिजली पैदा कर सकता है। साथ ही, इससे तैयार कपड़े स्मार्ट होंगे, जो शरीर के तापमान, पल्स रेट और हार्ट रेट को भी मॉनिटर करेंगे। वायरस-बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने में इससे मदद मिल सकती है।

मंदी का डर फिजूल

अमेरिका से पिछले दिनों बेरोजगारी के आंकड़े आए तो मंदी के डर से दुनियाभर के शेयर बाजार हिल गए। जापान के मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट हुई, भारत में भी निवेशकों को झटका लगा। मगर क्या US में मंदी आएगी, आइए समझते हैं :

AI image

जल्दबाजी का अनुमान | अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में हालिया गिरावट अमेरिका में मंदी के डर से ही आई। US गिरा तो मेसेज गया कि बाकी जगह भी आर्थिक झटके लगेंगे। लेकिन अभी ऐसा मानना जल्दबाजी होगी।

लेबर शॉर्टेज नहीं | सारा डर टिका है US में बेरोजगारी दर पर, जो जुलाई में बढ़कर 3 साल में सबसे अधिक 4.3% हो गई। हालांकि कोविड में कंपनियां वर्कफोर्स की कमी से जूझ रही थीं, लेकिन अब लेबर शॉर्टेज नहीं है।

5 पॉइंट

काम की तलाश | लगभग सभी विकसित देशों में Labour force participation rate बेहतर हुआ है। यानी काम की तलाश करने वाले बढ़े हैं और इससे कुछ समय के लिए बेरोजगारी दर बढ़ सकती है। लेकिन, पॉजिटिव आस्पेक्ट यह है कि जॉब ग्रोथ भी अच्छी बनी हुई है। विकसित मुल्कों में बस जापान ही अपवाद है, जहां रोजगार 0.03% घटा।

बढ़ रहा मुनाफा | मंदी की आहट पर कंपनियां का मुनाफा घटने लगता है, लेकिन दुनियाभर की कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। Deutsche Bank की रिसर्च का दावा है कि इस साल पहली तिमाही में टॉप ग्लोबल कंपनियों की कमाई 7 तिमाहियों में सबसे अधिक रही।

महंगाई कम, GDP ज्यादा | ज्यादातर अमीर देशों में विकास की रफ्तार ठीक-ठाक है। OECD देशों में जो औसत महंगाई दर 2022 में 10% थी, वह इस साल जून में 2.6% है। उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बेहतर हुई।

प्रस्तुति : शैलेंद्र पांडेय

ओली को चीन समर्थक मानना ग़लत

पूर्व विदेश सचिव के. वी. राजन नेपाल में भारत के राजदूत रहे हैं। पिछले दिनों इनकी किताब 'काठमांडू क्रॉनिकल्स' आई। नेपाल अपेक्षाकृत नया लोकतंत्र है। वहां की राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। अक्सर वहां सरकारें बदलती रहती हैं। नेपाल की राजनीति और हालिया इतिहास पर उनसे बात की ***अमन श्रीवास्तव*** *ने। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश :*

साप्ताह का इंटरव्यू

के. वी. राजन

■ नेपाल में पिछले दिनों हुई राजनीतिक उथलपुथल को कैसे देखते हैं आप? इसकी क्या प्रमुख वजहें मानते हैं?

अस्थिरता नेपाल के लिए भी खतरा है। इनवेस्टमेंट की उसे बहुत जरूरत है। लेकिन इस तरीके से अनस्टेबल होता रहा तो न तो अंद्रूनी निवेशक कुछ करेंगे, न ही बाहर के इनेस्टर्स नेपाल आने को तैयार होंगे। स्टेबिलिटी तुरंत न हो, तो भी एक विश्वास बने कि सरकार बदलने से इन्वेस्टमेंट पर कोई खतरा नहीं रहेगा। वैसे डेमोक्रेसी कहीं भी परफेक्ट नहीं है। नेपाल में गठबंधन सरकार है, बदलती रहती है। नेपाल में काफी अच्छे तरीके से लोग इसे समझते हैं।

■ आपने अपनी किताब में लिखा है कि नेपाल ने मुश्किल समय में हमेशा भारत को 'चीन कार्ड' दिखाया है। उस लिहाज से देखें तो केपी शर्मा ओली का आना दोनों देशों के आपसी संबंधों पर कैसा असर डालेगा, खासकर यह देखते हुए कि ओली की इमेज भारत विरोधी और चीन समर्थक नेता की मानी जाती रही है?

के पी शर्मा ओली को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वह एंटी इंडिया हैं और चीन के समर्थक। यह सच है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे भारत को चोट लगी है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार ओली का प्रधानमंत्रित्व काल बहुत पॉजिटिव था। ओली अच्छे से समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, नेपाल के इंटरेस्ट में क्या है और नेपाल-भारत संबंध के लिए क्या जरूरी है। मेरे समय में वह जब होम मिनिस्टर थे, कम्युनिस्ट सरकार में उन्होंने अपने पांडिया से बहुत मदद की। तब वह भारत समर्थक कहलाते थे। उनके घर पर पत्थर फेंकते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कि आप तो भारत समर्थक हैं। हमारे मीडिया वगैरह में भी हमें इस तरीके से शायद प्रजेंट नहीं करना चाहिए कि वह भारत विरोधी या चीन समर्थक हैं। यह सच नहीं है।

■ आपने किताब में लिखा है कि बहुतेरे नेपाली सोचते हैं, नेपाल के आंतरिक मसलों में हस्तक्षेप करता है भारत। यह कितना सच है?

यह परसेप्शन का सवाल है। जब नेहरू जी ने या यह तय किया कि राजा त्रिभुवन को यहां लाया जाए, राजशाही के साथ लोकशाही को भी लाया जाए, तब भारत के नजरिए से यह बहुत ही अच्छा था। भारत के लिए बहुत गुडविल थी नेपाल में। लेकिन भारत ने जब देखा कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है तो उसने यह जरूरी समझा कि नेपाल के साथ रिश्ते और मजबूत किए जाएं। नेपाल में जिस डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस की शुरुआत हुई, उस पर भारत अढ़वाइज देने के लिए तैयार था। यह मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ओलीजी के जमाने से। ओलीजी ने यही कोशिश की थी कि उनके मन में यह विचार फैला दें कि भारत असली दोस्त देश नहीं है।

■ क्या आने वाले समय में नेपाल फिर 'हिंदू राष्ट्र' बन सकता है?

यह तो नेपाल को डिसाइड करना है कि किस तरीके की आइडेंटिटी वह रखना चाहता है। नेपाल बड़े अच्छे तरीके से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, जिसमें सारे धर्म के लोग शांति से रहते थे। वैसे भी कभी वहां सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। लोकशाही में जब उनका स्ट्रक्चर बदला तो उन लोगों ने तय किया कि उनका देश सेकुलर रिपब्लिक बने। मेरे ख्याल से इस मसले पर नेपाल को ही सोचना या तय करना चाहिए। इसमें भारत का कोई रोल नहीं है।

■ एक समय शायद राजा त्रिभुवन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि क्यों न नेपाल को इंडिया में मिला दिया जाए? आज आप उस बात को कैसे देखते हैं?

राजा त्रिभुवन ने शायद ऐसा कहा होगा। यह सेंसियस प्रपोजल है या नहीं, यह किसी को नहीं पता क्योंकि लिखित कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा था कि बिना भारत के सहयोग से नेपाल की प्रगति बहुत कठिन होगी। नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने की जो बात उठ रही थी, उससे शायद राजा त्रिभुवन के भीतर एक असमंजस था कि नेपाल अभी उसके लिए तैयार नहीं है और उसे भारत की मदद की जरूरत पड़ेगी।

> केपी शर्मा ओली को इस तरह से प्रॉजेक्ट किया जाता है कि वह भारत विरोधी हैं और चीन समर्थक। सच है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे भारत को चोट लगी है। लेकिन यह भी सच है कि ओली का प्रधानमंत्रित्व काल पॉजिटिव भी था। ओली अच्छे से समझते हैं कि उनका हित क्या है और नेपाल का हित क्या है

■ यहां जो भारत विरोधी भावना दिखती है, उसके पीछे क्या है?

उसके पीछे दो कारण है। एक तो जो विश्वास होना चाहिए, नैचरल ट्रस्ट, उसमें थोड़ी-बहुत कमी रही है। दूसरी बात, दोनों देशों में शायद इसके बारे में ज्यादा विचार भी नहीं किया गया है और कोशिश भी नहीं की गई कि कैसे इन मसलों को आड़ेस किया जाए।

■ ओपन बॉर्डर होने के बावजूद भारत-नेपाल के बीच सीमा विवाद है। कालापानी और लिपुलेख बड़े उदाहरण हैं और नेपाल के 100 रुपये के नोट में नया पॉलिटिकल मैप भी...

ओपन बॉर्डर का प्रॉब्लम काफी सीरियस था, क्योंकि इसका दुरुपयोग पाकिस्तान काफी खुले तरीके से कर रहा था। इसमें भारत के विरोध में कई एक्टिविटीज चल रही थीं- स्मगलिंग, नारकोटिक्स या टेररिज्म की। इसमें पाकिस्तान का रोल काफी स्पष्ट था, लेकिन 2001 के बाद दोनों देश काफी सीरियस हुए। उन्होंने बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में काफी गंभीरता से सोचा और उसमें कई इंप्रूवमेंट आए हैं। लेकिन इस बिंदु पर यह बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ओपन बॉर्डर दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा असेट भी है, क्योंकि ये दोनों को बहुत फायदा देता है। वैसे भी दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते के बारे में हम कहते हैं तो उसके पीछे भी यह ओपन बॉर्डर ही है। ओपन बॉर्डर के कारण ही एक बहुत ही यूनीक संबंध बन जाते हैं। इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे रिश्ते और भी मजबूत बन सकें।

रीडर्स मेल

▸ पीएम ने जगाया भरोसा

16 अगस्त का संपादकीय 'सरकार की प्राथमिकता' पढ़ा। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीति की अन्य धाराओं से भिन्न मान्यता रखते हुए पार्टी के लक्ष्यों को प्राप्त करना किसी से छुपा नहीं है। चाहे अनुच्छेद 370 हो या मंदिर निर्माण, उन्होंने इन मुद्दों पर स्पष्ट रूप से कदम उठाए हैं। अब उनका एक और लक्ष्य कॉमन सिविल कोड है, जिसे लागू करना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। हालांकि उनके एजेंडे में स्पेस सेक्टर में शतक से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करना, मेडिकल सीटों में 75,000 सीटों का इजाफा करना और महिला अपराध रोकने जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। देखना यह है कि पीएम मोदी के प्रेरक और संतुलित भाषण धरातल पर कितना उतरते हैं।

माम चंद सागर, ई-मेल से

▸ नई सरकार से रिश्ते

यह पत्र 16 अगस्त के लेख 'क्या बांग्लादेश पर भारत से हुई कोई चूक' से संबंधित है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार केवल छात्र आंदोलन के कारण अचानक नहीं गिरी। बल्कि अंतरराष्ट्रीय साजिशों में बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख भी शामिल रहे। फिर भी यदि समय पर हमारा खुफिया तंत्र इसे भांप पाता, तो शायद स्थिति अलग होती। शेख हसीना भारत सरकार से सैन्य सहायता प्राप्त कर सकती थीं और साजिशें नाकाम हो जातीं। अब भारत को नई सरकार के साथ नए सिरे से सामंजस्य बैठाना होगा, और वह भी ऐसी सरकार के साथ जो पहले से ही चीन-पाकिस्तान के सहयोग से सत्ता में आई है। सैन्य सहयोग से बनी सरकार सेना के नियंत्रण में ही काम करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वर्तमान में भारत की सीमा से लगे छोटे देश एक अजीब संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके बीच भारत को अपनी सुरक्षा और सामर्थ्य को मजबूत बनाए रखना होगा।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

[illegible]